● वर्ष-2
● अंक-297
रायपुर, शुक्रवार
04 अगस्त 2023
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.
samacharpacheesa@gmail.com

।। संगछध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

ज्ञानवापी में आज से एएसआई का सर्वे

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया, मुस्लिम पक्ष को झटका

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के एएसआई का सर्वे को लेकर गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही ज्ञानवापी परिसर के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सर्वे को हरी झंडी दे दी है। अब आज से सर्वे शुरू होगा।

दरअसल, 21 जुलाई को वाराणसी जिला जज ने ज्ञानवापी के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) सर्वे का आदेश दिया था। इस पर मुस्लिम पक्ष ने पहले सुप्रीम कोर्ट फिर हाईकोर्ट में सर्वे के फैसले को चुनौती दी। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की इस याचिका को खारिज कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि न्यायहित में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का सर्वे जरूरी है। कुछ शर्तों के साथ इसे लागू करने की जरूरत है।

पिछले दिनों वाराणसी जिला जज एके विश्वेश ने मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वे कराने का आदेश जारी किया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को चार अगस्त तक सर्वे की रिपोर्ट वाराणसी कोर्ट को सौंपनी थी। जिला अदालत के आदेश के बाद एएसआई की टीम सोमवार को ज्ञानवापी परिसर का सर्वे करने पहुंची थी। लेकिन मुस्लिम पक्ष ने सर्वे का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने

एएसआई सर्वे पर दो दिन के लिए रोक लगाते हुए मस्जिद कमेटी को इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने के लिए कहा था। इसके बाद मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट पहुंचा। अब सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है।

कोर्ट में दलील देते हुए मुस्लिम पक्ष के वकील एसएफए नकवी ने असमायिक अदालती आदेश के जरिये ज्ञानवापी के वैज्ञानिक सर्वेक्षण से ज्ञानवापी के मूल ढांचे को नुकसान पहुंचनें की आशंका जताई थी। उन्होंने यह भी कहा था कि अयोध्या के बाबरी मामले का दंश देश ने झेला है। सिविल वाद में पोषणीयता का बिंदु तय किये बिना जल्दबाजी में सर्वेक्षण और खोदाई का फैसला घातक हो सकता है।

हालांकि एएसआई ने मुस्लिम पक्ष की दलील को सिरे से खारिज करते हुए कहा था कि सर्वेक्षण के लिए अपनाई जाने वाली तकनीक से ज्ञानवापी की मूल संरचना को खरोंच तक नहीं आयेगी। जबकि, हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन और सौरभ तिवारी का कहना था कि वैज्ञानिक सर्वेक्षण के जरिए वो ज्ञानवापी की सच्चाई सामने लाना चाहते है। सुनवाई के दौरान कोर्ट में मौजूद रहे प्रदेश के महाधिवक्ता अजय कुमार मिश्र ने कहा था कि याचिका में राज्य सरकार पक्षकार तो नहीं हैं, लेकिन सर्वेक्षण होने की दशा में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालने को राज्य सरकार तैयार है।

उधर, ज्ञानवापी मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में बुधवार को एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। इसमें श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की अनुमति दिए जाने की मांग की गई है। हालांकि, वाराणसी कोर्ट में इस मामले का पहले से वाद चल रहा है। एएसआई सर्वे पर चीफ जस्टिस की बेंच के फैसले के एक दिन पहले यह याचिका दायर की गई।

जनहित याचिका में ज्ञानवापी परिसर में मिले हिंदुओं के प्रतीक चिह्नों को संरक्षित किए जाने और गैर हिंदुओं के प्रवेश पर पाबंदी लगाए जाने की हाईकोर्ट से अपील की गई है। जनहित याचिका में कहा गया है कि श्रृंगार गौरी केस में जब तक वाराणसी की अदालत का फैसला नहीं आ जाता तब तक परिसर में गैर हिंदुओं का प्रवेश प्रतिबंधित किया जाए।

सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मुस्लिम पक्ष, सर्वे के फैसले को चुनौती; कैविएट भी दाखिल

नई दिल्ली। अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। शीर्ष कोर्ट में दाखिल याचिका में एएसआई को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने की अनुमति देने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है। मस्जिद कमेटी के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में मामले का जिक्र करते हुए कहा कि एएसआई को सर्वे की इजाजत न दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा कि वह इस मुद्दे पर गौर करेगा। सुप्रीम कोर्ट याचिका पर कल विचार करेगा।इससे पहले काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू याचिकाकर्ताओं में से एक ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में कैविएट अर्जी दायर की। इसमें मांग की गई है कि अगर मुस्लिम पक्ष एएसआई को मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण की अनुमति देने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका दायर करता है तो कोई भी आदेश पारित करने से पहले उसका पक्ष सुना जाए। दरअसल, एक वादी कैविएट आवेदन यह सुनिश्चित करने के लिए दायर करता है कि बिना उसका पक्ष सुने उसके खिलाफ कोई आदेश पारित न किया जाए। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के एएसआई का सर्वे को लेकर गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज कर दिया और ज्ञानवापी परिसर के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सर्वे को हरी झंडी दे दी।

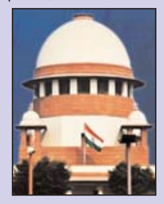

इन दिनों

✍ संतोष पाठक

मोदी ने किया नीतीश और बादल का जिक्र

एनडीए के विस्तार में जुटे भाजपा के अभियान के बाद जिन दो राजनीतिक दलों की एनडीए के पाले में वापसी को लेकर लगातार और बार-बार कयास लगाए जा रहे हैं, वह दोनों ही दल अभी तक इस बारे में कोई अंतिम फैसला शायद नहीं कर पा रहे हैं। स्वर्गीय प्रकाश सिंह बादल की पार्टी शिरोमणि अकाली दल जिसे उनके देहांत के बाद आजकल उनके बेटे सुखबीर सिंह बादल चला रहे हैं और दूसरा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड। यह दोनों ही राजनीतिक दल भाजपा के पुराने सहयोगी रहे हैं। भाजपा पंजाब और बिहार में इन दलों के साथ मिलकर लंबे समय तक सरकार चला चुकी है और यह दोनों ही राजनीतिक दल केंद्र की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार और नरेंद्र मोदी सरकार में भी शामिल रह चुके हैं लेकिन राजनीतिक परिस्थितियों की वजह से आज अकाली दल और जेडीयू, दोनों ही एनडीए से दूर हो चुके हैं। भाजपा का साथ छोड़ने के बाद नीतीश कुमार देशभर में 2024 लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को हराने के मंत्र के साथ विपक्षी दलों को एकजुट करने की मुहिम में लगे हुए हैं तो वहीं सुखबीर सिंह बादल एनडीए और विरोधी दलों के गठबंधन दोनों से अलग हटकर मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर पंजाब में अपने पुराने गौरवशाली दिनों को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा पहले ही कह चुके हैं कि भाजपा ने न तो किसी दल को एनडीए से जाने को कहा है और न ही आने को कहेगी, यह फैसला इन दोनों दलों के नेताओं को करना है कि वह फिर से भाजपा के साथ आना चाहते हैं या नहीं? हालांकि जेडीयू और अकाली दल लगातार भाजपा के साथ फिर से जाने की खबर पर इंकार करने का ही स्टैंड अपनाए हुए हैं लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं कमान संभालते हुए नीतीश कुमार और बादल परिवार दोनों को ही या यूं कहें कि जेडीयू और शिरोमणी अकाली दल को भाजपा के त्याग की याद दिलाते हुए कहा है कि एनडीए स्वार्थ नहीं त्याग की भावना से बना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को एनडीए सांसदों की कलस्टरों की बैठक में एनडीए को त्याग की भावना से बना गठबंधन बताते हुए यह कहा कि विधायकों की कम संख्या होने के बावजूद भाजपा ने नीतीश कुमार को बिहार में मुख्यमंत्री बनाया। उन्होंने बादल परिवार को भी भाजपा के त्याग की याद दिलाते हुए कहा कि पंजाब में अकाली-भाजपा गठबंधन सरकार में भाजपा विधायकों की अच्छी खासी संख्या होने के बावजूद भाजपा ने उपमुख्यमंत्री का पद नहीं मांगा।

बाघ संरक्षण में बड़ी उपलब्धि, लेकिन टला नहीं है खतरा

नईदिल्ली। बाघों की 2022 आबादी आकलन रिपोर्ट के अनुसार, उत्तराखंड 560 बाघों के साथ भारत में तीसरा सबसे अधिक बाघों वाला प्रदेश है, जो तुलनात्मक रूप से प्रदेश के छोटे भौगोलिक क्षेत्रफल को देखते हुए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। वर्ष 2018 की गणना में प्रदेश में बाघों की संख्या 442 थी। उत्तराखंड में बाघों के संरक्षण के लिए दो महत्वपूर्ण प्राकृतिक संरक्षित क्षेत्र, कॉर्बेट बाघ अभयारण्य और राजाजी बाघ अभयारण्य तराई आर्क भूभाग के पश्चिमी हिस्से में स्थित हैं।

उत्तराखंड में स्थित तराई आर्क भूभाग बाघ संरक्षण में सफल रहा है, लेकिन मानवीय हस्तक्षेप के कारण इस भूभाग में विगत वर्षों में हुए कई बदलावों के चलते महत्वपूर्ण बाघ आवासों के बीच जंगली जानवरों का परस्पर आवागमन खतरे में है। पिछले कुछ वर्षों में महत्वपूर्ण जंगलों को मानवजनित दबाव का सामना करना पड़ा है। कृषि क्षेत्रों का विस्तार, बढ़ती आबादी, शहरीकरण, उपजाऊ खेतों का मानव बस्तियों में बदलना, रेत खनन और बुनियादी ढांचा परियोजनाएं इस भूभाग के भीतर वन्यजीवों के निवास स्थान के नुकसान का कारण बनी हैं। कॉर्बेट बाघ अभयारण्य बाघों की महत्वपूर्ण आबादी (2022 के आकलन में 260 बाघ) के लिए जाना जाता है, जहां बाघों का आबादी-घनत्व उच्चतम है। जैव-विविधता से भरपूर कॉर्बेट में बाघों के अलावा 1,200 से अधिक हाथियों, चार प्रकार की हिरण प्रजातियों, भालू की दो प्रजातियों, अन्य वन्य जीव प्रजातियों सहित सैकड़ों पक्षी प्रजातियां भी पाई जाती हैं। बाघों के दीर्घकालिक अस्तित्व के लिए कॉर्बेट और अन्य वन प्रभागों के बीच जानवरों के आवगमन हेतु जंगलों का आपस में जुड़ा होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कॉर्बेट बाघों को पड़ोसी वन प्रभागों में फैलाने के लिए एक स्रोत के रूप में कार्य करता है।

उत्तराखंड में पश्चिमी तराई आर्क भूभाग के भीतर स्थित लगभग 1,150 वर्ग किलोमीटर में फैला राजाजी बाघ अभयारण्य दूसरा महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्र है। क्षमता के विपरीत यह अभयारण्य अभी तक विभिन्न कारणों से बाघ संरक्षण में उतना प्रभावी योगदान नहीं दे पाया है, क्योंकि महत्वपूर्ण वन्यजीव गलियारे अत्यधिक दबाव में आ गए हैं और मानवीय गतिविधियों, बुनियादी ढांचे के विकास और आसपास के परिदृश्य में तेजी से बदलाव के कारण जंगलों की निरंतरता में और अधिक विखंडन का खतरा है। कॉर्बेट से पश्चिमी राजाजी टीआर में बाघों को स्थानांतरित करने का सरकार का निर्णय वास्तव में बाघ संरक्षण प्रयासों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्तमान में केवल दो छोटे और खंडित गलियारे हैं, जो राजाजी और कॉर्बेट को जोड़ते हैं। एक गलियारा लैंसडाउन वन प्रभाग में शिवालिक पहाड़ियों से होकर गुजरता है।

रायपुर। राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन कोउनके जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रपति श्रीमती द्रोपदी मुर्मु, केन्द्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधानसभा अध्यक्ष श्री चरणदास महंत ने उनके स्वस्थ और सुदीर्घ जीवन के लिए शुभकामनाएं दी। साथ ही राज्यपाल के सचिव श्री अमृत खलखों, विधिक सलाहकार राजेश श्रीवास्तव, रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी सहित राजभवन सचिवालय के अधिकारी कर्मचारी, विश्वविद्यालयों के कुलपतियों एवं ब्रम्हकुमारी बहनें, परिजनों सहित गणमान्य नागरिकों ने भी रा'यपाल श्री हरिचंदन को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी।

प्रमुख समाचार

हिजबुल का संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार

लखनऊ। अफगानिस्तान जाकर आतंकी ट्रेनिंग हासिल करके देश में बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने के मंसूबे पालने वाले संदिग्ध आतंकी अहमद रजा को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है। एटीएस की सहारनपुर यूनिट की टीम ने बृहस्पतिवार को अहमद रजा उर्फ शाहरुख उर्फ मोहीउद्दीन से पूछताछ के बाद उसे गिरफ्त में ले लिया। उसके मोबाइल की गैलरी में हथियारों की फोटो, चैट के स्क्रीन शॉट व जिहादी वीडियो मिले हैं। इस बारे में पूछताछ में वह कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया और अपना गुनाह कबूल कर लिया। स्पेशल डीजी कानून-व्यवस्था एवं अपराध प्रशांत कुमार ने बताया कि एटीएस को केंद्रीय खुफिया एजेंसियों से सूचना मिली थी कि मुरादाबाद के मूढ़ा पांडे के ग्राम मिलक गुलड़िया निवासी अहमद रजा सोशल मीडिया के माध्यम से आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन व पाकिस्तान के आतंकी हैंडलर्स के लगातार संपर्क में है। वह पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान जाकर आतंकी कमांडो ट्रेनिंग लेकर, भारत में आतंकी घटना अंजाम देने का मंसूबा बना रहा है। उसके खिलाफ एटीएस थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है।

बरी करने के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट ने नोटिस जारी की

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भड़काऊ भाषण दिए जाने के मामले में पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खां को विशेष अदालत रामपुर द्वारा बरी करने के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार की अपील पर नोटिस जारी की है। साथ ही अधीनस्थ अदालत की पत्रावली तलब की है। अपील की अगली सुनवाई 27 सितंबर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने राज्य सरकार की अपील की सुनवाई करते हुए दिया है। मामले में वर्ष 2022 में आजम खां के खिलाफ केस दर्ज हुआ। पुलिस चार्जशीट पर न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने आजम खां को तीन साल कैद की सजा सुनाई थी। सजा के खिलाफ आजम खां ने रामपुर की विशेष अदालत (एमपीएमएलए) में अपील दाखिल की थी। एमपीएमएलए अदालत ने दाखिल अपील को स्वीकार करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा सुनाई गई सजा के फैसले को रद्द कर आजम खां को बरी कर दिया। यूपी सरकार ने एमपीएमएलए अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आजम खां को नोटिस जारी की है।

सीबीआई ने 216 सिविल सेवकों पर मामले किए दर्ज

नई दिल्ली। भारतीय सिविल सेवा को भारत सरकार और देश की प्रशासनिक मशीनरी की रीढ़ माना जाता है। सरकार में नाम तो नेताओं का होता है लेकिन योजनाओं के पीछे एक प्रशासनिक अधिकारी ही होता है। वहीं इन सिविल सेवकों पर कार्रवाई से जुड़े आंकड़े सरकार ने संसद में पेश किए। सरकार ने गुरुवार को राज्यसभा को सूचित किया कि केंद्रीय जांच ब्यूरो ने पांच साल से अधिक समय में 216 सिविल सेवकों के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं। 39 सिविल सेवक महाराष्ट्र, 22 जम्मू-कश्मीर, 21 दिल्ली, 17 उत्तर प्रदेश और 14 कर्नाटक के थे जिन पर मामले दर्ज किए गए हैं। एक लिखित उत्तर में केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले पांच वर्षों यानी 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 और 2023 के दौरान, सीबीआई ने 216 सिविल सेवा अधिकारियों के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं। मामलों का सामना कर रहे कुल सिविल सेवकों में से 12 बिहार से, 11 तमिलनाडु से, नौ-नौ गुजरात, हरियाणा और केरल से और आठ-आठ पंजाब, राजस्थान और तेलंगाना से थे।

आयात पर पाबंदी से बढ़ सकती हैं इलेक्ट्रॉनिक की कीमतें

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने गुरुवार को लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन पर्सनल कंप्यूटर और अल्ट्रा-स्मॉल कंप्यूटर और सर्वर के आयात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। भारत में बिक्री के लिए लैपटॉप और कंप्यूटर लाने की योजना बनाने वाली किसी भी इकाई या कंपनी को अब अपने इनबाउंड शिपमेंट के लिए सरकार से अनुमति या लाइसेंस लेना होगा। इस संबंध में डीजीएफटी द्वारा जारी की गई थी। एचएसएन 8741 कोड के अंतर्गत आने वाले अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर कंप्यूटर और सर्वर सहित इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की सात श्रेणियों के आयात पर भी पाबंदी लगाई गई है। सरकार के इस फैसले के बाद लैपटॉप और कंप्यूटर जैसे इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की कीमत में बढ़ोत्तरी हो सकती है। चलिए समझते हैं कि इस फैसले का उपभोक्ताओं पर क्या असर होगा? साथ ही भारत कौनसी कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आयात करता है, के बारे में भी जानेंगे। सरकार ने एचएसएन 8741के अंतर्गत आने वाले इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की सात श्रेणियों के आयात पर भी पाबंदी लगाई गई है। यानी यह नियम लेनोवो, एचपी, आसुस, एसर, सैमसंग जैसे अन्य पीसी निर्माताओं पर भी लागू होगा।

कोल इंडिया अपना नाम बदलकर रखा एनर्जी इंडिया

नईदिल्ली। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी और देश की सबसे पुरानी सरकारी खनन कंपनी कोल इंडिया अब अपना नाम बदलने जा रही है। कंपनी का नाम बदलने के पीछे मकसद ऊर्जा परिवर्तन की राष्ट्रीय योजना के अनुरूप खुद को ढालना और कारोबार बढ़ाना है। विश्वस्त सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, कोयला मंत्रालय और देश की पुरानी कंपनियों में शुमार कोल इंडिया कंपनी ने अब अपना नाम बदलने का फैसला कर लिया है। कंपनी ने नया नाम सीआईएल एनर्जी इंडिया रखने का फैसला किया है। नए नाम से कंपनी की भावी कारोबारी योजना की झलक मिलेगी, जो कोयला खनन के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी जाना चाहती है। मंत्रालय से जुड़े सूत्रों ने बताया कि, कोल इंडिया के रीब्रांडिंग और नाम बदलने पर फिलहाल विचार चल रहा है। कोल इंडिया का निदेशक मंडल जल्द ही इस पर कोई फैसला ले सकता है। कोल इंडिया भविष्य में अपना कारोबार दुर्लभ खनिजों के खनन, कोयले के गैसीकरण, कार्बन कैप्चर, हरित हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में फैलाना चाहती है। भविष्य में अन्य क्षेत्रों में कारोबार को देखते हुए यह जरूरी है कि कंपनी का नाम बदला जाए। क्योंकि कोल इंडिया के नाम से कंपनी केवल कोल के क्षेत्र में काम के लिए पहचानी जाती है।

अस्तित्व का संकट बनाम सत्ता और शक्ति का संघर्ष

अनुज अग्रवाल

दुनिया इन दिनों विचित्र त्रासदियों से गुजर रही है। कुछ जगह जो रास्ते, सभ्यता के ढाँचे (घर, दुकान, सड़क आदि आदि) उसने धरती की हरियाली को मिटाकर बनाए थे उसे बाढ़ और बारिश मिटाने पर तूली है तो कुछ जगह भीषण गर्मी उस हरियाली को ही जलाने पर उतारू है और दुनिया के अनेक देशों के जंगलों में लगी आग महीनों से बुझने का नाम ही नहीं ले रही। दशकों से सूख चुकी नदीयो में आयी बाढ़ आधी दुनिया में तबाही और भीषण जल प्रलय जैसे हालात पैदा कर चुकी है। मात्र पिछले चार पाँच वर्षों में ही धरती का तापमान .2 डिग्री बढ़ चुका है और जुलाई 23 पिछले एक लाख से भी अधिक वर्षों में धरती का सबसे गर्म वर्ष घोषित हो गया है। ग्लोबल वार्मिंग अब ग्लोबल बॉयलिंग में बदल चुकी हैं किंतु इस नष्ट होती सभ्यता और प्रकृति के बीच उबलती दुनिया के लोगों की बुद्धि ही कुंठित हो भ्रमित हो गयी है। अत्यधिक जनसंख्या, अधिकतम मानवीय गतिविधियों और जीवाश्म ईंधन के अतिशय प्रयोग ने हर व्यक्ति के सुख चैन और स्थिर जीवन की संभावनाओ को लीलना शुरू कर दिया है। विकास और जीडीपी की होड़ की सीमाए बाज़ार व लालची व्यवस्थाओं ने बेतरह तोड़ मरोड़ दी हैं और इस अनियंत्रित दोहन से प्रकृति व विकास का संतुलन बिगड़ चुका है। निर्धारित मानक यह है कि जितना प्रकृति का दोहन उतना पुनरुत्पादन किंतु व्यवहार में इसके ठीक उलट हो रहा है और इसी कारण जितनी जीडीपी देशों और दुनिया की प्रतिवर्ष बढ़ती है उससे ज़्यादा का नुक़सान ग्लोबल बॉयलिंग कर दे रही है। वैज्ञानिकों और पर्यावरणविदो का स्पष्ट आँकलन है कि यह नुक़सान हर दिन के साथ बढ़ता जाना है इसलिए सरकारों और कारपोरेट दोनों को अपनी नीति और मानसिकता बदलनी ही होगी किंतु उनकी जिद पूरी मानवीयता और प्रकृति को संपूर्ण विनाश

की और ले जा रही है । ऐसे में कहीं ऐसा न हो कि यह सदी मानव की अंतिम सदी न हो जाए।

इतनी विकट परिस्थितियों के बीच भी दुनिया रुस - अमेरिका (यूक्रेन) युद्ध से दो चार है और अमेरिका - नाटो देश व वर्ल्ड इकोनॉमिक फ़ोरम दुनिया में अपने वर्चस्व को बनाए रखने की हर संभव कोशिशों में है और दुनिया को चौथी औद्योगिक क्रांति की ओर धकेल रहा है। खाद्यान्न व चारे के उत्पादन में निरंतर होती कमी, घटते जंगल, जीव -जंतु और जलचर कैसे और कब तक आठ सौ करोड़ मानवों को ज़िंदा रख पाएँगे यह बड़ी चुनौती है। हर दिन बदलते मौसम ने कृषि व मौसम वैज्ञानिको के हर शोध, दावे व भविष्यवाणी को तोड़मरोड़ के रख दिया है और इस अनियंत्रित मौसम ने जीवन के अस्तित्व पर ही बड़े प्रश्नचिन्ह लगा दिए हैं।पिघलते ग्लेशियर और उबलते सागर इतनी वर्षा कर रहे हैं कि पृथ्वी जलप्रलय की ओर बढ़ चुकी है। भारत में हिमालय पर हो रहा विध्वंश इसका गवाह है। हर व्यक्ति इसे महसूस कर भी रहा है और विनाश निकट जान ईश्वर की आराधना व धार्मिक स्थलों के प्रति लोगों का रुझान बढ़ता जा रहा है । किंतु अंधी व्यवस्थाएँ और सरकारे जो अब बहुराष्ट्रीय कंपनियों की कठपुतली हो चुकी हैं अपना बाज़ारूपन नहीं छोड़ रही हैं। अंधाधुंध और अनियंत्रित विकास और जनता को भरमाने के लिए नित नए नाटक, उपद्रव, पंगे, ड्रामे और मीडिया स्टोरी व ब्रेकिंग न्यूज़।

देश में व दुनिया में हर क़ीमत पर व हर परिस्थितियों में लोकतंत्र के नाम पर चुनाव करवाए जा रहे हैं।अमेरिका और चीन - रुस दोनों गुट हर देश में अपने अपने पक्ष की सरकार बनाने के लिए हर संभव खेल खेल रहे है। अनेक देशों में आंतरिक संघर्ष, उथल पुथल, हिसा व संघर्ष इसी खेल का नतीजा हैं। भारत में भी मणिपुर तो ताज़ा संकट इसी कुटिल खेल का एक उदाहरण है। कई जगह पर पुरानी तो कहीं नई राजनीतिक पार्टी सरकार बना रही है। भारत में भी 26 बनाम 38 का इंडिया बनाम भारत (एनडीए) गढ़जोड़ आमने सामने है तो तीसरा मोर्चा तटस्थ दलों का है किंतु देश वि विश्व जिन चुनौतियों से जूझ रहा है उनसे मुक़ाबला करने की कोई दिशा, चिंतन व रणनीति किसी के पास नहीं और जो शिक्षा प्रणाली इसको सिखाना चाहती है उसे ही ख़ारिज किया जा रहा है।भारतीय संस्कृति व जीवन दर्शन हमेशा प्रकृति केंद्रित विकास की बात करता है किंतु जितनी इसकी चर्चा इन दिनों हो रही है उतना ही वास्तविक जीवन से यह ग़ायब होता जा रहा है। जनता की वास्तविक आवश्यकताओ, चुनौतियों, आशंकाओं व अपेक्षाओं से ये सभी दल दूर हैं। जन से दूर ये जनार्दन अहम, सत्ता व वर्चस्व के संघर्ष में इस कदर उलझ चुके हैं कि मानवता की वास्तविक चुनौती व समस्याओं को समझने व उनका निदान करने का माद्दा ही खो चुके हैं या फिर वे समझ चुके हैं कि धरती तो अब डूबता जहाज है और इसकी बीमारी इतनी अधिक बढ़ चुकी है कि इसका कोई इलाज ही नहीं बचा। ऐसे में लोगों को उलझाए रखो और फँसाए रखो। बाज़ार, उत्तेजना, मादक द्रव्य, पोर्न, धर्म, जाति, भाषा , नस्ल आदि के मुद्दे इसी सोच की उपज हैं। सत्तायें और राजनेताओ को इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता कि विकास के विकार अब मानव को लीलना प्रारंभ कर चुके हैं और अगर निर्णायक कदम नहीं उठाए गए तो अगले कुछ दशकों में भीषण जनहानि हो सकती है।

नक्सल प्रभावित चांदामेटा के नये मतदान केंद्र में पहली बार होगा मतदान : विजय दयाराम

बस्तर जिले में 8 नए मतदान केंद्र बनाए गए, कुल 576019 मतदाता करेंगे मतदान

■ **4 अक्टूबर 2023 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा**

जगदलपुर। विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारियों को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर विजय दयाराम ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि विधानसभा चुनाव के लिए बस्तर जिले में 08 नए मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जिले की 03 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 773 मतदान केंद्र थे, जो अब बढ़कर 781 हो जाएंगे। दरभा ब्लॉक के नक्सल प्रभावित चांदामेटा में पहली बार मतदान होगा। यहां कुल 327 मतदाता हैं जिनके लिए नया मतदान केंद्र बना दिया गया है, इसके अलावा बस्तर विधानसभा में 01, जगदलपुर विधानसभा में 02 और चित्रकोट विधानसभा में 05 नए मतदान केंद्र अस्तित्व में आ गए हैं।

उन्होने कहा कि जिले में नए मतदाताओं मैं अपना नाम जुड़वाने के प्रति रुझान नजर आया है, इससे पहले के पुनरीक्षण के बाद से आज दिनांक तक कुल 14569 नए मतदाता हो गए हैं जिनकी उम्र 18-19 वर्ष है। जबकि 05 जनवरी 2023 को पहले पुनरीक्षण के दौरान इस वर्ग

के मतदाताओं की संख्या 9294 थी। जिले में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। यहां कुल 576019 मतदाता है, जिनमें 298630 महिला और 277358 पुरुष मतदाता हैं। थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या 31 है, 08 नए मतदान केंद्र बनाए गए हैं, दरभा के चांदामेटा को छिंदगुर मतदान केंद्र से अलग कर दिया गया है। चांदामेटा के मतदाता अब तक 10 किमी दूर छिंदगुर तक जाकर मतदान करते थे लेकिन अब इन्हें यहां नहीं आना पड़ेगा।

कलेक्टर दयाराम ने बताया कि बस्तर विधानसभा में बोदरा से अलग कर सांवरापाल, जगदलपुर विधानसभा में चोकावाड़ा और चांदामेटा, चित्रकोट विधानसभा में गढिया, आंजर, सरगीगुडा, मादरकोंटा और पखनार नए मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया 31 अगस्त तक मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से लेकर उसमें सुधार से संबंधित दावा-आपत्ति किए जा सकते हैं। 12 और 13 अगस्त और 19 और 20 अगस्त को विशेष शिविर भी लगाए जाएंगे। इस दौरान प्राप्त दावा आपत्ति का निराकरण 22 सितंबर तक कर लिया जाएगा और 04 अक्टूबर 2023 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। दिव्यांग मतदाता प्रपत्र 08 के द्वारा पीडब्ल्यू मार्किंग के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन नाम दर्ज कराने के लिए भी आवेदन किया जा सकता है जिसकी आखिरी तारीख 31 अगस्त है।

अंबिकापुर ननि में मोबाइल टॉर्च की रोशनी में काम कर रहे सभापति और जनप्रतिनिधि

सरगुजा। अंबिकापुर नगर निगम में आलम ये है कि बिजली गुल हो जाने के बाद नगर निगम के सभापति व कैबिनेट मंत्री का दर्ज प्राप्त नेता अंधेरे में मोबाइल के टॉर्च में काम करने को मजबूर है। निगम में अधिकारियों के चेंबर में इनवर्टर की सुविधा उपलब्ध है। लेकिन नगर निगम के जन प्रतिनिधियों के चेम्बर में ना तो जनरेटर की सुविधा दी गई है, ना ही इनवर्टर की सुविधा है।

सभापति ने निगम अधिकारियों पर लगाया आरोप- इनवर्टर की सुविधा नहीं होने पर नगर निगम के सभापति सहित अन्य जनप्रतिनिधि विरोध करते हुए नजर आए। नगर निगम के सभापति ने कहा कि अधिकारियों की मनमानी की वजह से इस तरह की समस्या सामने आ रही है। जिसकी वजह से मोबाइल के टॉर्च में काम करने को मजबूर होना पड़ रहा है। ऐसे में जिम्मेदार अधिकारियों को संज्ञान लेने की जरूरत है।मामला मंगलवार का है, जब नगर निगम के सभापति और छत्तीसगढ़ शासन के बीस सूत्रीय क्रियान्वयन समिति के उपाध्यक्ष अजय अग्रवाल अपने चेम्बर में काम कर रहे थे। इसी दौरान बिजली चली गई। बिजली नहीं होने के कारण उनको मोबाइल का टॉर्च जलाकर काम करना पड़ रहा था। रोजाना इस तरह की दिक्कत से तंग आ चुके जनप्रतिनिधि भड़क उठे और अधिकारियों को हिदायत दी है।

अंबिकापुर नगर निगम में कांग्रेस की सरकार है। प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार है। आम तौर पर अपनी ही सत्ता में जनप्रतिनिधि विरोध जैसी बात से बचते हैं लेकिन सरकार में कैबिनेट मंत्री का दर्जा रखने वाले अजय अग्रवाल नाराज नजर आ रहे हैं। नगर निगम मे अधिकारियों ने अपने चेम्बर में इन्वर्टर की व्यवस्था की हुई है जबकि जनप्रतिनिधियों को यह व्यवस्था नहीं दी गई है।

विधायक ने जारी किया हितग्राही कार्ड, रजिस्ट्रेशन करने से मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ

बालोद। बालोद विधानसभा क्षेत्र की विधायक संगीता सिन्हा गुरुवार को %भूपेश है तो भरोसा है% हितग्राही कार्ड की शुरुआत की। इस दौरान वह हितग्राही कार्ड लेकर सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ बालों शहर के सड़कों पर उतरीं। उन्होंने छोटे-छोटे व्यवसायियों और आम जनता से चर्चा कर उन्हें हितग्राही काट दिया।

विधायक संगीता सिन्हा ने कहा कि इस कार्ड में रजिस्ट्रेशन करने से योजनाओं के लाभ मिलेंगे और यदि कोई योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है तो संगठन के माध्यम से उन्हें योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा। उन्होंने हाथों में हितग्राही पंजीकरण फार्म भी रखा हुआ था। उनके साथ जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चंद्रप्रभा सुधाकर, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चंद्रेश हिरवानी भी मौजूद रहे।

जिले में बीते 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, ऐसे में संचारी बालोद विधानसभा क्षेत्र की विधायक संगीता सिन्हा बरसते पानी में आम जनता के बीच पहुंचे। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी वर्गों के लिए अनेक अनेक जन हितकारी योजनाएं लागू की। सभी पात्र जनों के तक इन्हें पहुंचना उनकी प्राथमिकता है।

छत्तीसगढ़ सरकार राज्य के जन-जन का

जीवन बेहतर बनाने के लिए संकल्पित है। उन्होंने हितग्राही कार्ड के रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। उन्होंने कहा कि हितग्राही कार्ड में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आम जनता इस नंबर पर मिस कॉल देकर सीधे जुड़ सकते हैं।

ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चंद्रेश हिरवानी ने कहा कि सभी कार्यकर्ता हितग्राही पंजीकरण फार्म लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। जितनी भी जनहित योजनाएं छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू की हैं, उसका फीडबैक भी ले रहे हैं। आज से इस योजना की शुरुआत हुई है। चंद्रेश कुर्बानी ने कहा कि भूपेश बघेल के सरकार ने सभी किसानों का कर्ज माफ किया है। इसका लाभ उन्हें मिला है।

सरकार राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से प्रति एकड़ 9,000 एवं अन्य फसलों पर 10,000 रुपये की अदान सहायता दे रही है। बेरोजगारी भत्ता सहित दर्जन भर योजनाएं हैं, जिसका लाभ लोगों को मिला रहा है या नहीं, इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। यदि किसी को लाभ नहीं मिलता है तो उसे लाभ दिलाने के लिए संगठन पूरा प्रयास करेगी।

विधायक संगीता सिन्हा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में जब से कांग्रेस की सरकार बनी, तब से किसानों का कर्ज माफ हुआ है। भाजपा सरकार में किसान आत्महत्या के आंकड़े बढ़ते जा रहे थे। किसनों की समस्याओं को देखते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपना वादा निभाया और आज बघेल सरकार में आत्महत्या के आंकड़े शून्य हैं।

वहीं, जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष चंद्रप्रभा सुधाकर ने कहा कि किसान आदिवासी सभी के हित में सरकार ने काम किया है। पहले सात लघु वन उपज की खरीदी होती थी। वहीं, अब 65 लघु वनों पर ही खरीदी हो रही है। शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी व हिंदी स्कूलों में मुफ्त पढ़ाई हो रही है। बस्तर में 240 बंद स्कूल फिर से खुले हैं।

48 घंटे की बारिश बनी आफत, सड़कें पानी-पानी

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही। जिले में पिछले 48 घंटे से रुक रुककर हो रही बारिश से नदी-नाले उफान पर हैं। तो कुछ सड़कों पर पानी ऊपर आ गया है। जिससे लोगों को परेशान हो रही है। वहीं मौसम विभाग ने गौरेला पेण्ड्रा मरवाही जिले में मौसम का अलर्ट जारी किया है। अगले तीन दिनों तक रुक रुक कर बारिश होगी।

दरअसल, पिछले 48 घंटों से गौरेला पेण्ड्रा मरवाही जिले में रुक रुककर बारिश जारी बारिश से खेती किसानी के काम में तेजी आ गई है। जिससे किसानों के चेहरे खिल गए हैं, तो तापमान में भी गिरावट दर्ज की है। वहीं लगातार झमाझम बारिश से नदी नाले उफान पर हैं तो गौरेला के कोरजा गांव को जाने वाली सड़क पर स्थित नदी नाले में बारिश के पानी से उफान पर है।

पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, मलनिया बांध से पानी छोड़े जाने से खेतों में भी पानी भर गया है। पेण्ड्रा से भदौरा होते हुए खोडरी को जोडने वाली सड़क में स्थित छूइया नाला पुलिया के ऊपर से बारिश का पानी निकल रहा है। वहीं जोगिसार से कारिआम जाने वाली सड़क पर स्थित खराब है। पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। जिसके चलते इस सड़क पर आने जाने वाले लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अभी आने वाले दो दिनों तक इस क्षेत्र में बारिश जारी रहने की बात मौसम विभाग ने की है।

एसपी ने ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने वालों को लगाई फटकार

कवर्धा। प्रदेश और देश में चर्चित आईपीएस अधिकारी और कबीरधाम एसपी डॉ. अभिषेक पल्लव बुधवार देर शाम कवर्धा शहर में गश्त पर निकले। यातायात व्यवस्था और लोगों को नियम का पालन कराने के लिए गश्त पर निकले थे। इस दौरान उन्होंने यातायात नियम का पालन नहीं करने वालों को जमकर फटकार लगाई।

उन्होंने साथ ही कई लोगों का चालान भी काटा। उनकी इस कार्रवाई का वीडियो सोशल मीडिया जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल, वे जिले में दो माह पहले ही पदस्थ हुए हैं। इससे पहले वह पहले दुर्ग में एसपी थे। दुर्ग-भिलाई में भी उनकी कार्रवाई के वीडियो काफी वायरल होते रहते थे। साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोपियों की वन-टू-वन चर्चा भी चर्चित रही है।

कवर्धा में बुधवार को पहली बार ट्रैफिक व्यवस्था को देखने के लिए निकले हुए थे। इस दौरान वे शहर के सिग्नल चौक, मेन मार्केट, एकता चौक, पुराना बस स्टैंड, गुरु नानक गेट तक गए। मार्केट में चार पहिया वाहन लेकर पहुंचे चालकों को फटकार लगाई।

कबीरधाम जिले में बढ़ते सड़क हादसे पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। क्योंकि इस साल जनवरी से लेकर 31 जुलाई तक सड़क हादसों में 70 से अधिक लोगों की मौत हुई हैं। इसी प्रकार 150 से अधिक लोग घायल हुए हैं। सड़क हादसों में ज्यादातर मौत बाइक सवार की हुई हैं। अधिकतर मोटर साइकिल सवार हेलमेट नहीं पहनते हैं। इस कारण हादसे में सिर पर गंभीर चोट आती है और मौत हो जाती है। इन सब को देखते हुए पुलिस द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

एक बार फिर ईडी के निशाने पर कोरबा के व्यापारी

कोरबा। ईडी की टीम एक बार फिर छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में छापेमारी कर रही है। स्टेशन रोड निवासी नगर निगम कोरबा के पूर्व पार्षद और व्यवसायी शिव अग्रवाल के यहां सुबह 5ः00 बजे ही ईडी की टीम ने दस्तक दी। घर के लोग कुछ समझ पाते, तब तक टीम ने घर के सभी लोगों को एक कमरे में एकत्रित कर जांच कर दी। जांच के दौरान शिव अग्रवाल के यहां मिला तो कुछ नहीं, लेकिन उनका पूरा परिवार ईडी की छापेमारी से परेशान जरूर हो गया। लगभग 5 घंटे तक माथापच्ची करने के बाद ईटी की टीम खाली हाथ वापस लौट गई। दूसरी तरफ एक और टीम ने किराना गल्ला व्यवसायी रूड़मल अग्रवाल के घर और दुकान में छापेमारी की। टीम के साथ आए सशस्त्र बल के जवान घर के बाहर निगरानी करते देखे गए।

पहाड़ का हिस्सा टूटकर सड़क पर गिरा, आवागमन बंद

गौरेला पेंड्रा मरवाही। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में पिछले दो दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी है, जिसके कारण नदी-नाले उफान पर हैं। वहीं, लगातार हो रही बारिश से केवची अमरकंटक मार्ग पर पहाड़ का हिस्सा भी सड़क पर गिर गया है। पहाड़ का मलबा सड़क पर आ जाने से अमरकंटक मार्ग पर आवागमन बाधित है। करीब दो घंटे से इस मार्ग पर आवागमन बंद है। आने-जाने वाले लोग परेशान हो रहे हैं और जाम लगा हुआ है। लोग दूसरे वैकल्पिक मार्ग का उपयोग कर यात्रा पूरी कर रहे हैं। इसके साथ ही अमरकंटक मार्ग में सिद्ध बाबा के पास भी पहाड़ का मलबा सड़क पर आ गया है। जिले में हो रही लगातार बारिश के कारण लैंडस्लाइडिंग की भी घटना हुई हैं। गौरेला से ज्वालेश्वर और दुर्गाधारा के रास्तों से अमरकंटक जाने वाले मार्ग में भी कई स्थानों पर पहाड़ों से पत्थर और मलबा गिरकर सड़क पर आया है। इन रास्तों पर फिलहाल आवागमन जारी है। जिला प्रशासन ने इन रास्तों से आने-जाने वाले लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है।

बिलासपुर-नागपुर सेक्शन में आज से कुछ ट्रेनें रद्द

बिलासपुर। रेलवे ने विकास कार्य के बहाने एक बार फिर से आठ ट्रेनों को रद कर दिया है। दरअसल चार और पांच अगस्त को बिलासपुर-नागपुर सेक्शन में तीसरी लाइन में इलेक्ट्रानिक इंटरलाकिंग का काम होना है, इसके जिसके कारण ट्रेनों को रद किया गया है। यात्रियों को होने वाली असुविधा के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने के बजाए रेलवे ने खेद जताया है। रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि हावड़ा-मुंबई मेन लाइन पर स्थित बिलासपुर-नागपुर सेक्शन में तीसरी लाइन का काम चल रहा है। 4 अगस्त को रायपुर से चलने वाली 08707 रायपुर-दुर्ग मेमू पैसेंजर स्पेशल रद रहेगी। 4 अगस्त को दुर्ग से चलने वाली 08708 दुर्ग-रायपुर मेमू पैसेंजर स्पेशल रद रहेगी। 4 अगस्त को रायपुर से चलने वाली 08709 रायपुर-डोंगरगढ़ मेमू पैसेंजर स्पेशल रद रहेगी। 4 अगस्त को अंतागढ़ से चलने वाली 08815/08816 अंतागढ़-रायपुर-अंतागढ़ डेमू स्पेशल रायपुर एवं दुर्ग के बीच रद रहेगी। 5 अगस्त को डोंगरगढ़ से चलने वाली 08730 डोंगरगढ़- रायपुर मेमू पैसेंजर स्पेशल रद रहेगी।

13 अगस्त को होगी क्लर्क भर्ती परीक्षा

बेमेतरा। बेमेतरा जिला कोर्ट में क्लर्क भर्ती के लिए 13 अगस्त को परीक्षा होगी। इसे लेकर कोर्ट की वेबसाइट पर प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है। इस भर्ती परीक्षा में क्लर्क अंतर्गत शीघ्रलेखक (अंग्रेजी), शीघ्रलेखक (हिंदी), सहायक ग्रेड-3 (निष्पादन लिपिक, सेल अमीन आदेशिका लेखक, जूनियर नायब नाजिर साक्ष्य लेखक, सहायक सांख्यिकीय लिपिक, प्रतिलिपिकार) के पद शामिल हैं। कोर्ट द्वारा पात्र-अपात्र अभ्यर्थियों को सूची जारी की गई थी। इसके बाद 19 से 28 जुलाई दावा आपत्ति मंगाए गए थे। प्राप्त दावा आपत्ति का निराकरण के बाद अब परीक्षा होगी। यह परीक्षा सुबह 11 से 12 बजे तक होगी। इसके लिए बेमेतरा शहर के विभिन्न कॉलेज व स्कूल को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। लिखित परीक्षा में सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन के प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रवेश पत्र जिला न्यायालय बेमेतरा की अधिकारिक वेबसाइट districts.ecourts.gov.in/bemetara पर अपलोड की गई है। सभी पद के लिए एक ही प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जा रही है।

बिना लाइसेंस के चल रही थी खाद की दुकान, किया सील

बेमेतरा। बेमेतरा जिले के कृषि विभाग ने बिना लाइसेंस के चल रही खाद की दुकान पर छापेमारी की। विभाग ने संबंधित दुकान को सील कर दिया है। इस दुकान में कई अनियमितता भी पाई गईं हैं। कृषि विभाग के उपसंचालक मोरध्वज डड़सेना ने बताया कि बुधवार को कृषि केंद्र खंडसरा बेमेतरा द्वारा बिना लाइसेंस के खाद विक्रय करने संबंधी शिकायत प्राप्त हुई थी। मामले को संज्ञान में लेते हुए अनुविभागीय कृषि अधिकारी रिती तिवारी, उर्वरक निरीक्षक डॉ. श्याम लाल साहू ने बाबा कृषि केंद्र ग्राम खंडसरा का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि दुकान में बिना अनुमोदित प्रिंसिपल सर्टिफिकेट के कीटनाशकों का भंडारण किया गया है। साथ ही कीटनाशकों के मूल्य सूची का प्रदर्शन नहीं किया गया है और न ही नियमानुसार किसानों को बिल दिया जा रहा है। ये सब कीटनाशी अधिनियम 1968 तथा कीटनाशी नियम 1971 का उल्लंघन है। दुकानदार द्वारा बिना अनुज्ञप्ति पत्र (लाइसेंस) के उर्वरकों का भंडारण, विक्रय किया जा रहा था।

मेकाज में मनाया गया अंगदान महोत्सव दिवस

■ **एमबीबीएस के छात्र-छात्राओं ने लिया हिस्सा**

जगदलपुर। स्व. बलिराम कश्यप मेमोरियल शासकीय मेडिकल कॉलेज में गुरुवार को इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे मनाया गया। इसमें वर्ष 2022 के छात्र-छात्राओं को इस दिन के लिए पोस्टर बनाने की बात भी कही गई थी। बेस्ट तीन पोस्टर बनाने वाले ग्रुप को प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। इन पोस्टरों के निरीक्षण के लिए तीन निर्णायक भी रखे गए थे, जिनके द्वारा ग्रुप का सलेक्शन भी किया गया।

इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे के संबंध में एनाटोमी विभाग के एचओडी डॉक्टर बीथिका नेल कुमार ने बताया कि भारत सरकार के द्वारा आए आदेश के अनुसार आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में अंगदान महोत्सव एक से 31

जुलाई तक मनाया गया। वहीं, ती अगस्त को छत्तीसगढ़ के सभी मेडिकल कॉलेज से लेकर जिला अस्पताल में अंगदान महोत्सव को मानने की अपील की गई थी।

गुरुवार को मेकाज में वर्ष 2022 के एमबीबीएस के छात्र-छात्राओं को इस दिन को मानने के साथ ही ऑर्गन के महत्व के बारे में जानकारी के लिए एक पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इसमें 124 छात्र-छात्राओं को अलग-अलग ग्रुप में विभाजित किया गया। उन्हें पोस्टर बनाने के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। इन ग्रुपों ने करीब 32 पोस्टर भी तैयार किए। इन पोस्टरों में बेस्ट पोस्टर के चयन के लिए तीन निर्णायक भी रखे गए थे, जिसमें डॉक्टर छाया सोरी, डॉक्टर प्रदीप पांडेय एवम कमलेश ध्रुव मौजूद थे। उनके द्वारा पोस्टरों का निरीक्षण करने के साथ ही उन पोस्टरों में बने ऑब्जेक्टिव के संबध में छात्र-छात्राओं से जानकारी ली गई।

तीन अगस्त को क्यों मनाया जाता है इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे

जानकारी के अनुसार, 8 जुलाई 1994 को ह्यूमन ऑर्गन एक्ट बनाया गया था, जिसके बाद पहला दिल का ट्रांसफ्लांट 3 अगस्त को किया गया था। इसीलिए तीन अगस्त को इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे मनाया जाता है।

बता दें कि प्रति वर्ष 13 अगस्त को दुनियाभर में ऑर्गन डोनेशन डे मनाया जाता है। नेशनल हेल्थ पोर्टल के मुताबिक, भारत में हर साल 5 लाख लोगों की मौत समय पर ऑर्गन न मिलने की वजह से हो जाती है। इनमें से दो लाख ऐसे हैं, जिनकी मौत लिवर नहीं मिलने की वजह से होती है। एक इंसान अपने ऑर्गन डोनेट कर आठ लोगों को नया जीवन दे सकता है।

ऑर्गन डोनेशन की कब हुई शुरुआत

आधुनिक चिकित्सा ने एक शख्स से दूसरे शख्स में अंगों को प्रत्यारोपित करना संभव बना दिया है। पहली बार सफल अंग प्रत्यारोपण अमेरिका में 1954 में किया गया था। डॉक्टर जोसेफ मरे को फिजियोलॉजी और मेडिसिन में जुड़वा भाइयों रोनाल्ड और रिचर्ड हेरिक के बीच सफलतापूर्वक किडनी प्रत्यारोपण करने पर 1990 में नोबेल पुरस्कार मिला था।

सीएम ने बर्खास्त संविदा कर्मियों की बहाली का दिया आश्वासन

बीजापुर। 3 जुलाई से नियमितीकरण की मांग को लेकर एक महीने से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहे सर्व विभाग संविदा कर्मचारी महासंघ ने आंदोलन वापस ले लिया हैं। साथ ही सीएम के आश्वासन के बाद बीजापुर के 211 बर्खास्त संविदा कर्मचारी बीजापुर विधायक से मिलने के वाद प्रांतीय टीम के नेतृत्व में गुरुवार को ज्वाइनिंग किया।

बता दे कि एक महीने से चल रही संविदाकर्मियों की हड़ताल बुधवार को स्थगित कर दी गई हैं। संगठन के पदाधिकरियों ने बुधवार की रात सीएम भूपेश बघेल से मिलकर इसका ऐलान कर दिया हैं। साथ ही बीजापुर के 211 नेशनल हेल्थ मिशन के बर्खास्त कर्मियों के बहाली का आश्वासन भी सीएम ने दिए हैं। सीएम ने प्रांतीय टीम से बीजापुर विधायक से मिलने को कहा है। सम्भवतः गुरुवार को बर्खास्त कर्मियों की ज्वाइनिंग प्रांतीय टीम की मौजूदगी में हो जाएगी।

वर्ष 2018 में नियमितीकरण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे बीजापुर के 34 स्टाफ नर्स को बर्खास्त कर दिया गया था। वही वर्ष 2022 के मनरेगा आंदोलन के दौरान एपीओ की सेवा समाप्त की गई थी। जबकि वर्तमान में बीजापुर के 211 एनएचएम कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

दिल्ली में मोदी और राजनाथ सिंह से मिले सिद्धारमैया

नईदिल्ली। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने गुरुवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री से मुलाकात से कुछ घंटे पहले मुख्यमंत्री ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। सिद्धारमैया ने पीएम मोदी को लकड़ी से बनी पारंपरिक हाथी की लघु प्रतिमा और माला भेंट की। पीएमओ द्वारा ट्वीट की गई तस्वीर में पीएम मोदी कर्नाटक की पारंपरिक पगड़ी और शॉल पहने नजर आ रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से सिद्धारमैया की मुलाकात संसद भवन में हुई। मई में विधानसभा चुनाव में जीत के बाद राज्य में उनके नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री के साथ यह उनकी पहली मुलाकात थी। इससे पहले सीएम गुरुवार सुबह परिसदन पहुंचे। अपने डिप्टी डीके शिवकुमार के साथ ट्यूनिंग पर एक रिपोर्टर के सवाल का जवाब देते हुए सिद्धारमैया ने कहा, कर्नाटक में सब ठीक है...मेरे और शिवकुमार के बीच कोई मतभेद नहीं है, हम साथ हैं।

पीएम मोदी पर टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने किया कटाक्ष

नई दिल्ली। तृणमूल सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष किया और कहा कि वह अभी तक एक मिनट के लिए भी संसद नहीं आए हैं, लेकिन उनके मंत्रियों ने घोषणा की है कि वह संसद के मानसून सत्र के आखिरी दिन आएंगे। तृणमूल सांसद ने कहा, अब आपके कृपापात्र घोषणा करते हैं कि आप अंतिम दिन, 10 अगस्त को आने के लिए तैयार हो गए हैं। संसद में मणिपुर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की मांग को लेकर कांग्रेस पीएम मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई। प्रस्ताव पर अभी विचार नहीं हुआ है और इस पर 8 से 10 अगस्त के बीच चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 अगस्त को अविश्वास प्रस्ताव का जवाब दे सकते हैं, जो सत्र का आखिरी दिन भी है। अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस द्वारा लाया गया है लेकिन विपक्षी गठबंधन इंडिया (भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन) से संबंधित सभी विपक्षी दलों ने प्रस्ताव का समर्थन किया।

हेट स्पीच मामले में आजम की बढ़ सकती है मुश्किलें

लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हेट स्पीच के मामले में सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खां को एमपी-एमएलए कोर्ट रामपुर के द्वारा बरी करने के आदेश को स्टे कर दिया है। यह आदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की अपील को स्वीकार करते हुए दिया है। मामले की अगली सुनवाई 27 सितंबर को होगी। यह मुकदमा भाजपा विधायक आकाश सक्सेना की शिकायत पर दर्ज किया गया था। रामपुर जिले के थाना में दर्ज मुकदमे मे 27 अक्तूबर 2022 को पूर्व मंत्री आजम खां को तीन वर्ष का कारावास की सजा सुनाई गई थी। इस आदेश को आजम खान ने जिला न्यायालय एमपीएमएलओ कोर्ट में चुनौती दी थी। इस अपील में आदेश दिनांक 24 मई 2023 को आजम खान को दोषमुक्त कर दिया गया था। इस आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। जिसकी सुनवाई बृहस्पतिवार को न्यायमूर्ति राजवीर सिंह की अदालत में हुई।

जनता के समर्थन से एमवीए मजबूत और एकजुट : अंबादास

मुंबई। शिवसेना-उद्धव बालासाहेब ठाकरे (शिवसेना-यूबीटी) के नेता अंबादास दानवे ने कहा कि महा विकास अघाड़ी (एमवीए) मजबूत है और महाराष्ट्र की जनता ने इस गठबंधन को अपना समर्थन दिया है। विधान परिषद में विपक्ष के नेता दानवे ने कहा कि एमवीए नेता जल्द ही राज्य का दौरा शुरू करेंगे और बैठकें करेंगे। दानवे ने कहा कि शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) में टूट के बावजूद एमवीए मजबूत और एकजुट है। इस बैठक में शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे, कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण और बालासाहेब थोराट, राकांपा के जयंत पाटिल के साथ-साथ समाजवादी पार्टी के अबू आसिम आजमी और जनता दल (यूनाइटेड) के कपिल पाटिल जैसे कुछ प्रमुख नेता मौजूद थे। बैठक को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि 17 अगस्त के बाद एमवीए सहयोगी चुनाव की तैयारी के लिए संयुक्त रैलियों के साथ-साथ कार्यकर्ता सम्मेलन भी करेंगे।

महाराष्ट्र में कांग्रेस विधायक विजय वडेट्टीवार बने नेता विपक्ष

मुंबई। कांग्रेस विधायक विजय वडेट्टीवार, महाराष्ट्र विधानसभा के नए नेता विपक्ष नियुक्त किए गए हैं। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने विजय वडेट्टीवार के नाम का एलान किया। बता दें कि अजित पवार गुट के शिवसेना-भाजपा के साथ सरकार में शामिल होने के बाद से बीते एक महीने से नेता विपक्ष का पद खाली था। इससे पहले अजित पवार इस पद पर थे। अजित पवार ने 30 जून को इस पद से इस्तीफा दे दिया था और दो जुलाई को वह सरकार में शामिल हो गए थे। वडेट्टीवार के नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने के एलान के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार और विपक्ष के नेता अजट वडेट्टीवार को नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी तक लेकर गए। जब अजित पवार, अजय वडेट्टीवार को नेता प्रतिपक्ष के आसन तक लेकर जा रहे थे तो सदन में दोनों पक्ष की तरफ से जमकर ठहाके लगाए जा रहे थे। दरअसल कुछ समय पहले खुद इस पद पर थे और अब वह सरकार के साथ बैठे हैं।

नाराज लोकसभा अध्यक्ष को मनाने की कोशिश

बिरला हमारे संरक्षक, लोकसभा का संचालन करें : विपक्षी सांसद

नई दिल्ली। संसद के दोनों सदनों में मणिपुर को लेकर गतिरोध लगातार जारी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सांसदों के व्यवहार से नाराज हो गए। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए साफ तौर पर कह दिया कि जब तक सांसद सदन की गरिमा के अनुरूप व्यवहार नहीं करेंगे। वह सदन के भीतर नहीं आएंगे। इसके बाद उन्हें मनाने की कोशिश लगातार की जा रही है। इन सबके बीच खबर यह है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के नेतृत्व में विभिन्न दलों के सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की है और उनसे सदन में आने का अनुरोध किया है। विपक्षी सांसद अधीर रंजन चौधरी ने अपील की है कि लोकसभा सभापति ओम बिरला कार्यवाही का संचालन करें।

मणिपुर मुद्दे पर लोकसभा में बृहस्पतिवार को भी पिछले कुछ दिनों की तरह गतिरोध बरकरार रहा और विपक्षी दलों के सदस्यों के शोर-शराबे के कारण सदन की कार्यवाही शुरू होने के करीब 20 मिनट बाद अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इसके बाद अग्रवाल ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू कराया, विपक्षी दलों के सदस्य मणिपुर मुद्दे पर जल्द चर्चा कराने और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जवाब की मांग करते हुए हंगामा करने लगे। हाथों में तख्तियां लिए हुए कई विपक्षी सांसद आसन के निकट नारेबाजी करने लगे। हंगामे के बीच ही आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप पुरी और जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कुछ सदस्यों के पूरक प्रश्नों के उत्तर दिए। सदन में नारेबाजी लगातार जारी रहने पर पीठासीन सभापति अग्रवाल ने सदन की कार्यवाही 11 बजकर करीब 20 मिनट पर अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

अधीर रंजन चौधरी ने की अपील

गुरुवार को लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो सभापति के आसन पर ओम बिरला की जगह राजेंद्र

अग्रवाल बैठे। ओम बिरला के नहीं आने पर लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने विनती की कि सभापति ओम बिरला लोकसभा कार्यवाही का संचालन करें। चौधरी ने कहा कि वह हमारे संरक्षक हैं। इस पर आसन पर बैठे राजेंद्र अग्रवाल ने चौधरी से कहा कि वह उनका संदेश सभापति तक पहुंचा देंगे।

सांसदों ने की सभापति से मुलाकात

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी, एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले, एनके प्रेमचंद्रन, बसपा के रितेश पांडे, भाजपा के राजेंद्र अग्रवाल, टीएमसी सांसद सौगत राय, एनसीपी सांसद फारुख अब्दुल्ला और डीएमके सांसद कनिमोझी ने आज लोकसभा सभापति ओम बिरला से मुलाकात की। इस मुलाकात में सांसदों ने लोकसभा स्पीकर से सदन की कार्यवाही का संचालने करने की अपील की गई।

बता दें कि संसद के मानसून सत्र की शुरुआत से ही मणिपुर मुद्दे को लेकर हंगामा जारी है। विपक्ष जहां मणिपुर मुद्दे पर प्रधानमंत्री के संसद में बयान देने की मांग पर अड़ा है। वहीं सत्ता पक्ष मणिपुर के साथ ही राजस्थान, छत्तीसगढ़ में महिलाओं के खिलाफ हुए अपराध के मुद्दों पर चर्चा की मांग कर रहा है। इसके चलते हंगामा जारी है और कई विधेयक लंबित हैं। विपक्षी सांसद लोकसभा की कार्यवाही के दौरान सदन में नारेबाजी कर रहे हैं और

'45 साल से शादीशुदा हूं', खड़गे ने बताया नाराज तो धनखड़ ने दिया जवाब

नई दिल्ली। संसद के मानसून सत्र में हंगामा जारी रहा। राज्यसभा में एक बार फिर मणिपुर मामले को लेकर गहमागहमी दिखाई दी। विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा को घेरने में लगी हुई है। इस बीच

गुरुवार को राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे के बीच तीखी बहस हुई। वहीं, ठहाके भी लगते दिखे। दरअसल, खरगे ने कहा कि मणिपुर पर नियम 267 के तहत चर्चा होनी चाहिए। मैंने अपने नोटिस में 8 पॉइंट में ये बताया है कि नियम 267 के तहत चर्चा क्यों होनी चाहिए। हमारा सुझाव है कि आप हमें अपने चेंबर में बुलाइए और 1 बजे तक सदन को स्थगित कीजिए। इस मसले पर समाधान होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि कल मैंने आपसे अनुरोध किया था, लेकिन आप शायद नाराज थे। सभापति हंसे और उन्होंने कहा कि मैं 45 साल से अधिक समय से शादीशुदा आदमी हूँ। मैं कभी क्रोधित नहीं होता। उन्होंने इतना ही कहते ही सदन में ठहाके लगने शुरू हो गए। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस नेता पी.चिदंबरम का जिक्र किया और कहा कि चिदंबरम एक प्रख्यात वरिष्ठ वकील हैं। वह जानते हैं कि एक वरिष्ठ वकील के रूप में हमें गुस्सा करने का कोई अधिकार नहीं है, कम से कम प्राधिकार के समक्ष तथा आप (नेता प्रतिपक्ष खरगे) एक प्राधिकार हैं। मैं कभी गुस्सा नहीं करता। सभापति ने खरगे से कहा कि वह अपनी बात में सुधार कर लें। इस पर खरगे ने कहा कि आप इसे दिखाते नहीं हैं, लेकिन आप अंदर से गुस्से में हैं। खरगे की इस बात पर न केवल सभी सदस्य बल्कि सभापति धनखड़ भी खिलखिला कर हंसने लगे। बाद में खड़गे ने फिर अपनी बात रखनी शुरू की। कहा कि मैंने अपने नोटिस में 8 पॉइंट में ये बताया है कि नियम 267 के तहत चर्चा क्यों होनी चाहिए।

दिल्ली विधेयक पर बोले अमित शाह- आप का मकसद सेवा नहीं

गठबंधन नहीं दिल्ली के बारे में सोचे विपक्षी दल: अमित शाह

नईदिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को लोकसभा में दिल्ली सेवा विधेयक पर चर्चा करते हुए विपक्षी गुट इंडिया पर कटाक्ष किया और कहा, कांग्रेस को बताना चाहता हूं कि इस विधेयक के पारित होने के बाद वे (आप) आपके साथ कोई गठबंधन नहीं करने जा रहे हैं। उन्होंने विपक्षी सांसदों से गठबंधन के बारे में नहीं, बल्कि दिल्ली के बारे में सोचने की अपील की। इसके साथ ही विपक्षी गठबंधन पर हमला बोलते हुए अमित शाह ने कहा कि विपक्षी दलों के एक साथ आने के बावजूद 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री चुने जाएंगे।

शाह ने कहा कि मेरा सभी पक्ष से निवेदन है कि चुनाव जीतने के लिए किसी पक्ष का समर्थन या विरोध करना, ऐसी राजनीति नहीं करनी चाहिए। नया गठबंधन बनाने के अनेक प्रकार होते हैं। विधेयक और क़ानून देश की भलाई के लिए लाया जाता है इसलिए इसका विरोध और समर्थन दिल्ली की भलाई के लिए करना चाहिए। गौरतलब है कि पटना में विपक्षी दलों की पहली बैठक के बाद आप ने कहा था कि अगर सबसे पुरानी पार्टी ने केंद्र के फैसले का विरोध नहीं किया तो पार्टी के लिए किसी भी गठबंधन का हिस्सा बनना मुश्किल होगा, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने भी कहा था कि अगर कांग्रेस ने अध्यादेश मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट नहीं किया तो वे बेंगलुरु में विपक्षी दलों की दूसरी बैठक में शामिल नहीं होंगे। अंततः कांग्रेस ने घोषणा की कि वह दिल्ली सरकार का समर्थन करेगी और आप ने दो दिवसीय बैठक में भाग लिया और इंडिया ब्लॉक में शामिल हो गई।

लोकसभा में मंगलवार को दिल्ली सेवा विधेयक (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023) पेश किया गया था। इसको लेकर आज चर्चा हुई। लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट के आदेश को संदर्भित करता है जो कहता है कि संसद को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से संबंधित किसी भी मुद्दे पर कानून बनाने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि संविधान में ऐसे प्रावधान हैं जो केंद्र को दिल्ली के लिए कानून बनाने की अनुमति देते हैं। अमित शाह ने लोकसभा में दिल्ली अध्यादेश विधेयक, 2023 का समर्थन करते हुए कहा कि जवाहरलाल नेहरू से लेकर भीम राव अंबेडकर तक कई प्रमुख नेताओं ने पहले दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का विरोध किया था।

अमित शाह ने कहा कि साल 2015 में दिल्ली में एक ऐसी पार्टी सत्ता में आई जिसका मकसद सिर्फ लड़ना था, सेवा करना नहीं। उन्होंने कहा कि समस्या ट्रांसफर पोस्टिंग करने का अधिकार हासिल करना नहीं, बल्कि अपने बंगले बनाने जैसे भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए सतर्कता विभाग पर कब्ज़ा करना है। शाह ने कहा कि पहले दिल्ली में भाजपा और कांग्रेस और केंद्र में भी भाजपा और कांग्रेस की सरकार रही है लेकिन कभी झगड़ा नहीं हुआ। लोकसभा में कांग्रेस सांसद अधिर रंजन चौधरी ने कहा कि अगर दिल्ली में ऐसी छेड़खानी होती रहेगी तो आप अन्य राज्यों के लिए भी ऐसे बिल लाते रहेंगे। अगर आपको लगता है कि यहां घोटाला होता है तो उसके लिए आपको यह बिल लाना जरूरी था? आपके पास ईडी, सीबीआई, आईटी है, आप उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते?

खेल
प्रमुख समाचार

केएल राहुल का एशिया कप खेलना मुश्किल

नई दिल्ली। वनडे विश्व कप से पहले भारतीय खिलाड़ियों की चोट ने बीसीसीआई और फैंस की चिंता बढ़ा दी है। जसप्रीत बुमराह और प्रसिद्ध कृष्णा जैसे खिलाड़ी फिट हो चुके हैं और टीम इंडिया में वापसी भी कर चुके हैं, लेकिन ऋषभ पंत का इस साल मैदान में लौटना मुश्किल है। भारत के दो और अहम खिलाड़ी लोकेश राहुल और श्रेयस अय्यर की फिटनेस भी बीसीसीआई और टीम मैनेजमेंट के लिए चिंता का विषय बनी हुई है।

लोकेश राहुल विश्व कप से पहले फिट हो सकते हैं, लेकिन श्रेयस अय्यर का इस टूर्नामेंट से पहले पूरी तरह फिट होना मुश्किल है। बीसीसीआई से जुड़े एक सूत्र ने यह जानकारी दी है। सूत्र के अनुसार पूरी संभावना है कि सीनियर बल्लेबाज केएल राहुल श्रीलंका में होने वाले एशिया कप में नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि उन्हें अपनी हैमस्ट्रिंग चोट से उबरने में अधिक समय लगेगा, जबकि जहां तक विश्व कप में उनकी भागीदारी का सवाल है तो यह श्रेयस अय्यर के लिए भी मुश्किल हो सकता है।

राहुल ने जांघ की सर्जरी कराई थी जबकि अय्यर ने स्ट्रेस फ्रैक्चर को ठीक करने के लिए अपनी पीठ के निचले हिस्से की सर्जरी कराई थी। बीसीसीआई के आखिरी अपडेट में इन दोनों की वापसी की तारीख नहीं बताई गई। जहां तक खेल में वापसी की बात है तो इन्हें धीरे-धीरे अपने कार्यभार में बढ़ोतरी करते देखा गया।

बीसीसीआई के एक सूत्र ने बताया श्रीलंका में होने वाले एशिया कप में लोकेश राहुल और श्रेयस अय्यर के खेलने की संभावना नहीं है। ये दोनों श्रीलंका के हालातों में मैच खेलने के लिए पूरी तरह फिट नहीं हो पाएंगे। बीसीसीआई की मेडिकल टीम को लगता है कि राहुल कम से कम विश्व कप से पहले होने वाली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए फिट हो सकते हैं।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 542 अंक लुढ़का निफ्टी 19,400 के नीचे

नईदिल्ली। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग के अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग घटाने के बाद निवेशक कम उत्साहित नजर आए। वैश्विक बाजारों में कमजोर रुख और विदेशी कोषों की निकासी के बीच गुरुवार को लगातार दूसरे कारोबारी सत्र में घरेलू शेयर बाजार में जोरदार गिरावट दर्ज की गई। बीएसई सेंसेक्स 542 से ज्यादा अंक की गिरावट लेकर बंद हुआ। निफ्टी में भी 145 अंकों की भारी गिरावट दर्ज की गई। बीएसई का 30 शेयरों वाला मानक सूचकांक सेंसेक्स 542.10 अंक यानी 0.82 फीसदी की भारी गिरावट के साथ 65,240.68 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 65,820.82 की ऊंचाई तक गया और नीचे में 64,963.08 तक आया। वहीं, दूसरी तरफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में भी 144.90 अंक यानी 0.74 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई। निफ्टी दिन के अंत में 19,381.65 अंक पर बंद हुआ।

सरकार ने लैपटॉप, टैबलेट पर्सनल कंप्यूटर और सर्वर के आयात पर लगाया प्रतिबंध

नईदिल्ली। लोकल मैन्यूफेक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन पर्सनल कंप्यूटर, अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर कंप्यूटर और सर्वर के आयात को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया है। किसी उत्पाद के आयात पर प्रतिबंध लगाने का मतलब है कि उनके आयात के लिए लाइसेंस या सरकार की अनुमति अनिवार्य होगी। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने गुरुवार को जारी अधिसूचना में कहा कि शोध एवं विकास, परीक्षण, बेंचमार्किंग और मूल्यांकन, मरम्मत और वापसी तथा उत्पाद विकास के उद्देश्य से प्रति खेप अब 20 वस्तुओं तक आयात लाइसेंस की छूट रहेगी। अधिसूचना में कहा गया है, 'लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन पर्सनल कंप्यूटर और सर्वर के आयात को तत्काल प्रभाव से 'अंकुश' की श्रेणी में डाल दिया गया है।'

सर्विस सेक्टर में जुलाई में 13 साल के हाई पर पहुंचा पीएमआई

नईदिल्ली। एसएंडपी ग्लोबल ने 3 अगस्त को सर्विस पीएमआई के आंकड़े जारी किए हैं। आंकड़ों के मुताबिक जुलाई में सर्विसेज पीएमआई में जोरदार बढ़त देखने को मिली है। ये जून के 58.5 से बढ़कर 62.3 के स्तर पर आ गई है। जुलाई महीने में सर्विसेज पीएमआई 13 साल के हाई लेवल पर पहुंच गई है। जुलाई में कंपोजिट पीएमआई भी 59.4 से बढ़कर 61.9 के स्तर पर आ गई है। इसके अलावा जुलाई में सर्विसेज पीएमआई लगातार 24वें महीने 50 के अहम स्तर से भी ऊपर रही है। इसका मतलब ये है कि लगातार 24 महीनों में देश में सर्विसेज सेक्टर की गतिविधियों में विस्तार देखने को मिला है। बता दें, पीएमआई आंकड़ा 50 के ऊपर होता है तो यह माना जाता है कि कारोबारी गतिविधियों में ग्रोथ हुई है। वहीं अगर ये आंकड़ा 50 के नीचे रहता है तो यह माना जाता है कि कारोबारी गतिविधियों में संकुचन आया है।

सांघीपुरम पोर्ट का विस्तार करेगा अदाणी ग्रुप

नईदिल्ली। अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकनॉमिक जोन के मुख्य कार्यपालक अधिकारी करण अडाणी ने कहा है कि अदाणी समूह की सांघीपुरम के निजी (कैप्टिव) बंदरगाह की क्षमता बढ़ाने पर निवेश करने की योजना है। इससे इस बंदरगाह पर 8,000 डीडब्ल्यूटी (डेडवेट टन भार) के जहाज आ सकेंगे। अदाणी ग्रुप की कंपनी अंबुजा सीमेंट्स लि. (एसीएल) ने गुरुवार को पश्चिम भारत की प्रमुख सीमेंट विनिर्माता सांघी इंडस्ट्रीज लि. (एसआईएल) का 5,000 करोड़ रुपये के उपक्रम मूल्य पर अधिग्रहण करने की घोषणा की है। अंबुजा सीमेंट द्वारा सांघी इंडस्ट्रीज लि. (एसआईएल) के मौजूदा प्रवर्तकोंज्वि सांघी और परिवार से कंपनी की 56.74 प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया जाएगा। इससे अंबुजा सीमेंट को अपनी क्षमता को बढ़ाकर 7.36 करोड़ टन सालाना करने में मदद मिलेगी।

यह 2013 का भारत नहीं, तीसरे मुकाम तक पहुंचने करने होंगे ठोस काम

अजय बग्गा

वर्ष 2014 में भारत को दुनिया की दसवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर गिना जाता था। लेकिन 2022 में भारत ने छलांग लगाते हुए दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा हासिल कर लिया। फिलहाल भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था (मौजूदा अमेरिकी डॉलर की कीमतों पर नॉमिनल जीडीपी के मामले में) बना हुआ है। इस वक्त भारत सिर्फ अमेरिका (255 खरब अमेरिकी डॉलर), चीन (181 खरब अमेरिकी डॉलर), जापान (42 खरब अमेरिकी डॉलर) और जर्मनी (41 खरब अमेरिकी डॉलर) से पीछे है।

अनुमान लगाए जा रहे हैं कि 2027 से 2030 के बीच भारत पचास खरब डॉलर से ज्यादा के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के साथ, जापान को पछाड़ते हुए दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इसके बारे में बात की। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा, हमारे ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए कहा जा सकता है कि हमारी सरकार के तीसरे कार्यकाल में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। यह मोदी की गारंटी है।

भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जारी अनुमानों के अनुसार भी वर्ष 2027 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के जुलाई, 2023 के वैश्विक आर्थिक पूर्वानुमान के अनुसार, वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर 2022 के 3.5 फीसदी से घटकर 2023 और 2024 दोनों में तीन फीसदी रहने का अनुमान है। भारत में वृद्धि दर 2023 में 6.1 फीसदी (5.9 फीसदी पूर्व अनुमान), जबकि 2024 में 6.3 फीसदी रहने की उम्मीद है।

यह स्थिति दरअसल भारतीय अर्थव्यवस्था में किए गए महत्वपूर्ण सुधारों की देन है। इनमें वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी), दिवाला और दिवालियापन संहिता, कॉरपोरेट करों की दर में उल्लेखनीय कमी, मेक इन इंडिया और स्टार्ट-अप इंडिया जैसी रणनीतियां और उत्पादन को प्रोत्साहन देने वाली कई योजनाएं शामिल हैं। इन सबकी बदौलत, भारत दुनिया की सबसे तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था बना हुआ है। वित्त वर्ष 2024 के केंद्रीय बजट में अर्थव्यवस्था की ऊंची वृद्धि को बरकरार रखने के लिए कुछ और कदम भी उठाए गए हैं। पूंजी निवेश परिव्यय में लगातार तीसरे वर्ष उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जो रिकॉर्ड 10 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। यह सकल घरेलू उत्पाद का 3.3 फीसदी है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर अपनी एक हालिया रिपोर्ट में कहा है कि इस दशक के अंत से पहले भारत की जीडीपी दोगुनी होकर साठ खरब अमेरिकी डॉलर होने की पूरी उम्मीद है। इससे यह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। वर्ष 2030 में भारत की जीडीपी के 35 खरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर पचास खरब अमेरिकी डॉलर होते ही, भारतीयों की प्रति व्यक्ति आय 2,500 अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष से बढ़कर 4,000 अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष हो जाएगी। इसके साथ ही, घरेलू उपभोग व्यय 21 खरब अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष से बढ़कर 34 खरब अमेरिकी डॉलर प्रतिवर्ष हो जाएगा। कुल मिलाकर, 2030 तक भारतीय घरेलू उपभोग व्यय का आकार 30 से 34 खरब अमेरिकी डॉलर के बीच होगा, जो आज भारत की कुल जीडीपी के लगभग बराबर है। प्रतिष्ठित निवेश बैंकिंग कंपनी मॉर्गन स्टेनले का भारत की स्थिति में हो रहे इस बदलाव पर कहना है, अब यह 2013 वाला भारत नहीं रह गया है। सिर्फ दस साल के भीतर भारत ने वैश्विक व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान पा लिया है। मॉर्गन स्टेनले ने उन दस वजहों को गिनाया है, जिनकी बदौलत यह बदलाव आया है। इनमें शामिल हैं- आपूर्ति में सुधार, अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाना, रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, सामाजिक हस्तांतरणों को डिजिटल बनाने पर जोर, दिवाला और दिवालियापन संहिता, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण, एफडीआई पर ध्यान, भारत के खुदरा म्यूचुअल फंड और पेंशन फंड प्रवाह, सरकारी सहायता और बहुराष्ट्रीय कंपनियों का भारत के प्रति झुकाव। इन कोशिशों के निहितार्थ समझने की जरूरत है।

राजनीति का अखाड़ा नहीं है संसद

राज कुमार सिंह

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और संसद लोकतंत्र का सर्वोच्च मंदिर, पर लगता है उसकी गरिमा और महत्ता का ध्यान उन्हें ही नहीं रह गया है जो उसके माननीय सदस्य हैं। विपक्ष के हंगामे या अनुपस्थिति के बीच कुछ विधेयक पारित करने के अलावा मानसून सत्र में अभी तक कोई महत्वपूर्ण चर्चा नहीं हो सकी है। पर ऐसा क्यों हो रहा है, इसका जवाब इतना सरल नहीं है। संसदीय लोकतंत्र में दो ही पक्ष होते हैं- सत्ता पक्ष और विपक्ष। संसद के संचालन में दोनों की भूमिका होती है। मगर, जब भी संसदीय गतिरोध पर सवाल उठते हैं, दोनों ही एक-दूसरे पर उंगलियां उठाने लगते हैं। ग्रीष्मकाल से वर्षा ऋतु आ गयी, लेकिन मणिपुर जातीय हिंसा की आग में अभी भी जल रहा है। वहां आग तो तीन मई को ही भड़की थी, मगर तब सत्तापक्ष और विपक्ष कर्नाटक की चुनावी जंग में व्यस्त थे। फिर, संसद के पिछले बजट सत्र में उनके तरकश में और भी राजनीतिक तीर थे। और ऐसे में, ढाई महीने बाद मणिपुर पर हंगामा तब हो रहा है जब उसकी तपिश अंतरराष्ट्रीय मीडिया से लेकर दूसरे देशों की संसद तक में भारत की छवि को झुलसा चुकी है। अभी, दोनों ही पक्षों को इसी साल होने वाले पांच राज्यों के विधानसभा और अगले साल के आम चुनाव के लिए एक-दूसरे को कटघरे में खड़ा करने का यह अनुकूल अवसर लगता है। इसलिए, विपक्ष मणिपुर हिंसा पर नियम 267 के तहत चर्चा और प्रधानमंत्री के बयान के लिए अड़ा रहा, जबकि सत्ता पक्ष नियम 176 के तहत चर्चा और गृह मंत्री अमित शाह के जवाब के लिए ही तैयार था। दोनों ही पक्षों के अपने-अपने तर्क हो सकते हैं, पर जब एक राज्य हिंसा की आग में जल रहा है, महिलाओं के साथ अत्याचार का वीडियो वायरल हो कर सारी दुनिया को शर्मसार कर चुका है, तब संसद में चर्चा को नियम के विवाद में उलझा कर हमारे सांसद क्या संदेश देना चाहते थे? अगर संसद एक सीमावर्ती राज्य के ऐसे संवेदनशील हालात पर भी चर्चा नहीं करती और बजट समेत तमाम महत्वपूर्ण विधेयक बिना चर्चा ही पारित कर दिये जाते हैं, तब जनमानस में देर-सवेर यह स्वाभाविक सवाल उठ सकता है कि यह संसद किसकी खातिर है? अब विपक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव के मास्टर स्ट्रोक के बाद संसद में चर्चा होगी और प्रधानमंत्री को जवाब देना पड़ेगा। तो फिर संसदीय गतिरोध से क्या हासिल हुआ? मानसून सत्र में मणिपुर पर संसद के इस मौन से भी बड़े और प्रासंगिक सवाल उसके कामकाज को लेकर उठने लगे हैं। संसदीय कार्यवाही में व्यवधान की बीमारी बहुत पहले 1963 में ही दिखाई पड़ गयी थी, लेकिन उसके निदान के प्रति गंभीरता के बजाय राजनीतिक इस्तेमाल की प्रवृत्ति का परिणाम है कि अब वह नासूर बनती नजर आ रही है। अपवाद छोड़ दें तो गठबंधन राजनीति के सहारे कमोबेश सभी दल सत्ता में रह चुके हैं, पर अपनी भूमिकाएं बदलने पर वे वैसा ही आचरण करने लगते हैं, जिसे कभी अलोकतांत्रिक बताते रहे। आम मान्यता है कि सदन चलाना सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है, पर इसका अर्थ यह नहीं कि विपक्ष की भूमिका व्यवधान पैदा करने की ही होगी। मतदाताओं ने सदन चलाने की जिम्मेदारी दोनों को सौंपी है। लंबा संसदीय गतिरोध पहली बार राजीव गांधी के प्रधानमंत्री रहने के समय संभवत: 1988 में पैदा हुआ था, जब बोफोर्स समेत रक्षा सौदों में दलाली का आरोप लगाते हुए विपक्ष ने जेपीसी की मांग पर संसद नहीं चलने दी। दूसरा बड़ा मौका पीवी नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्रित्व काल में शेयर घोटाले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति के गठन की मांग की वजह से आया। तब विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने मुझसे एक साक्षात्कार में कहा था कि सरकार राजहठ का परिचय दे रही है, जो उसे शोभा नहीं देता। वाजपेयी के ही नेतृत्व में भाजपा का राजयोग शुरू हुआ। पर क्या वही राजहठ उत्तरोत्तर सत्ता पक्ष का चरित्र नहीं बन गया है? संसदीय राजनीति के प्रखर चेहरे अरुण जेटली और सुषमा स्वराज ने संसदीय गतिरोध को भी विपक्ष की संसदीय रणनीति का सर्वथा उचित हथियार बताया था। आम धारणा है कि विपक्ष ही संसद में हंगामा करता है पर पिछले कुछ दशकों में सत्ता पक्ष ने भी अपनी सुविधानुसार संसद ठप्प करने में संकोच नहीं किया है। आज यह एक बड़ा और प्रासंगिक सवाल है कि संसद की लगातार बिगड़ती छवि को कैसे सुधारा जाए। संसदीय कार्यवाही पर नजर रखने वालों का आकलन है कि वर्तमान 17वीं लोकसभा कामकाजी बैठकों की संख्या की दृष्टि से 1952 के बाद सबसे काम करने वाली लोकसभा बन सकती है।

मोदी के विकास रोडमैप से घबराया विपक्ष

मृत्युंजय दीक्षित

विगत दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात की एक सफल यात्रा की। कुछ समय से प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं से एक परिवर्तन देखा जा रहा है अब उनकी विदेश यात्राएं समय की दृष्टि से छोटी हो रही हैं किंतु अब वे एक साथ कई देशों की यात्रा पर जा रहे हैं। उदाहरण के लिए, प्रधानमंत्री ने अमेरिका यात्रा के साथ मिस्र की यात्रा की और फ्रांस के साथ संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा की।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फ्रांस की राजधानी पेरिस में भव्य स्वागत हुआ और उनको फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ आनर से भी सम्मानित किया गया जबकि संयुक्त अरब अमीरात में प्रधानमंत्री मोदी को वहां के राष्ट्रपति ने हाथ में फ्रैंडशिप बैंड बांधकर सम्मान करते हुए भारत और यूएई के मध्य संबंधों के प्रगाढ़ होने का संकेत भी दिया।

प्रधानमंत्री की फ्रांस यात्रा

प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी की यह पांचवीं फ्रांस यात्रा थी। इस बार प्रधानमंत्री फ्रांस की नेशनल परेड के मुख्य अतिथि भी रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कई महत्वपूर्ण बातें कहीं जिनका प्रभाव काफी दूर तक जा रहा है। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में जी-20 की अध्यक्षता व भारत में आयोजित हो रही बैठकों का उल्लेख किया और चंद्रयान-3 की भी चर्चा। उन्होंने एक रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए बताया कि भारत ने करीब 42 करोड़ देशवासियों को गरीबी की रेखा से बाहर निकाला है। उन्होंने कहा कि भारत अगले 25 वर्षों में विकसित देश होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। आज हर अंतरराष्ट्रीय एजेंसी कह रही है कि भारत आगे बढ़ रहा है। अब भारत में निवेश का अवसर है। उन्होंने भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि अब फ्रांस में तमिल कवि और संत तिरुवल्लुवर की की प्रतिमा लगेगी। उनकी लिखी पुस्तक तिरुक्कुरल दुनियाभर में लोकप्रिय है और उसका कई भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। इस माध्यम से उन्होंने तमिलनाडु की जनता को भी संदेश दिया है। इसके पहले प्रधानमंत्री ने अमेरिका में भी तमिल साहित्य और भाषा की लोकप्रियता और विशेषता बताकर तमिलनाडु की जनता का दिल जीतने का प्रयास किया है।

भारत सरकार ने फ्रांस सरकार की सहायता से मार्सिले में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलने का निर्णय लिया है। वहां पर अध्ययन करने वाले छात्रों को अब पांच वर्ष का अध्ययन वीजा दिये जाने की घोषणा भी की गई है।

भारत और फ्रांस के मध्य अब यूपीआई के माध्यम से डिजिटल पेमेंट की भी व्यवस्था प्रारम्भ हो रही है। भारत और फ्रांस के पारस्परिक सम्बन्ध 300 वर्षों से लगातार चले आ रहे हैं और समय के साथ प्रगाढ़ हो रहे हैं। जब अटलजी की सरकार के समय भारत ने परमाणु परीक्षण किये थे, उस समय फ्रांस ही एकमात्र ऐसा देश था जिसने भारत पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया था और भारत के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहा था। फ्रांस संयुक्त राष्ट्र महासभा सहित सभी अंतरर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के साथ सदा खड़ा दिखाई देता है।

वर्तमान समय में भारत-फ्रांस के मध्य रक्षा सम्बंध भी लगातार प्रगाढ़ हो रहे हैं। फ्रांस मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत में महत्वपूर्ण भागीदार बन रहा हैं। भारत और फ्रांस सौर ऊर्जा और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भी फ्रांस भारत के साथ खुलकर खड़ा है। भारत और फ्रांस के मध्य 26 लड़ाकू राफेल-एम लड़ाकू विमान खरीदने सहित नौसेन के लिए 3 स्कार्पीन क्लास सबमरीन खरीद का ऐतिहासिक समझौता हुआ है जिससे भारतीय सेना की ताकत बढ़ेगी। आज भारत और फ्रांस के मध्य जो रक्षा समझौते हो रहे हैं उससे भारत के शत्रु राष्ट्रों में बेचैनी है।

संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की यात्रा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात की भी एक दिवसीय यात्रा की। इस छोटी यात्रा के बड़े राजनैतिक निहितार्थ थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूएई में भी भव्य स्वागत हुआ। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद नाहयान की वार्ता के बाद जारी किये गये संयुक्त बयान के अनुसार दोनों देश क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सभी रूपों में सीमा पार आतंकवाद सहित उग्रवाद और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अपने द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने पर सहमत हो गये हैं। दोनों देशों के रक्षा आदान-प्रदान, अनुभवों को साझा करने, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण को बढ़ाने पर भी सहमति जताई गयी है। सभी प्रकार के उग्रवाद, घृणास्पद भाषण और भेदभाव को त्यागने की आवश्यकता पर बल दिया गया।

भारत और यूएई के मध्य भी कई समझौते हुए हैं जिसमें दोनों देश भारतीय और यूएई की मुद्राओं क्रमश: रुपए और दिरहम में व्यापार करेंगे। इससे भुगतान में कम समय लगेगा और मुद्रा बाजार में रुपये-दिरहम में निवेश करने का विकल्प भी खुलेगा। पर्यटन भी सुविधाजनक होगा। दोनों देशों के बीच डिजिटल भुगतान मैसेजिंग सिस्टम यानी भारत के यूपीआई और यूएई के भुगतान प्लेटफार्म आईपीपी को आपस में जोड़ा जायेगा। इससे दोनों देशों की जनता को एक-दूसरे देश में कार्ड लेन-देन पर कोई अतिरिक्त चार्ज भी नहीं लगेगा। आइआइटी दिल्ली अबू धाबी (यूएई) में अपना पहला कैंपस खोलेगा। यह मीना क्षेत्र अर्थात मध्य यूएई में भारत का पहला कैंपस होगा।

यूएई में इसी वर्ष जलवायु परिवर्तन पर कॉप-28 सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसकी सफलता के लिए पूर्ण सहयोग देने का वादा किया है। यूएई भारत के लिए काफी अहम मित्र राष्ट्र है क्योंकि यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारत और यूएई के मध्य 84 अरब डालर से अधिक का द्विपक्षीय व्यापार प्रगति पर है। यहां प्रवासी भारतीय समुदाय सबसे बड़ा जातीय समुदाय है और कुल आबादी में उसकी तकरीबन 30 प्रतिशत हिस्सेदारी है। 2021 में यहां प्रवासी भारतीयों की संख्या लगभग 30 लाख थी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस में जहां दुनिया का सबसे बड़ा एफिल टॉवर देखने गये वहीं दूसरी ओर यूएई स्थित बुर्ज खलीफा उनके स्वागत में भारतीय तिरंगे से रोशन हुआ और इमारत पर पीएम मोदी की तस्वीर भी दिखाई गयी। यह प्रधानमंत्री की वैश्विक लोकप्रियता को भी दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश यात्राओं में श्रेष्ठ भरतीय परम्पराओं को नहीं छोड़ते हैं साथ ही अपनी पुरानी परम्पराओं को नये धागे में पिरोकर भारतीय संस्कृति का मान बढ़ाते हैं और यही कारण है कि संपूर्ण विश्व में भारतीय सनातन संस्कृति का डंका बज रहा है और सभी देशों के लोग इसको समझने के लिए लालायित हैं।

प्रधानमंत्री मोदी की यूएई यात्रा ऐसे समय में हुई है जब भारत में समान नागरिक संहिता को लागू करने की प्रक्रिया का आरंभ हो चुका है और तमाम विरोधी दल मुस्लिम संगठनों का साथ लेकर पूरी ताकत से इसका विरोध कर रहे हैं किंतु जिस प्रकार मिस्र के बाद यूएई में भी प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान किया गया है उससे मुस्लिम तुष्टिकरण करने वालों की नींद गायब हो गयी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस भी देश की यात्रा पर जाते हैं उस देश में उपस्थित भारतीय समुदाय को भी अवश्य संबोधित करते हैं और भारत के लिए अपने भविष्य की दृष्टि को उजागर करते हैं इससे भारत में चुनावों में उनको पराजित करने के लिए महागठबंधन बना रहे दल व नेता बेचैन हो उठते हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात में भव्य स्वागत हुआ तो भारत के अंदर मुस्लिम तुष्टिकरण करने वाले राजनैतिक दल बेचैन हो उठे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व उनकी सरकार को जो अराजक राजनैतिक तत्व मुस्लिम विरोधी बताकर अपनी छवि को सुधारना चाहते थे उनका प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व उनकी सफल नीतियों का ही परिणाम है कि आज संपूर्ण विश्व में भारत की आवाज को सुना जा रहा है। राजनैतिक विश्लेषक अनुमान लगा रहे हैं कि वर्ष 2024 का लोकसभा चुनाव व उससे पहले होने जा रहे विधानसभा चुनावों पर मोदी की मिस्र और यूएई आदि देशों की यात्राओं का उदारवादी व लाभार्थी मुसलमानों के बीच अच्छा संदेश जाएगा और विपक्ष भाजपा व मोदी की छवि पर जो आघात करने का प्रयास कर रहा है उससे निपटने में भी आसानी रहेगी। महत्वपूर्ण यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 के लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखकर संबोधन नहीं करते हैं अपितु वह आगामी 25 वर्षों के लिए देश के विकास व विश्व के देशों से संबंधों का रोडमैप बताते हैं जिसके कारण सामान्य जन स्वाभाविक रूप से उनका नेतृत्व स्वीकार करता है और परिवारवादी भ्रष्टाचारी दलों को अपने अस्तित्व पर संकट मंडराया दिखता है।

भारतीय ज्ञान परंपरा....

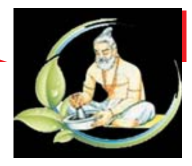

ध्यानबिन्दुपनिषद् (भाग-3)

गतांक से आगे...

हृदयकमल की कर्णिका के मध्य स्थिर ज्योतिशिखा के समान अंगुष्ठमात्र आकार के नित्य कार रूप परमात्मा का ध्यान करे। इड़ा (बायीं नासिका) से वायु को भरकर उदर में स्थापित करे और देह के बीच में ज्योतिर्मय कार का ध्यान करे। पूरक, कुम्भक और रेचक को क्रमश: ब्रह्मा, विष्णु रुद्र कहा गया है, ये प्राणायाम के देवता कहलाते हैं। यहाँ यह ध्यातव्य है कि आगे चलकर 29 से 31 मन्त्र में पूरक के समय विष्णु कुम्भक के समय ब्रह्मा एवं रेचक के समय शिव का ध्यान करना लिखा है। यही पुरातन परम्परा भी है, परन्तु इस मन्त्र में पूरक को ब्रह्मा और कुम्भक को विष्णु कहा जाना परम्परा से हटकर है, जो विचारणीय है।

अन्त:करण और प्रणवाक्षर को नीचे और ऊपर की अरणिरूप बनाकर मंथनरूप ध्यान के अभ्यास से अग्रि की भाँति व्याप्त गूढ़त्तत्व (परमात्मा) का साक्षात्कार करे।

प्रणव ध्वनि का, नाद सहित रेचक वायु के विलय हो जाने तक अपनी सामर्थ्यानुसार (तब तक) ध्यान करे, जब तक नाद का भली प्रकार लय नहीं हो जाता। गमन और आगमन में विद्यमान तथा गमनादि से रहित, करोड़ों सूर्यो की प्रभा के समान सभी मनुष्यों के अन्त:करण में विराजमान हंसात्मक प्रणव का जो दर्शन करते हैं, वे कृतकृत्य हो जाते हैं। जो मन त्रिगुणमय संसार के सृजन पालन और संहार का कारण है, उसके विलय हो जाने पर विष्णु के परमपद की प्राप्ति होती है। अष्टदल और बत्तीस पंखुड़ियों से युक्त जो हृदयकमल है, उसके बीच सूर्य और सूर्य के बीच चन्द्रमा विद्यमान है। चन्द्रमा के बीच अग्नि और अग्नि के बीच दीप्ति स्थित है। उसके बीच नानाविध रत्नों से सुसज्जित पीठस्थान है। उस पीठ के बीच निरञ्जन प्रभु वासुदेव विराजमान हैं, जो श्रीवत्स, कौस्तुभमणि एवं मणि- मुक्ताओं से विशेष रूप से सुशोभित हैं। शुद्ध स्फटिक के सदृश करोड़ों चन्द्रमा की कान्ति वाले महाविष्णु का विनयान्वित होकर ध्यान करे। पूरक द्वारा साँस अन्दर खींचते समय नाभिस्थान में प्रतिष्ठित अतसी पुष्प के समान चतुर्भुज महाविष्णु भगवान् का ध्यान करना चाहिए। कुम्भक द्वारा साँस भीतर रोकने के समय हृदय स्थल में कमल के आसन पर सुशोभित लालिमामय गौर वर्ण वाले चतुर्मुख पितामह ब्रह्मा का ध्यान करना चाहिए। रेचक से साँस छोड़ते हुए ललाट में शुद्ध स्फटिक के सदृश श्वेत रंग के त्रिनेत्रयुक्त, निष्कल (कलारहित), पाप संहारक भगवान् शिव का ध्यान करना चाहिए।

क्रमश: ..

बपचन में बिल्कुल बेसुरे थे किशोर कुमार

रेनू तिवारी

जब भी गायकी की बात आती है तो किशोर कुनार का नाम जहन में आता है। किशोर कुमार जब गाते थे तो उनके पास कोई खास म्युजिक की ड्रिग्री या शास्त्रीय प्रशिक्षण नहीं था लेकिन किशोर दा वास्तव में सभी ट्रेडों के उस्ताद थे- चाहे वह उनकी खूबसूरत आवाज़ हो जो किसी भी गीत को जीवंत कर देने वाली उनकी कला। किशोर दा एक ऐसे अभिनेता भी थे जिन्होंने कॉमेडी में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। हालांकि उन्हें भारतीय सिनेमा के सबसे महान पार्श्व गायकों में से एक के रूप में जाना जाता है, बहुआयामी किशोर कुमार एक गीतकार, संगीतकार, निर्माता, निर्देशक, पटकथा लेखक और पटकथा लेखक भी थे।

किशोर कुमार फिल्म इंडस्ट्री के उन सिंगर्स में से हैं जिन्हें हर उम्र के लोगों ने बराबर प्यार दिया। किशोर कुमार ने अपनी आवाज की ऐसी छठा बिखेरी कि सब उनके मुरीद हो गये। आज भी उनके गाये गीतों को लोग बड़े चाव से सुनते हैं। इसके अलावा वे अपनी कॉमिक टाइमिंग के लिए भी जाने जाते हैं उन्होंने अपने इस हुनर से 50-60 के दशक में दर्शकों को खूब हंसाया। 4 अगस्त 1929 को आभास कुमार गांगुली के नाम से जन्में किशोर का नाम सुनते ही एक कंफ्यूजन दिमाग में दौड़ती है कि उन्हें किस रुप में याद किया जाए। वो एक्टर, सिंगर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, म्यूजिक डायरेक्टर, और सबसे बढ़कर एक कमाल की शख्सियत थे। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को कई सदाबहार क्लासिक दिए, जिसे सुनकर आज भी हर कोई मदहोश हो जाता है। मेरे मेहबूब..., आ चल के तुझे..., आने वाला पल..., बचना ए हसीनो... आदि सैंकड़ों गीत आज भी बड़े चाव से सुने जाते हैं।

किशोर कुमार ने कुछ फिल्मों का निर्देशन भी किया, जिनमें चलती का नाम जिंदगी, बढ़ती का नाम दाढ़ी, दूर का राही, दूर गगन की छांव में प्रमुख हैं। उन्हें 8 बार बेस्ट सिंगर के फिल्मफेयर अवॉर्ड से नवाजा गया था। किशोर कुमार की आवाज एक ऐसी आवाज थी जिसने कई स्टार्स को सुपरस्टार बनाया। मस्तमौला अंदाज वाले किशोर के जन्मदिन पर आइए जानते है उनसे जुड़े कुछ मजेदार और अनसुने किस्से।

किशोर कुमार की आवाज को लेकर एक बहुत ही मजेदार कहानी है कहते है की बचपन में किशोर दा की आवाज बहुत ही खराब थी। आज दिलो पर राज करने वाले किशोर दो उस टाइम बिल्कुल बेसुरे थे। उनके बड़े भाई अशोक कुमार ने एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा करते हुए कहा था कि बचपन में किशोर की आवाज फटे बांस जैसी थी, लेकिन एक बार उनका पांव सब्जी काटने वाली दराती पर पड़ गया, जिससे उनके पैर की अंगुली कट गई। डॉक्टरों ने उंगली का तो इलाज कर दिया लेकिन किशोर का दर्द नहीं गया। वो कई दिनों तक दर्द के कारण जोर-जोर से रोया करते थे। इस घटना की वजह से उनका ऐसा रियाज हुआ कि उनकी आवाज ही बदल गई। इस तरह घंटो रोने से उनकी वोकल कॉर्ड्स पर असर पड़ा और उनकी आवाज हस्की हो गई। किशोर की यह नई आवाज उस हादसे की देन थी। और आज किशोर दा इंडस्ट्री के टॉप सिंगर्स में गिने जाते हैं। उनकी ताजगी भरी आवाज आज भी कानों में पड़ती है तो जोश भर आता है।

13 अक्टूबर, 1987 को उन्होंने दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। किशोर कुमार और सबके दिलों को छू जाने वाले उनके गीतों को भुलाया जाना मुमकिन नहीं है। वे सदा गीत प्रेमियों के दिलों पर राज करते रहेंगे।

पाक सेना पर निशाना साधने वाले नवाज अब क्यों बने फेवरेट

अभिनय आकाश

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बड़ी घोषणा की है कि उनके बड़े भाई और पार्टी प्रमुख नवाज शरीफ जल्द ही देश लौटेंगे। उन्होंने कहा कि अगर सत्तारूढ़ गठबंधन सत्ता में लौटता है तो नवाज प्रधानमंत्री का पद संभालेंगे। बता दें कि नवाज शरीफ पाकिस्तान के तीन बार के प्रधानमंत्री हैं। वर्तमान में वो लंदन में रह रहे हैं। 2017 में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अयोग्य करार दिया था। 2018 में पनामा पेपर्स मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वो जीवन भर सार्वजकि पद संभालने के लिए अयोग्य हो गए। 2019 में वो चिकित्सा आधार पर लाहौर उच्च न्यायालय से चार सप्ताह की जमानत पर लंदन रवाना हो गए। नवाज शरीफ अल-अजीजिया मिल्स भ्रष्टाचार मामले में सात साल की जेल की सजा हुई थी। कोर्ट से जमानत मिलने के बाद वो वापस पाकिस्तान दोबारा नहीं लौटे। लेकिन अब पूरी तैयारी कर ली गई है। नवाज शरीफ अपने ग्रैंड कम बैक के लिए तैयार हैं। उनके छोटे भाई शहबाज शरीफ ने संकेत दिए है कि कुछ ही हफ्तों में नवाज की वतन वापसी हो सकती है। लेकिन ये केवल संयोग नहीं है। इसकी टाइमिंग पर गौर करें तो नेशनल असेंबली 12 अगस्त से पहले भंग कर दी जाएगी। इसके बाद पाकिस्तान में चुनावी माहौल का आगाज हो जाएगा। इन सब के बीच ही नवाज शरीफ पाकिस्तान लौट रहे हैं। ऐसे में ये सवाल उठ रहे हैं कि नवाज को क्यों लौटने दे रही है सेना? क्या सेना और शरीफ़ों के बीच कोई गुप्त समझौता हो गया है?

सत्ताधारी गठबंधन को शायद जीत की गारंटी दी गई है, वरना नवाज़ शरीफ़ कभी वापस नहीं आते। उनके लिए जोखिम बहुत अधिक है। पाकिस्तान सरकार उनके लिए जमीन तैयार कर रही है। पिछले ही महीने पाकिस्तान की सरकार की तरफ से एक नया कानून लाया गया। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने कानून पारित किया है कि सांसदों को कितने समय तक पद से अयोग्य ठहराया जा सकता है। संशोधन में कहा गया कि अदालतें केवल पांच साल की अवधि के लिए सांसदों को अयोग्य घोषित कर सकती हैं। नवाज शरीफ को 2017 में अयोग्य घोषित किया गया था। इसमें पांच साल जोड़ने पर ये 2023 यानी वर्तमान वर्ष तक की अवधि तक ही जाता है। या तो शरीफ बहुत ही भाग्यशाली है या फिर सब सुनियोजित ढंग से किया गया। पाकिस्तान में ऐसा ही कुछ होता रहा है, वहां की सेना आपके भाग्य का फैसला करती है।

सरकार 12 अगस्त को आधिकारिक तौर पर पद छोड़ देगी। नवंबर में आम चुनाव होंगे। वर्तमान माहौल पर गौर करें तो सत्तारूढ़ गठबंधन के दोबारा पावर में लौटने की प्रबल संभावना है। बस किसे कितनी सीटें मिलेंगी इसका जवाब उसी वक्त पता चलेगा। पाकिस्तान की सत्तारूढ़ गठबंधन में दो बड़े दलों में बिलावल भुट्टो जरदारी के नेतृत्व वाली पीपीपी और शरीफ परिवार की पीएमएनएल नमाज शामिल हैं। लेकिन ये चुनाव सेना के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले कुछ महीने पाकिस्तान के लिए मुश्किल भरे रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी और फिर उनके समर्थकों का सेना हेडक्वार्टर पर हमले ने सेना की बहुत किरकिरी करवाई है। ऐसे में पाकिस्तानी सेना के पास दो विकल्प है। या तो पीटीआई को बैन करके इमरान खान को जेल में डाल दे, नहीं तो फिर इमरान को उनके ही खेल में मात दी जाए। सेना ने दूसरा विकल्प चुना है। इमरान खान और उनकी पार्टी को बैन नहीं किया जाएगा। उन्हें चुनाव लड़ने की छूट दी जाएगी। फिर जब इमरान खान की चुनाव में हार होती है तो सेना का अगला कदम सभी को पता है।

सभी तैयारियां कर ली गई हैं। पीटीआई को तोड़ दिया गया है। फवाद चौधरी समेत बड़े नेता इमरान का साथ छोड़ चुके हैं। इतना ही नहीं इमरान समर्थकों को सैन्य कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि नवाज शरीफ का निर्णय थोड़ा सा आश्चर्यजनक है। सेना के साथ उनके संबंध हमेशा तनावपूर्ण रहे हैं। 2020 में लंदन से वर्चुल रूप से अपने संबोधन में उन्होंने सैन्य शासकों पर जमकर निशाना साधा था। उन्होंने पूर्व सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा पर उनकी सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाया था। फिर आखिर इन 2-3 सालों में क्या बदल गया? जवाब दो शब्दों में है- इमरान खान।

पाकिस्तान में राजनेता उस पैकेट की तरह हैं जो आपके मोबाइल फोन के साथ आता है। पैकेट से किसी को कोई मतलब नहीं लेकिन आप प्रोडक्ट को पैकेट के बिना बेच नहीं सकते। पाकिस्तान में ये पैकेट वक्त के साथ बदलते रहते हैं। साल 2018 में सेना शरीफ को सत्ता से बाहर करना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने इमरान खान को सत्ता संभालने के लिए जमीन तैयार की। अब पाक सेना का एक ही मकसद है कि कैसे भी करके इमरान खान को सत्ता से बाहर रखा जाए। इसलिए वो शरीफ का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक तय एकाधिकार वाले खेल की तरह है। जहां सेना ही जीत होगी, वहीं पाकिस्तान की जनता ही हमेशा हार ही होगी।

बापू की दिनचर्या

आचार और व्यवहार (भाग-5)

गतांक से आगे...

कहते हैं कि बस उसी समय उन्होंने अपने उन कपड़ों का त्याग कर दिया और अधनंगा रूप धरण कर लिया। उनकी कच्छनुमा धोती की लंबाई बाई गज और चौड़ाई लगभग एक गज होती। सन् 1930 या 32 में बापू प्रयाग में नेहरूजी के आनंद भवन में टिके थे। जाड़े के दिन थे। उन दिनों उनके पास एक पतला ऊनी कंबल था, जो घिसा हुआ (पुराना) था। सौराष्ट्र में बना कंबल पुराना होने पर भी गरमी देता है। नया कंबल ग्रहण करने के आग्रह पर उन्होंने कहा था- अरे, गरीबों की ओर क्यों नहीं देखते, जो सारा जाड़ा चार हाथ के अँगोछे में काट देते हैं। मैं उन्हीं का प्रतिनिधि हूँ न? सन् 1931 में गोलमेज परिषद् में बापू लंदन गए तो सम्राट् पंचम जार्ज ने उनको मिलने के लिए आमंत्रित किया। जब वे उनके महल में जाने को निकले, तब पैरों में चप्पल, कमर में अँगोछा और कंधे पर चादर! अरे, इस पोशाक में सम्राट् के महल में उनसे मिलेंगे? - ऐसा बहुतों ने सोचा, पर कहता कौन? बापू की सुविधा पर नियुक्त अंग्रेज अफसर यह दृश्य देख तुरंत उठा, किंतु उनसे कुछ कहना उसकी अधिकार-सीमा से बाहर था। फिर भी, संयत स्वर में उसने कहा- क्षमा कीजिएगा, क्या आप सोचते हैं कि आप बादशाह से मिलने योग्य पोशाक में जा रहे हैं? बापू के निकट परिषद् के एक-दूसरे प्रतिनिधि खड़े थे, अंग्रेजी वेशभूषा से सजे-धजे, एकदम साहबबहादुर। उनकी तरफ देखकर बापू उस अफसर से बोले-आप चिंता न करें, बादशाह के पास हम दोनों के योग्य पोशाक होगी। जो पास खड़े थे, वे इतनी जोर से हँसे कि साहबबहादुर भी सकुचा गए और वह अफसर भी । लौटने पर फिर किसी ने कहा- आप राजभवन में कम-से-कम अच्छा लिबास पहनकर गए होते! बोले- मेरे न सही, सम्राट् के शरीर पर तो हम दोनों के लिए पर्याप्त कपड़े थे न?

क्रमश: ...

कांग्रेस का मिशन डाइनिंग, दस जनपथ से आएगा बुलावा

नईदिल्ली। जैसे-जैसे लोकसभा के चुनाव नजदीक आते जाएंगे कांग्रेस अपने सियासी एजेंडे में अलग-अलग तरह के मिशन को शामिल कर लोगों से जुड़ने का अभियान चलाती जाएगी। कांग्रेस के रणनीतिकारों ने लोगों से सीधे तौर पर जुड़ने के लिए ऐसे कई आयोजनों की पूरी फेहरिस्त तैयार की है। जिसके माध्यम से सोनिया, राहुल और प्रियंका से लोगों की सीधी मुलाकात हो सके। इस कड़ी में कांग्रेस की ओर से मिशन डाइनिंग शुरू किए जाने की योजना बन रही है। इसमें रोज कमाने खाने वालों से मुलाकातों के साथ-साथ उनको 10 जनपथ पर बुलाकर भोजन भी कराए जाने की योजना बन रही है।

कांग्रेस पार्टी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक जिस तरह से राहुल गांधी लगातार देश के अलग-अलग हिस्सों में जाकर लोगों से मिल रहे हैं, वह पार्टी को आने वाले चुनावी दिनों के लिए बेहद मुफीद कनेक्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस के रणनीतिकारों ने तय किया है कि राहुल गांधी की मुलाकात के बाद अब ऐसे ही रोज कमाने खाने वालों को एक-अलग-अलग ग्रुप को एक समय के अंतराल पर राहुल, प्रियंका और सोनिया गांधी से मुलाकात के लिए उनके आवास पर भी बुलाया जाएगा। कांग्रेस के रणनीतिकारों के मुताबिक इनमें वह ग्रुप शामिल होंगे, जिनसे राहुल गांधी पहले से फील्ड में जाकर लोगों से मुलाकात कर चुके होंगे। इस कड़ी में शुरुआत हरियाणा की उन किसान महिलाओं से हो भी चुकी है, जिनसे राहुल गांधी ने पिछले महीने शिमला जाने के दौरान खेतों में मुलाकात की थी। इन किसान महिलाओं को बीते दिनों सोनिया गांधी के आवास पर भोजन के दौरान मिलने के लिए भी बुलाया गया था।

कांग्रेस के रणनीतिकारों के मुताबिक लोगों से मुलाकात का यह सिलसिला पार्टी के लिए भी प्रेरणादायक था और मिलने आई महिलाओं और बच्चों के लिए भी एक यादगार लम्हा था। इस मुलाकात के बाद ही तय किया गया कि आने

वाले दिनों में इस तरह के और आयोजन किए जाते रहेंगे। पार्टी से जुड़े रणनीतिकारों के मुताबिक लंच या डिनर पर देश के उन लोगों को बुलाए जाने की योजना बन रही है, जो अपनी दिनचर्या में रोज कमाने खाने वाले लोग हैं। सूत्रों के मुताबिक शुरुआती दौर में यही हो रहा है कि जो रोजमर्रा की जिंदगी में कमाने खाने वाले लोग हैं, उन्हें सोनिया गांधी के आवास पर बुलाया जाए। उनके साथ कांग्रेस पार्टी के नेता बैठकर भोजन भी करेंगे और देश की समस्याओं के साथ उनकी समस्याओं से रूबरू होकर उनसे ही उनकी समस्याओं को दूर किए जाने वाले उपायों पर बातचीत करेंगे।

कांग्रेस पार्टी से जुड़े नेताओं का कहना है कि इस समय देश के कई अलग-अलग राज्यों में सीधे तौर पर उनकी सरकारें हैं या फिर गठबंधन के साथ सत्ता में हैं। पार्टी का मानना है, इसलिए लोगों से सीधे तौर पर मिलकर उनकी समस्याओं को जानकर और उनसे ही उनके निराकरण पर बात करके बहुत से समाधान निकाले जा सकते हैं। यही वजह है कि ऐसे लोगों से सीधे तौर पर मुलाकात करके और उनको दिल्ली में कांग्रेस के नेताओं के साथ खाने पर बुलाकर जो चर्चा होगी और उसके बाद जो उनकी समस्याओं को दूर करने के उपाय होंगे, उन्हें कांग्रेस शासित राज्यों में लागू भी किया जाएगा। कांग्रेस के रणनीतिकारों में शामिल एक वरिष्ठ नेता कहते हैं कि यह लोगों से मुखातिब होने और उनकी समस्याओं को दूर करने के साथ-साथ लोगों से सीधे जुड़ने का यह बेहतर तरीका है।

कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पीएल पुनिया कहते हैं कि राहुल गांधी लगातार समाज के उन लोगों से मिल रहे हैं, जिनका योगदान देश को मजबूत करने में हैं। अभी राहुल गांधी ने दिल्ली की आजादपुर मंडी में जाकर किसानों से लेकर दिल्ली की अलग-अलग बाजारों में सब्जी और फल बेचने वालों से मुलाकात की थी। इससे पहले हरियाणा में महिला किसानों से राहुल गांधी ने मुलाकात की। दिल्ली के मैकेनिक हों या राह चलते ट्रक ड्राइवर। राहुल गांधी रोज कमाने खाने वालों से मुलाकात कर रहे हैं। ऐसी ही मुलाकातों को लेकर कांग्रेस पार्टी के एक अन्य वरिष्ठ नेता कहते हैं कि इस तरह की मुलाकातों का सिलसिला राहुल गांधी अब लगातार करते रहेंगे।

पार्टी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी का ऐसे लोगों से मिलने का सिलसिला सिर्फ चुनावी राज्यों में ही नहीं चलेगा। वह कहते हैं कि राहुल गांधी उन राज्यों में भी ऐसे ही लोगों से मुलाकात करेंगे, जहां पर फिलहाल विधानसभा चुनाव नहीं होने हैं। इसके पीछे के तर्क को लेकर सियासी जानकारों का मानना है कि दरअसल यह एक तरीके से दिखाने की कोशिश है कि वह इन मुलाकातों के माध्यम से राजनीति नहीं कर रहे हैं। राजनीतिक जानकार और वरिष्ठ पत्रकार जीडी शुक्ला का मानना है कि किसी बड़े राजनेता खासतौर से राहुल गांधी जैसे बड़े कद के नेताओं का इस तरह लोगों से मिलना-जुलना एक सामान्य प्रक्रिया तो नहीं हो सकती है। अब जब ऐसे मिलने वालों को अपने घर पर बुलाकर साथ में खाना खाया जाएगा, तो निश्चित तौर पर एक कनेक्ट बनेगा। शुक्ला मानते हैं कि किसी भी बड़े कद के नेता का ऐसे लोगों से मिलना-जुलना और फिर उन्हें अपने घर पर बुलाकर भोजन करना उन्हें सीधे तौर पर जोड़ता है। वह कहते हैं कि यही वजह है कि राहुल गांधी का यह फॉर्मूला हिट भी माना जा रहा है। शुक्ला का मानना है कि राहुल गांधी ने बीते चुनावों में कर्नाटक में भी ऐसे ही लोगों से मुलाकात की थी और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान लगातार ऐसे लोगों से मिलते रहे थे। इसलिए, कमाने-खाने वालों से मिलने के फॉर्मूले पर पार्टी लोकसभा के चुनावों के नजरिए से बड़ी फील्डिंग सजा रही है।

न्यायाधीश ने तीस्ता की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग किया

गुजरात। राज्य सरकार ने पहले सत्र अदालत में सुनवाई के दौरान आरोप लगाया था कि सीतलवाड़ ने तत्कालीन मुख्यमंत्री (अब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी), वरिष्ठ अधिकारियों और मंत्रियों सहित निर्दोष व्यक्तियों को फंसाने के लिए, पीड़ितों के नाम पर हलफनामे तैयार किये थे। एहसान जाफरी उन 68 लोगों में शामिल थे, जो गोधरा ट्रेन अग्निकांड के एक दिन बाद 28 फरवरी, 2002 को अहमदाबाद की गुलबर्ग सोसाइटी में भड़की हिंसा के दौरान मारे गए थे। गोधरा ट्रेन अग्निकांड में 59 लोगों की मौत हुई थी। गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति समीर दवे ने बृहस्पतिवार को सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ की उस याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया, जिसमें उन्होंने 2002 के दंगों के मामलों में कथित रूप से फर्जी सबूत गढ़ने के लिए अहमदाबाद अपराध शाखा द्वारा उनके खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी को रद्द करने का अनुरोध किया गया है। सुनवाई के लिए जब मामले का उल्लेख किया गया तो न्यायमूर्ति दवे ने कहा, ''मेरे सामने नहीं। अब, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मामले को एक नये न्यायाधीश के पास भेजेंगे।'' एक सत्र अदालत ने इस मामले में आरोपमुक्त किये जाने संबंधी सीतलवाड़ की याचिका पिछले महीने खारिज कर दी थी।

लैटिन अमेरिका, कैरेबियाई देशों के साथ भारत के संबंध ऊंचे स्तर पर : जयशंकर

विदेश मंत्री बोले- 2027 तक व्यापार दोगुना पहुंच सकता है

नईदिल्ली। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को कहा कि भारत और लैटिन अमेरिका और कैरेबियन (एलएसी) क्षेत्र के देशों को 2027 तक दोतरफा व्यापार को दोगुना कर 100 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखना चाहिए। उन्होंने आर्थिक संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए चार सूत्री योजना की रूपरेखा तैयार की है। जयशंकर ने विदेश मंत्रालय और भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित भारत-एलएसी कॉन्क्लेव के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि दोनों पक्षों को गतिशीलता समझौतों पर बातचीत करने पर भी विचार करना चाहिए क्योंकि कानूनी गतिशीलता ज्ञान अर्थव्यवस्था में तेजी से महत्वपूर्ण और पारस्परिक रूप से लाभप्रद होती जा रही है।

2022-23 में दोनों क्षेत्रों के बीच लगभग 50 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ और ब्राजील को भारत का निर्यात 10 बिलियन डॉलर रहा, जो जापान को होने वाले निर्यात से लगभग दोगुना है। जयशंकर ने कहा कि व्यापार की मात्रा

2027 तक दोगुनी होकर 100 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है और लक्ष्य निर्धारित करना परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रेरक के रूप में कार्य करता है। विदेश मंत्री ने भारत और एलएसी देशों के बीच गहन व्यापार और आर्थिक जुड़ाव के लिए चार स्तंभों वाली एक योजना का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों को आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरण पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि कोविड-19 महामारी ने अतिरिक्त सोर्सिंग, विविध उत्पादन और खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा के लिए लचीली आपूर्ति श्रृंखला की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है।

भारत की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की स्थिति और देश में तेल, गैस, रणनीतिक खनिज और भोजन की बढ़ती मांग को देखते हुए, दोनों पक्षों को संसाधन साझेदारी पर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारतीय उत्पाद और सेवाएं एलएसी देशों के मध्यम वर्ग की जरूरतों को भी पूरा कर सकते हैं। दोनों पक्षों को डिजिटल क्षमताओं, स्वास्थ्य समाधान और कृषि प्रथाओं सहित विकासात्मक अनुभवों को साझा करना चाहिए। इस संदर्भ में, भारत एलएसी देशों के लिए अनुकूलित प्रशिक्षण और आदान-प्रदान प्रदान कर सकता है।

हरियाणा में हिंसा को लेकर समूचा विपक्ष राज्य सरकार पर हमलावर, मगर ममता ने कर दिया खट्टर का समर्थन

चंडीगढ़। हरियाणा में हाल की हिंसक घटनाओं के चलते समूचा विपक्ष मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पर हमला बोल रहा है। कोई कह रहा है कि भाजपा को सरकार चलाना नहीं आता यह मणिपुर और हरियाणा की घटनाओं से साबित हो गया है, कोई कह रहा है कि डबल इंजन सरकार का डबल इंजन फेल हो गया है। ऐसे ही तीखे व्यंग्य इस समय हरियाणा की भाजपा-जजपा सरकार पर किये जा रहे हैं। यही नहीं, विश्व हिन्दू परिषद और बजरंग दल जैसे संघ परिवार के घटक भी हरियाणा सरकार से नाराजगी जता रहे हैं कि वह उनके कार्यकर्ताओं पर हुए हमले को नहीं रोक पाई। यानि मनोहर लाल खट्टर चारों तरफ से घिरे हुए हैं लेकिन हैरत की बात यह है कि ऐसे कठिन समय में उन्हें ममता बनर्जी का साथ मिला है। वह ममता बनर्जी जोकि भाजपा और मोदी सरकार पर हमले का कोई मौका नहीं चूकतीं उन्होंने खट्टर का समर्थन करके सभी को हैरान कर दिया है।

हम आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हरियाणा के अपने समकक्ष और भाजपा नेता मनोहर लाल खट्टर के इस बयान का स्वागत किया है कि हर किसी की सुरक्षा नहीं की जा सकती। मगर ममता बनर्जी ने कहा कि सरकार को जातिवाद या सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। ममता बनर्जी ने साथ ही आरोप लगाया कि सांप्रदायिक तनाव

की घटनाओं की पटकथा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने लिखी है और इसका मकसद चुनाव जीतने के लिए लोगों को विभाजित करना है। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) प्रमुख ने पत्रकार वार्ता में कहा, मैंने मनोहर लाल खट्टर का बयान देखा है। एक राजनीतिक नेता के तौर पर नहीं बल्कि इस देश के नागरिक के तौर पर मैं उनके बयान की सराहना करूंगी क्योंकि ये सच है कि सरकार हर किसी को सुरक्षा नहीं दे सकती है। ममता बनर्जी ने कहा, ''लेकिन मैं यह भी कहूंगी कि सरकार जातिवाद, पंथवाद या सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा नहीं दे सकती...सांप्रदायिक तनाव इसलिए शुरू हुआ क्योंकि भाजपा चुनाव जीतने के लिए लोगों को जाति, पंथ और देश के आधार पर बांटने का गंदा खेल खेल रही है।'' उन्होंने कहा कि सरकार हालांकि लोगों को शांति प्रदान कर सकती है। ममता बनर्जी ने कहा, अगर हम मानसिक रूप से मजबूत हैं व एकजुट हैं और लोगों को नहीं बांटेंगे तो ऐसी चीजें नहीं होंगी। ऐसा नफरत भरे भाषण और उकसावे की वजह से होता है। ममता बनर्जी ने इस बात पर भी आश्चर्य जताया कि जिन राज्यों में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं हुई हैं, वहां कोई केंद्रीय दल क्यों नहीं भेजा गया? जहां तक ममता की ओर से खट्टर के समर्थन की बात है तो इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि खुद पश्चिम बंगाल सरकार पर राज्य में हिंसा की घटनाओं को नहीं रोक पाने के आरोप हैं। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनावों के दौरान जिस तरह हिंसा का तांडव हुआ उससे राज्य की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठे थे। इसलिए, जब खट्टर ने कहा कि सरकार के लिए हर नागरिक की रक्षा करना संभव नहीं है, तो ममता को ऐसा हथियार मिल गया जिससे वह भविष्य में भाजपा की ओर से किये जाने वाले वारों के समय पलटवार कर सकती हैं।

जहां तक हरियाणा के हालात की बात है तो वह इस समय शांत हैं। आगे से फिर कोई बवाल नहीं हो इसके लिए हरियाणा सरकार ने अभी से तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। हम आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा नूंह में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की दंगा-रोधी इकाई त्वरित कार्रवाई बल (आरएएफ) की एक नयी बटालियन को मंजूरी दिए जाने के लगभग पांच साल बाद, हरियाणा सरकार ने आखिरकार इसके लिए जमीन को मंजूरी दे दी। हरियाणा सरकार ने बटालियन के लिए जमीन की मंजूरी ऐसे समय दी है जब जिले में सांप्रदायिक झड़पें हुई हैं।

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक लोकसभा में हुआ पेश, कांग्रेस ने किया विरोध

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2023 लोकसभा में पेश किया। गौरतलब है कि केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बुधवार को कहा था कि सरकार गुरुवार को संसद में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (डीपीडीपी) विधेयक पेश कर सकती है।

उधर कांग्रेस ने इस विधेयक का विरोध किया है। लोकसभा में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, 2023 पेश होने पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि मैं बिल का विरोध करता हूं। इस बिल के जरिए सरकार सूचना का अधिकार, कानून और निजता के अधिकार को कुचलने जा रही है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि हम इस सरकार द्वारा प्रदर्शित किए जा रहे इस तरह के इरादे का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। इस बिल को स्थायी समिति या किसी अन्य मंच पर चर्चा के लिए भेजें। हालांकि राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बुधवार कहा था कि विधेयक को कभी भी स्थायी समिति के पास नहीं भेजा गया। मंत्री ने यह भी कहा था कि स्थायी समिति ने नागरिकों की गोपनीयता और डेटा संरक्षण के मुद्दे का स्वयं मूल्यांकन किया है, पहले के मसौदे को देखा है और टिप्पणी की है।

गौरतलब है कि पीडीपीडी विधेयक में प्रस्तावित किया गया है कि उल्लंघन की प्रत्येक घटना के लिए ?250 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सरकार ने कहा कि डीपीडीपी एक महत्वपूर्ण कानून है जो भारत में व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा को बढ़ाएगा। विधेयक के लागू होने से व्यक्तिगत डेटा के उपयोगकर्ताओं को अपनी निजता की रक्षा करने और अपने डेटा के दुरुपयोग से बचने में मदद मिलेगी।

सरकार के मुताबिक, यह विधेयक व्यक्तिगत डिजिटल डेटा के उपयोग को सुरक्षित करने की कोशिश करता है। उपयोगकर्ताओं के कर्तव्यों को सुनिश्चित करते हुए एकत्रित डाटा का कानूनी रूप से उपयोग करने के दायित्वों को निर्धारित करता है। यह विधेयक इन सिद्धांतों पर आधारित है कि व्यक्तिगत डेटा का संग्रह और उपयोग वैध होना चाहिए और पारदर्शिता बनी रहे। उद्देश्य पूरा होने तक डाटा को सुरक्षित रूप से संग्रहित किया जाना चाहिए। व्यक्तियों का प्रासंगिक डेटा एकत्र किया जाना चाहिए। और पूर्व-निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति ही एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए। साथ ही डाटा की सटीकता भी महत्वपूर्ण है।

अपतटीय क्षेत्र खनिज कानून में संशोधन विधेयक पारित

नई दिल्ली। मणिपुर मुद्दे पर विपक्ष के विरोध के बीच लोकसभा के बाद अब राज्यसभा ने भी अपतटीय क्षेत्र खनिज कानून संशोधन विधेयक 2023 पारित कर दिया है। मणिपुर मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों के बहिर्गमन के बीच इस विधेयक को ध्वनिमत से पारित किया गया। अब इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की अनुमति के बाद यह विधेयक कानून बन जाएगा। इस विधेयक में अपतटीय खनिजों के लिए एक निश्चित 50-वर्षीय उत्पादन पट्टा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। बता दें कि अपतटीय क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2002 में लागू किया गया था। बता दें कि इससे पहले, मंगलवार को लोकसभा ने इस विधेयक को पारित कर दिया था। गुरुवार को दोपहर के बाद इस विधेयक को चर्चा के लिए राज्यसभा में कोयला और खान मंत्री प्रल्हाद जोशी ने पेश किया। वहीं, इस दौरान विपक्षी दलों ने मणिपुर पर चर्चा को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। बावजूद इसके राज्यसभा से इस विधेयक को भारी हंगामे के बीच पारित कर दिया गया। इस विधेयक में अपतटीय खनिजों के लिए 50-वर्षीय उत्पादन पट्टा प्रदान करने का प्रावधान है। इसके विधेयक में अपतटीय खनिजों के लिए उत्पादन पट्टा नीलामी प्रक्रिया के जरिए देने का प्रावधान है । इसके अलावा, विधेयक में परमाणु खनिजों के संबंध में अन्वेषण लाइसेंस या उत्पादन पट्टा केवल सरकार या सरकारी निगम को देने का प्रावधान किया गया है।

पाक पीएम के बयान पर भारतीय विदेश मंत्रालय की दो टूक

पाकिस्तान को बातचीत के लिए आतंकमुक्त माहौल बनाना होगा

नईदिल्ली। देशों के बीच बातचीत को लेकर पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की भारत पर टिप्पणी पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि हमने रिपोर्टें देखी हैं। भारत का रुख इस बात पर कायम है कि हम सभी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध चाहते हैं...लेकिन इसके लिए आतंक और शत्रुता से मुक्त वातावरण जरूरी है। उन्होंने कहा कि पीओके भारत का क्षेत्र है और बातचीत के लिए आतंकमुक्त माहौल बनाना होगा। आतंक पर कार्यवाही होने पर ही बातचीत करेंगे। सीमा हैदर मामले पर बागची ने कहा कि इसे एजेंसियां देख रही हैं। अंजू का मामला विदेश नीति से जुड़ा नहीं है। अंजू निजी तौर पर पाकिस्तान गई है।

बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत से बातचीत का ऑफर दिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि पिछले 75 सालों में हमने 3 जंग लड़ी, जिसने दोनों देशों को गरीबी, बेरोजगारी और तबाही के सिवा कुछ नहीं दिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि हम भारत से बातचीत को तैयार हैं। हम चाहते हैं कि भारत के साथ हमारी बातचीत हो। रिश्ते अच्छे हो। हम गरीबी में हैं, मुफलिसी में हैं। हम तीन युद्धों में बहुत कुछ खो चुके हैं और हमें गरीबी और तबाही के अलावा कुछ नहीं मिला है।

अरिहा शाह के मामले पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि हम इस मामले को उच्च प्राथमिकता दे रहे हैं... हमने इस संबंध में इस सप्ताह जर्मन राजदूत को बुलाया है। हमने जर्मन अधिकारियों से बच्ची को जल्द से जल्द वापस लाने के लिए कहा है। हम जर्मन अधिकारियों के संपर्क में हैं। हरियाणा की घटना पर अमेरिकी विदेश विभाग की टिप्पणी पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि आप हिंसा को रोकने और शांति बहाल करने के लिए स्थानीय अधिकारियों द्वारा उठाए गए कदमों से अवगत हैं। विदेश विभाग की जो टिप्पणियाँ हमने देखीं उनमें यह भी शामिल है उसी तरह...हम सामान्य स्थिति और शांति की वापसी देखना चाहेंगे।

मंडल बनाम कमंडल पर होगा 2024 का चुनाव! जाति सर्वेक्षण से किसका फायदा

नईदिल्ली। बिहार सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को अपने-अपने जिलों में जाति-आधारित सर्वेक्षण कराने की प्रक्रिया फिर से शुरू करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय पटना उच्च न्यायालय द्वारा सर्वेक्षण को चुनौती देने वाली सभी रिट याचिकाओं को खारिज करने के बाद आया है, जिससे इसके जारी रहने का रास्ता साफ हो गया है। बिहार में जाति सर्वेक्षण इस साल 7 जनवरी को शुरू हुआ, जिसे मई के अंत तक खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। हालाँकि, 4 मई को पटना उच्च न्यायालय के एक अंतरिम आदेश के बाद सर्वेक्षण को अस्थायी रूप से रोक दिया गया था, जिसने राज्य सरकार को पहले से एकत्र किए गए डेटा को संरक्षित करने का निर्देश दिया था। सर्वेक्षण फिर से शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

हालाँकि, जाति सर्वेक्षण से बिहार में मंडल बनाम कमंडल की राजनीति फिर से शुरू हो सकती है, जो 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य में बड़े पैमाने पर खेल कर सकती है। भाजपा और महागठबंधन दोनों ही राजनीतिक लाभ के लिए जाति गणना डेटा का उपयोग कर सकते हैं। जद (यू), राजद और भाजपा ने जाति-आधारित सर्वेक्षण पर अदालत के आदेश का स्वागत किया। इस फैसले से 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले राज्य में मंडल बनाम कमंडल (पिछड़ा बनाम अगड़ा) की राजनीति फिर से शुरू हो सकती है। 2024 चुनाव को लेकर भाजपा हिंदुत्व की राह पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। राम मंदिर मुद्दा और समान नागरिक संहिता उसके एजेंडे में है। भाजपा 2024 में राम मंदिर निर्माण को अपनी उपलब्धि बताएगी साथी साथ यूसीसी के मुद्दे पर हिंदुत्व वोट को एकजुट करने की कोशिश भी होगी। इसी को काटने की कोशिश की कवायद विपक्षी दलों की ओर से की जा रही है। विपक्षी दलों की ओर से जातीय जनगणना का एक बड़ा कार्ड खेला गया है। इसे 90 के दौर से भी जोड़ा जा सकता है। जब लालकृष्ण आडवाणी ने रथयात्रा वाला दांव खेला था लेकिन हिंदुत्व वाले प्रभाव को कम करने के लिए वीपी सिंह ने तब

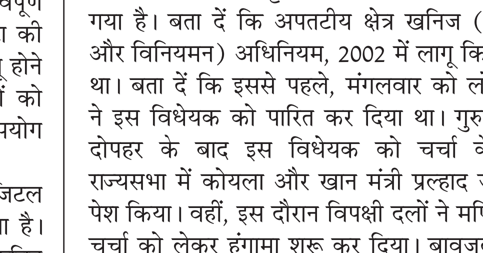

मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू कर दी थी। हालांकि, यह बात भी सच है कि कभी भाजपा को बनिया और ब्राह्मणों की पार्टी कही जाने वाली भाजपा नरेंद्र मोदी और अमित शाह के उदय के बाद ओबीसी और दलित वोट बैंक पर भी अपनी पकड़ मजबूत की है। इसलिए मौजूदा दौर 90 के दौर से अलग है।

बीजेपी ने पटना हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया। साथ ही साथ कई सवाल भी खड़े कर दिया। भाजपा ने कहा कि जातिगत सर्वे से हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सवाल यह है कि क्या प्रदेश में इससे कानून-व्यवस्था की स्थिति सुधरेगी? भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगेगा? इसके साथ ही भाजपा ने यह भी कहा है कि अगर सरकार की मंशा सही है तो रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाना चाहिए और गरीबों के लिए नीतियां बनाई जानी चाहिए। भाजपा का आरोप है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार की मंशा जातिगत सर्वे के जरिए समाज को बांटना है। भाजपा के सुशील मोदी ने यह भी दावा किया था कि हमारी सरकार रहने के दौरान ही इस पर फैसला हुआ था।

दरअसल, राजनीतिक दृष्टिकोण से बिहार काफी महत्वपूर्ण राज्य है वहां लोकसभा की 40 सीटें हैं। जातिगत सर्वेक्षण के बाद नीतीश कुमार का विपक्षी दलों के बीच कद बढ़ सकता है। लगातार गठबंधन बदलने वाले नीतीश कुमार की इमेज अस्थिर नेता की बन गई है। फिलहाल नीतीश कुमार की ओर से स्थिरता की कोशिश की जा रही है। ऐसे में जातिगत सर्वे उनके लिए संजीवनी साबित हो सकता है। नीतीश कुमार विपक्षी दलों के बीच कद बढ़ेगा। वह खुद ओबीसी समाज से आते हैं। ऐसे में उनके सहारे बाकी के विपक्षी नेता भाजपा को घेरने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अगर बिहार में यह पूरा हो जाता है तो ओडिशा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु जैसे कई राज्यों में जातिगत सर्वे का मामला सामने आ सकता है। संभावना है कि नीतीश अब राष्ट्रीय स्तर पर जाति जनगणना की मांग उठाएंगे और बीजेपी को घेरेंगे।

जातीय जनगणना को लेकर बिहार कहीं ना कहीं विपक्षी दलों का मार्गदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडिया गठबंधन के कई नेता लगातार जातीय गणना की मांग करते रहे हैं। खुद राहुल गांधी ने भी इसका समर्थन किया है। हालांकि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि यह सर्वेक्षण सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए है दावे चाहे जो भी हो रहे हो। भाजपा और महागठबंधन दोनों ही अपने उम्मीदवार इसी रिपोर्ट के आधार पर तय करेंगे। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इसका फायदा जनता को होता है या फिर राजनीतिक दल को।

प्रियंका ने जॉन सीना और एल्बा के साथ साइन की एक्शन फ़िल्म हेड्स ऑफ स्टेट सिटीडेल की रिलीज के बाद शुरू करेंगी शूटिंग

प्रियंका चोपड़ा जोनस इन दिनों भारत में अपनी आगामी ग्लोबल स्पाई सीरिज़ सिटाडेल के प्रमोशन टूर पर हैं । इसी बीच खबर आ रही है कि, प्रियंका चोपड़ा एक और एक्शन फ़िल्म में नज़र आने वाली है । अमेज़ॅन स्टूडियो के साथ जॉन सीना और इदरिस एल्बा स्टारर आगामी एक्शन फ़िल्म हेड्स ऑफ स्टेट में प्रियंका चोपड़ा एक्शन पैक्ड रोल में नज़र आने वाली हैं । जबकि फिल्म की कहानी अभी सामने आई नही है, हेड्स ऑफ स्टेट इल्या नैशुलर द्वारा निर्देशित, एयर फ़ोर्स वन मीट मिडनाइट रन होगा । प्राइम वीडियो पर 28 अप्रैल को सिटीडेल की स्ट्रीमिंग शुरू होने के कुछ ही दिनों बाद फिल्म मई में शुरू होगी ।

प्रियंका, जिनके पास 70 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय और हॉलीवुड फिल्में हैं और उनके रिज्यूमे पर 2 सीरीज हैं, आज भी हॉलीवुड में दक्षिण एशियाई प्रतिभाओं की सबसे अधिक मांग है । प्रियंका ने कई बाधाओं को तोड़ने और हॉलीवुड में अपने लिए जगह बनाने के लिए बहुत मेहनत की है। सिटाडेल के बाद प्रियंका आगमी फिल्म लव अगेन में दिखाई देंगी, जो 12 मई को रिलीज़ होगी । प्रियंका का प्रोडक्शन हाउस पर्पल पेबल पिक्चर्स, जो अमेज़ॅन स्टूडियोज के साथ एक फर्स्ट-लुक फिल्म और टीवी डील के तहत अस्यूम नथिंग- ए स्टोरी ऑफ़ पर आधारित एक सीमित सीरीज विकसित कर रहा है । अंतरंग हिंसा, तान्या सेल्वारत्नम का संस्मरण, जिसके कारण न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल एरिक श्नाइडरमैन का पतन हुआ । उन्होंने दुनिया भर में सभी संस्कृतियों को सामान्य करने वाली विविध कहानियों को बताने पर केंद्रित मूल कॉन्टेंट बनाने के लिए पैरामाउंट ग्लोबल के साथ भी सहयोग किया है ।

शाहरुख की पठान और सलमान की किसी का भाई किसी की जान में होगा कॉमन लिंक ; 21 अप्रैल को खुलेगा इसका राज

नायक पैदा नहीं होते बल्कि वह मौके की तलाश करते हैं । इस बयान से हम सभी सहमत होंगे । और ठीक वैसे ही, जब शाहरुख खान लोगों को खतरे से बचाते हैं, तो लोग उन्हें 'पठान' की उपाधि से सम्मानित करते हैं । दिलचस्प बात यह है कि इसी तरह की घटना सलमान खान की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्म किसी का भाई किसी की जान के साथ मनोरंजन प्रेमियों के लिए इंतजार कर रही है । क्योंकि सलमान खान 'भाईजान' के रूप में बड़े पर्दे पर दस्तक देंगे । पठान के इर्द-गिर्द रहस्य की हवा ने उनके चरित्र की छवि को और भी मजबूत बना दिया है और इसे एक शानदार सफल फिल्म बनाने के लिए इसमें बहुत बड़ा योगदान जोड़ा है । अब देखना दिलचस्प होगा कि कैसे किसी का भाई किसी की जान और पठान जैसी फिल्मों में एक कॉमन लिंक है । भाईजान और पठान की नायक उपाधियाँ उनके पात्रो द्वारा जीवन रक्षक अभिनय और जनता का आभार के कारण अर्जित की गई है । 'भाईजान' टाइटल के निर्माण की ओर ले जाने वाली घटनाओं का सटीक मोड़ क्या है, यह अपने आप में बड़ा रहस्य है जो 21 अप्रैल 2023 को सामने आएगा ! एक ऐसी तारीख जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार है । इस फिल्म को लेकर उत्साह चरम पर पहुंच गया है, जो इससे पहले कभी नहीं देखा गया । सलमा खान द्वारा निर्मित, सलमान खान फिल्म्स प्रोडक्शन किसी का भाई किसी की जान फरहाद सामजी द्वारा निर्देशित हैं। फिल्म में सलमान खान, वेंकटेश दग्गुबाती, पूजा हेगड़े, जगपति बाबू, भूमिका चावला, विजेंदर सिंह, अभिमन्यु सिंह, राघव जुयाल, सिद्धार्थ निगम, जस्सी गिल, शहनाज गिल, पलक तिवारी और विनाली भटनागर हैं। साथ ही सलमान खान की फिल्म के भी सारे एलिमेंट मौजूद है जैसे एक्शन, कॉमेडी, ड्रामा और रोमांस। ये फिल्म 21 अप्रैल 2023 को ईद पर रिलीज होने वाली है और यह दुनिया भर में ज़ी स्टूडियोज की रिलीज़ होगी ।

पुष्पा 2: द रूल के फ़र्स्ट लुक में अल्लू अर्जुन का दिखा 'फायर' अवतार

हाथ में चूड़ियों के साथ बंदूक़ और साड़ी पहने 'पुष्पाराज' के अनदेखे लुक ने बढ़ाई जिज्ञासा

पिछले कुछ दिनों से देश में अल्लू अर्जुन की पुष्पा का जादू देखने को मिल रहा है । दरअसल, निर्माताओं ने दर्शकों को एक वीडियो एसेट के साथ उत्साहित कर दिया है, जिसने पुष्पा की तलाश पर एक नई बातचीत को बढ़ावा दिया है और ऐसे में दर्शक यह सोचकर पागल हो रहे हैं कि उन्हें आगे और क्या देखने मिलने वाला है । फ़ाइनली अल्लू अर्जुन की फ़िल्म के मेकर्स ने पुष्पा 2: द रूल का दमदार पोस्टर रिलीज़ कर दिया है । लंबे इंतजार के बाद, वह दिन आ गया है, और पुष्पा 2 द रूल का पोस्टर आखिरकार जारी किया गया है जो असल में पुष्पा को फ्लावर नहीं फायर है इस बात को हर मायने में सही ठहराता है । पोस्टर में आइकन स्टार अल्लू अर्जुन उर्फ पुष्पराज को सबसे ऊपर दिखाया गया है । यह बहुत अलग और अनोखा, पोस्टर दिखने में असल में हटकर है और कुछ ऐसा है जिसे पहले कभी नहीं देखा गया है । साल की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक होने के नाते, पुष्पा 2 द रूल के निर्माताओं ने दर्शकों के बीच उत्साह पैदा करने का कोई मौका नहीं छोड़ा है। फिल्म जिस तरह का आक्रोश दर्शकों के बीच देखने के साथ देश भर में सुर्खियां बटोर रही है, ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि यह देश में इतिहास रचने के लिए तैयार है ।पुष्पा 2 द रूल सुकुमार द्वारा निर्देशित है, जिसमें अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और फहद फासिल अहम भूमिकाओं में हैं। फिल्म को मिथ्री मूवी मेकर्स ने प्रोड्यूस किया है।

अल्लू अर्जुनः 100 करोड़ का घर, सालाना इन्कम 32 करोड़

अल्लू अर्जुन भारतीय सिनेमा के सबसे ज्यादा फीस लेने वाले एक्टर्स में शुमार हैं। पुष्पा के बाद अब उनकी देशभर में तगड़ी फैन फॉलोइंग हो गई है। वो फिल्मों में कैसे आए, कौन-कौन सी मूवीज की, इस बारे में आप शायद जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि वो कितने करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं? हर महीने कितना कमाता हैं? एक मूवी के लिए कितना चार्ज करते हैं? क्या आप जानते हैं कि हैदराबाद में उनका 100 करोड़ का आलीशान घर भी है! जानकारी के मुताबिक, अल्लू अर्जुन की साल 2023 में कुल नेटवर्थ 370 करोड़ रुपये से ज्यादा है ।उनकी सालान इनकम 32 करोड़ रुपये से ज्यादा है। वो हर महीने 3 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाते हैं। उन्होंने कई हिट फिल्में दी हैं, जो बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर चुकी हैं। उन्होंने साल 1985 में बतौर चाइल्ड एक्टर अपने करियर की शुरुआत की थी। फिर साल 2003 में गंगोत्री से डेब्यू किया था। अल्लू अर्जुन की ज्यादातर कमाई फिल्मों और ब्रांड एंडोर्समेंट से होती है। हैदरबादा में स्थित 300 जुबली नाइट क्लब भी उनका है। वो एक फिल्म के लिए करीब 10 करोड़ रुपये चार्ज करते हैं। वहीं, ब्रांड एंडोर्समेंट की बात करें तो उसके लिए करीब 3 करोड़ रुपये वसूलते हैं ।Allu Arjun के पास महंगी कारों का भी कलेक्शन है। उनके पास करीब ढाई करोड़ की रेंज रोवर वोग है। उनके पास 7 करोड़ की वैनिटी वैन है।

वरुण पत्नी नताशा के साथ क्लीनिक के बाहर हुए स्पॉट, लोगों ने पूछा- गुड न्यूज है क्या

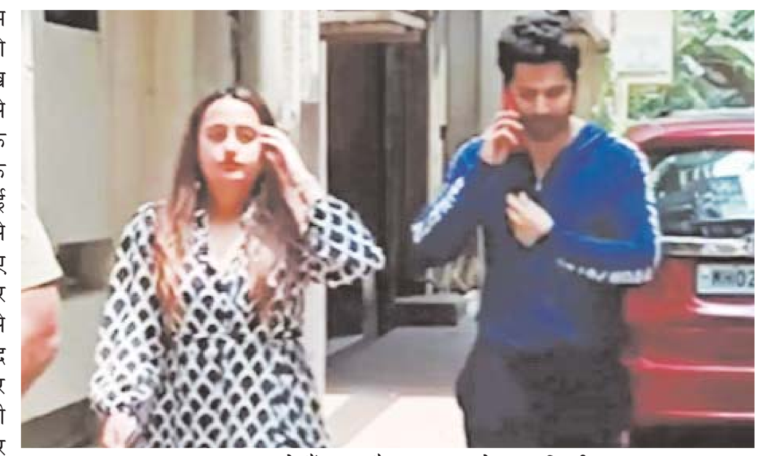

बीते दिनों फिल्म जगत में कई कपल्स को माता-पिता बनने का सुख मिला. रणबीर आलिया से लेकर प्रियंका चोपड़ा-निक जोनस तक पेरेंट्स बन चुके हैं. वहीं बॉलीवुड में कई कपल्स ऐसे भी हैं, जिनसे गुड न्यूज सुनने के लिए उनके फैंस बेताब हैं और वरुण धवन भी उनमें से एक हैं. हालांकि अब शायद वरुण धवन के घर खुशखबरी सुनाई दे सकती है. हाल में वरुण धवन और उनकी पत्नी नताशा को एक क्लीनिक के बाहर स्पॉट किया गया, जिसके बाद इस तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं.

इंस्टाग्राम पर सामने आए वीडियो में वरुण धवन और नताशा एक क्लिनिक के बाहर आते नजर आ रहे हैं. इस दौरान वरुण फोन पर किसी से बात करते नजर आ रहे हैं, तो वहीं नताशा कैजुअल लुक में दिखाई दे रही हैं. हालांकि वरुण ने मीडिया से बातचीत में कुछ भी नहीं कहा, लेकिन अफवाहों का बाजार गर्म हो गया है. लुक्स की बात करें तो वरुण ब्लू कलर की टी शर्ट के साथ ब्लैक पैंट पहने दिख रहे हैं, तो वहीं नताशा ने ब्लैक एंड व्हाइट कलर की शॉर्ट ड्रेस पहन रखी है.

बता दें कि नताशा और वरुण धवन की शादी जनवरी 2021 में हुई थी. उनकी शादी को दो साल से अधिक का समय गुजर चुका है. ऐसे में अब परिवार वालों के साथ ही वरुण के फैंस को भी गुड न्यूज का इंतजार है. ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इन अटकलों में कितनी सच्चाई है, लेकिन वरुण के फैंस अभी से खुशी मनाते नजर आ रहे हैं. एक फैन ने लिखा, बहुत खुशी की बात है. वहीं एक फैन ने लिखा कि भाई कोई बीमार भी हो सकता है, उनको प्राइवेसी दो.

[भविष्यफल]

मेष

आज का दिन व्यस्त हो सकता है। दूसरों के कारण मानसिक उलझनों से व बाहर के खाने से बचें। यदि नौकरी की तलाश में हैं तो आज आपको सुखद सूचना मिल सकती है लेकिन अति लोभ व नकारात्मक विचारों से ऊपर उठें।

वृष

आपका प्रयास आज रंग लाएगा। किसी तरह का शुभ समाचार मिलेगा। नए अवसर जीवन में परिवर्तन लाने का काम करेंगे। अपनों का सहयोग मिलेगा, मित्र भी साथ देंगे।

मिथुन

आपको धन लाभ होने की संभावना है। मनोकामना की पूर्ति का दिन है। आज दिन शुभ रहेगा। आज का दिन मंगलमय रहेगा। अचानक लाभ से मन प्रसन्न रहेगा।

कर्क

विद्यार्थी वर्ग के लिए समय अनुकूल है। कर्क राशि के जातक आज ऊर्जावान रहेगे। भागीदारी में लाभ कम होगा। आपके अपने मधुर व्यवहार करें इसलिए लिए जागरूक रहना सही है।

सिंह

आपका आज का दिन मिश्रित रहेगा। कार्यक्षेत्र में सामंजस्य बनाए रखने की आवश्यकता है। कोई समाचार मिलने के योग है। समय निकालकर आराम करें। सोच-समझकर यात्रा एवं कार्य-व्यवहार

कन्या

आज आशानुकूल लाभ होने की संभावना है। आपको अधिकारी वर्ग से सहायता मिलेगी। विरोधी निर्बल रहेंगे। आज आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। कार्यों में सफलता प्राप्त होगी।

तुला

आज प्रयास से सभी कार्य बनने की संभावना बनेगी। जिससे आपको धन लाभ होगा। रुका हुआ धन वापस मिलने की संभावना है।

वृश्चिक

आज कार्य बनने की खुशी होगी। बनाए गए नए सम्पर्कों से लाभ होने की संभावना है। सफलता प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। जोखिमपूर्ण कार्यों में रुचि बढ़ेगी।

धनु

आज व्यस्तता बनी रहेगी। फिर भी कार्यों की गति धीमी रहेगी। इरादों में मजबूती उन्नति का मार्ग प्रशस्त करेगी। नए कार्य में व्यस्तता बढ़ेगी। किसी संबंधी अथवा खुद की अस्वस्थता से परेशान न हों सब सही रहेगा।

मकर

आज की गई यात्रा सुखद रहेगी। किसी कार्य संबंधी मामले में उन्नति का समाचार मिलेगा। पुरस्कार अथवा भेंट मिलने की खुशी होगी।

कुंभ

आज आत्मविश्वास में बढोतरी होगी। कार्यक्षेत्र की जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। सुख-समृद्धि के साथ-साथ खर्च में भी वृद्धि होगी। गुप्त शत्रु तंग कर सकते हैं, सावधान रहें।

मीन

भाग्य का साथ आज सफलता दिलाएगा। विरोधी परास्त होंगे। यश-कीर्ति में वृद्धि होगी। व्यवहार कुशलता और शांत रहकर कार्य बना लें। उन्नति का अवसर मिलेगा।

द न्यूकमर्स पहल के साथ सूरज और जैन देंगे नए टैलेंट को मौका ; बॉलीवुड में लॉन्च करेंगे नए चेहरे

राजकुमार हिरानी के बाद, प्रसिद्ध फिल्म निर्माता सूरज आर बड़जात्या ने राजश्री की आगामी परियोजना में नए चेहरों को लॉन्च करने के लिए न्यूकमर्स इनिशिएटिव के साथ हाथ मिलाया है। फ़िल्म ऊंचाई की अपार सफलता के बाद अब राजश्री प्रोडक्शन और राजश्री फ़िल्मस के चाहनेवालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी हैं । टैलेंटेड और नए प्रतिभाशाली कलाकारों और न्यूकमर्स इनिशिएटिव के साथ राजश्री नए प्रतिभावान लोगों को अपनी फिल्मों में हुनर दिखाने का अद्भुत मौका देने वाले हैं । फिल्म को जियो स्टूडियो और महावीर जैन के सहयोग से राजश्री प्रोडक्शंस द्वारा बनाया जाएगा ।

द न्यूकमर्स पहल एक ऐसा मंच है जो पूरे भारत के अभिनेताओं, लेखकों, निर्देशकों, संगीतकारों और तकनीशियनों जैसी नई प्रतिभाओं को अवसर प्रदान करता है । देश के 23 से अधिक प्रमुख फिल्म निर्माता नई प्रतिभाओं को लॉन्च करने, सलाह देने और उनका समर्थन करने की इस असाधारण पहल के साथ आए हैं । उंचाई फिल्म पर उनकी सफल साझेदारी के बाद महावीर जैन और राजश्री प्रोडक्शंस के बीच यह दूसरा सहयोग है । यह रोमांचक घोषणा हाल ही आयी जब राजकुमार हिरानी फिल्म्स, महावीर जैन और जियो स्टूडियोज की ज्योति देशपांडे ने न्यूकमर्स पहल के तहत एक फीचर फिल्म के माध्यम से दो नए चेहरों को लॉन्च करने के लिए हाथ मिलाया है । सहयोग का उद्देश्य फिल्म उद्योग के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना और नई प्रतिभाओं के विकास को प्रोत्साहित करना है ।

सलमान खान ने यंग ऐक्टर्स को दी चुनौती, कहा- 'मैं, शाहरुख, आमिर, अक्षय और अजय अभी रिटायर नहीं हो रहे, हम 5 इन सब को थका देंगे'

बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान इन दिनों ईद पर रिलीज़ होने वाली फ़िल्म किसी का भाई किसी की जान की रिलीज़ की तैयारी में जुटे हुए हैं । हाल ही में सलमान खान लंबे वक्त के बाद मीडिया से मुख़ातिब हुए और उनके सवालों के दिलचस्प जवाब दिए । फिल्मफेयर अवॉर्ड्स से पहले हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान खान शामिल हुए जहां उन्होंने जान से मारने की धमकी, बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होती फ़िल्में, ओटीटी के वल्गर कंटेंट समेत कई विषयों पर खुलकर बात की । इसी के साथ सलमान खान ने नए स्टार्स के साथ कॉम्पिटिशन पर अपनी राय रखी और नए स्टार्स को खुली चुनौती भी दे दी की वो आसानी से रिटायर नहीं होंगे । सलमान खान ने यंग ऐक्टर्स को दी चुनौती, कहा- मैं, शाहरुख खान, आमिर खान, अक्षय कुमार और अजय देवगन अभी रिटायर नहीं हो रहे, हम 5 इन सब को थका देंगे ; बताई बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होती फ़िल्मों की वजह

सलमान खान नहीं होंगे अभी रिटायर- फिल्मफेयर अवॉर्ड्स से पहले हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए सलमान ने फिल्म इंडस्ट्री में नए कलाकारों को लेकर कहा कि वो सभी मेहनती हैं, लेकिन हम 5, शाहरुख खान, आमिर खान, मैं, अक्षय कुमार और अजय देवगन उन्हें थका देंगे ।

सलमान ने कहा कि, युवा कलाकार प्रतिभाशाली, केंद्रित और मेहनती हैं, लेकिन वो उनके सामने इतनी आसानी से हार नहीं मान रहे हैं । मैं, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन और आमिर खान उनके पैसों पर दांव लगाएंगे । हम जल्द ही रिटायर नहीं हो रहे हैं । हमारी फिल्में भी चलती हैं और इसलिए हम अपनी फीस बढ़ाते हैं । वे तब भी अपनी फीस बढ़ा लेते हैं जब उनकी फिल्में नहीं चल रही होती हैं । इसके अलावा सलमान ने बॉक्स ऑफिस पर पिट रही फिल्मों को लेकर कहा, हमारी हिंदी फिल्में है जो चल नहीं रही। खराब फिल्में बनाओगे तो कैसे चलेगी यार । सिंपल है । हर किसी के दिमाग में होता है कि हम शोले, मुगल-ए-आजम, हम आपके हैं कौन, दिलवाले जैसी फिल्में बना रहे हैं । लेकिन वो वैसी बन नहीं पाती । आजकल के कुछ डायरेक्टर्स के साथ मैंने बातचीत की ।

हेरा फेरी 4 को ब्लॉकबस्टर होने के लिए सुनील ने बताई ये ज़रूरी चीजें, कहा- इसे हेरा फेरी 1 के लेवल का होना होगा तभी लोग इसे पसंद करेंगे

लोगों की भारी डिमांड पर फ़ाइनली, बॉलीवुड की कल्ट क्लासिक कॉमेडी फ़िल्म हेरा फ़ेरी फ़्रैंचाइजी की तीसरी किश्त, हेरा फेरी 4 की तैयारी शुरू हो चुकी है । हेरा फेरी फ़्रैंचाइजी की तीसरी किश्त एक बार फ़िर अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल के साथ आ रही है लेकिन इस बार फ़िल्म में एक नया एडिशन हुआ है और वो है संजय दत्त का । इसके अलावा मेकर्स ने फ़िल्म का नाम हेरा फेरी 3 न रखकर हेरा फ़ेरी 4 रखा है और इसके पीछे फ़िल्म की कहानी है जो फ़िल्म देखने के बाद ही पता चलेगी । हाल ही में जब हेरा फेरी एक्टर सुनील शेट्टी, जो इन दिनों अपनी आगामी एक्शन थ्रिलर वेब सीरिज़ हंटर के प्रमोशन में बिजी हैं, ने बॉलीवुड हंगामा के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की तो उन्होंने बताया की हेरा फेरी 4 को हरा फेरी 1 के लेवल का अच्छा होना पड़ेगा, नहीं तो कोई भी इस फ़्रैचाइजी को पसंद नहीं करेगा । इसी के साथ सुनील शेट्टी ने वो फ़ैक्ट्स बताए जो हेरा फेरी 4 को ब्लॉकबस्टर फ़िल्म बना सकते हैं ।

बॉलीवुड हंगामा के इंटरव्यू के दौरान जब सुनील से जब हेरा फेरी के बारें में पूछा की क्या उन्हें फ़िल्म बनाते वक्त भी उतना ही मज़ा आया जितना हमें देखते हुए आता है तो इसके जवाब में सुनील ने कहा, हाँ, हेरा फेरी करते समय हम बहुत मस्ती किया करते थे । हमें इस बात की हमेशा चिंता सताती थी क्या हम उस फ़िल्म के लेवल का परफ़ॉर्म कर पाएँगे, क्योंकि वह एक कॉमेडी फ़िल्म है जबकि मैं और अक्षय कुमार एक्शन हीरो थे, इसलिए हमें डर था कहीं हम फ़िल्म की कहानी और उसके लेवल को जस्टिफ़ाई नहीं कर पाए तो । लेकिन फ़िल्म में परेश जी और ओम पुरी जैसे दिग्गज अभिनेता थे फिर कैसे कोई अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर सकता । हमारे साथ एक से बढ़ाकर एक आर्टिस्ट थे ।

हेरा फेरी 4 के बारें में सुनील ने आगे कहा, हेरा फेरी एक आइकॉनिक फ़िल्म है और मुझे लगता है कि हेरा फेरी 1 सबसे बेहतरीन फ़िल्म में से एक है । फिर हेरा फेरी, इसलिए चली क्योंकि उसके पास पहले रिलीज़ हुई हेरा फेरी की कल्ट फ़ैन फ़ॉलोइंग थी । और अब, हम जबकि हेरा फेरी 4 कर रहे हैं तो, इसे हेरा फेरी 1

जितना ही अच्छा होना होगा, नहीं तो इसे कोई पसंद नहीं करेगा और हर कोई इस फ़्रैचाइजी को कोसेगा । हेरा फेरी 4 को पहली हेरा फेरी के लेवल की बनाने के लिए इमोशन बहुत ज़रूरी है, रियल होना बहुत ज़रूरी है और सबसे ज़रूरी चीज़ कि हर किसी को अपना बेहतर देना होगा न कि एक दूसरे की स्पेस में जाकर फ़ाइट करना ।

वर्क फ़्रंट की बात करें तो, सुनील जल्द ही वेब सीरीज हंटर- टूटेगा नहीं तोड़ेगा में एक बार फिर एक्शन अवतार में नज़र आएँगे । इसकी कहानी सुनील शेट्टी को एसीपी विक्रम सिन्हा के किरदार में मुंबई के अपराध की दुनिया की अंधेरी गलियों में ले जाती है । एक गुमशुदा महिला को खोजने की कोशिश उसे अपने अतीत और आने वाले कल के बीच उलझा देता है ।

संक्षिप्त समाचार

रमन सिंह दिल्ली एम्स में हुए भर्ती स्वास्थ ठीक

रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री तथा भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डा. रमन सिंह फिलहाल एहतियात के तौर पर दिल्ली एम्स में भर्ती है जहां उनकी हालत ठीक है। उक्त जानकारी रमन सिंह ट्वीटर के माध्यम से जानकारी साझा करते हुए लिखा कि - पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में हूँ, आज रूटीन चेकअप के लिए एआईआईएमएस जाना हुआ जहाँ चिकित्सकों के परामर्श से एहतियात के तौर पर भर्ती हुआ हूँ। फ़िलहाल स्वास्थ्य ठीक है, मानसून के बीच आप सब भी बारिश में पूरी एहतियात बरतें और स्वस्थ रहें।

कौशिक ने किया जूनियर डॉक्टर्स का समर्थन

रायपुर। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धरमलाल कौशिक ने मानदेय में वृद्धि करने की मांग को लेकर जूनियर डॉक्टरों द्वारा किये जा रहे अनिश्चितकालीन हड़ताल का समर्थन करते हुए प्रदेश सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि जूनियर डॉक्टर की हड़ताल करना वाजिब है क्योंकि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने अपने किए वादों के अनुसार अभी तक उनकी मांगो को पुरा नहीं कर पाई है उन्होंने कहा कि विभिन्न कर्मचारी संगठनों की हड़ताल में चले जाने से प्रदेश की जनता को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है किन्तु कांग्रेस सरकार इनके मांगो को पुरा करना छोड़ अपने सारे वादों से मुकर रही है और इन पर दमनकारी नीति चला रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार जिन घोषणा पत्र एवं झूठे वादों को लेकर सत्ता में आई थी आज उन्हीं बातों से मुकर चुकी है। कांग्रेस ने अपने जन घोषणापत्र में कहा था कि सभी अनियमित-संविदा कर्मचारी साथियों को कांग्रेस की सरकार बनने के 10 दिनों के भीतर सबका नियमितिकरण कर दिया जाएगा। लेकिन पौने पांच साल गुजर जाने के बाद भी वादा पुरा नहीं कर पाई है और वादों को पुरा करने के बजाय अपनी मांगो को लेकर हड़ताल कर रहे संविदा कर्मचारियों एवं स्वास्थ्य कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त कर रही है।

पांच डिप्टी कलेक्टरों का तबादला

रायपुर। राज्य शासन की ओर से जारी आदेश के मुताबिक राज्य प्रशासनिक सेवा के पांच अधिकारियों का तबादला किया गया है। श्री कौशल तेंदुलकर डिप्टी कलेक्टर बिलासपुर से प्रोजेक्ट डायरेक्टर जि.प.जीपीएम,उत्तम प्रसाद रजक डिप्टी कलेक्टर सूरजपुर से रायपुर,पुष्पेन्द्र शर्मा संयुक्त कलेक्टर जीपीएम से रायपुर,मनोज खांडे डिप्टी कलेक्टर कोरबा से महासमुंद,श्रीकांत वर्मा डिप्टी कलेक्टर बिलासपुर से कोरबा स्थानांतरित किए गए हैं। इसके अलावा विभागीय समसंख्यक आदेश के मुताबिक कुछ संशोधन हुए है जिसके मुताबिक चंद्रकांत कौशिक अपर कलेक्टर दंतेवाड़ा को बालोद,डा.कल्पना ध्रुव डिप्टी कलेक्टर बीजापुर को दंतेवाड़ा,मुकेश कुमार कोठारी डिप्टी कलेक्टर रायपुर को मुख्य कार्यपालन अधिकारी पाटन दुर्ग,कु.सीमा पात्र डिप्टी कलेक्टर महासमुंद को कोरबा में पदस्थ किया जाता है । तत्काल सभी को नवीन पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना है।

राष्ट्रपति मुर्मु ने राज्यपाल को दी जन्मदिन की शुभकामनाएं

रायपुर। राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन को आज उनके जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु, केन्द्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल, विधानसभा अध्यक्ष श्री चरणदास महंत ने उनके स्वस्थ और सुदीर्घ जीवन के लिए शुभकामनाएं दी। साथ ही राज्यपाल के सचिव श्री अमृत खलखो, विधिक सलाहकार श्री राजेश श्रीवास्तव, रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी सहित राजभवन सचिवालय के अधिकारी कर्मचारी, विश्वविद्यालयों के कुलपतियों एवं ब्रम्हकुमारी बहनें, परिजनों सहित गणमान्य नागरिकों ने भी राज्यपाल हरिचंदन को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। राज्यपाल को सोशल मीडिया के जरिये बिहार के राज्यपाल राजेन्द्र अरलेकर, केन्द्रीय मंत्री द्वय अर्जुन मुंडा, श्रीमती रेणुका सिंह, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, डॉ. शिवकुमार डहरिया, डॉ. रमन सिंह, पूर्व नेता प्रतिपक्ष श्री धरमलाल कौशिक, मध्यप्रदेश के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत सहित छत्तीसगढ़ एवं अन्य प्रदेशों के जनप्रतिनिधिगण एवं आम नागरिकों ने भी दीर्घायु जीवन के लिए शुभकामनाएं दी।

एकलव्य के विद्यार्थियों को परीक्षाओं की तैयारी के लिए मिलेगी कोचिंग

मंत्री श्री मोहन मरकाम की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय आवासीय एवं आश्रम संस्थान समिति 'संचालक मण्डल' की बैठक

रायपुर। प्रदेश में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में कक्षा 12वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को जेईई और नीट प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए ऑनलाईन कोचिंग की सुविधा दी जाएगी। आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास मंत्री श्री मोहन मरकाम की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय में आयोजित छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं आश्रम संस्थान समिति 'संचालक मण्डल' की बैठक में इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। बैठक में एकलव्य विद्यालय के प्राचार्य एवं स्टाफ का राज्य समिति के अनुमोदन से ही स्थानांतरण करने पर सहमति दी गई।

मंत्री श्री मोहन मरकाम ने एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बच्चों की पढ़ाई से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। यदि विद्यालय विषय-विशेषज्ञ पर्याप्त संख्या में नहीं है, तो नियमानुसार अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था की जाए। इन स्कूलों का परीक्षा परिणाम बेहतर करने के लिए शिक्षकों की क्षमता विकास के लिए प्रशिक्षण दिया जाए और समय-समय पर विद्यालयों के अध्ययन-अध्यापन की समीक्षा भी की जाए।

बैठक में बताया गया कि शिक्षण सत्र 2023-24 में 25 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में कक्षा 12वीं कक्षाएं संचालित है। कक्षा 12वीं में अध्ययनरत 1474 विद्यार्थियों में से कक्षा 12वीं में जीव-विज्ञान के लगभग 982 विद्यार्थियों और गणित संकाय के लगभग 492 अध्ययनरत विद्यार्थियों को जेईई और नीट की प्रवेश परीक्षा की तैयारियों हेतु ऐसे विद्यालय जहां हाई स्पीड इंटरनेट स्थापित है, वहां ऑनलाईन कोचिंग दी जाएगी। वर्तमान में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में 22860 विद्यार्थियों के लिए गणवेश की आवश्यकता है। शाला गणवेश के लिए केव्हीआईसी के स्थान पर राज्य के स्थानीय बुनकरों को प्रोत्साहन देने के लिए हाथकरघा विकास विपणन संघ मर्यादित रायपुर को कार्यादेश दिए जाने के प्रस्ताव को कार्योत्तर अनुमोदन दिया गया। इसके साथ ही एकलव्य विद्यालय के विद्यार्थियों को शिक्षण सत्र 2023-24 में प्रयास आवासीय विद्यालय में प्रवेश दिए जाने का भी अनुमोदन किया गया।

सचिव श्री डी.डी. सिंह ने आदिम जाति कल्याण, आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान संचालन के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति ने नई दिल्ली से केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत प्राप्त राशि से यह योजना संचालित है। इसका मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा उपलब्ध कराकर सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के समकक्ष लाना, उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत कर प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हो इसके लिए, कक्षा 6वीं से 12वीं तक एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय प्रारंभ किए गए हैं। वर्ष 2018-19 से इन विद्यालयों में सीबीएसई के पाठ्यक्रम अनुसार अध्यापन कराया जा रहा है।

आयुक्त श्रीमती शम्मी आबिदी ने बताया कि शिक्षण सत्र 2023-24 में प्रदेश में संचालित कुल 74 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में 22 हजार 860 सीट स्वीकृत हैं, जिस पर प्रवेश की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। बैठक में एकलव्य विद्यालयों के भवन निर्माण के लिए वनभूमि का चिन्हांकन एवं आबंटन की स्थिति की समीक्षा की गई। साथ ही नवीन एकलव्य विद्यालय के लिए चिन्हांकित की गई वन भूमि की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली गई।एकलव्य विद्यालय में एनआईसी-एसआई के माध्यम से आउटसोर्स से लेखापाल रखे जाने की समीक्षा में बताया गया कि वर्तमान में आउटसोर्स के माध्यम से लेखापाल रखे जाने के लिए प्रस्तावित 74 पदों के विरूद्ध 24 लेखापाल रखे गए हैं, शेष के संबंध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इसके अलावा एनआईसी-एसआई मंत्रालय रायपुर से मल्टी टास्किंग स्टाफ रखने का अनुमोदन किया गया।

छत्तीसगढ़ की महिलाएं पुरुषों पर भारी पलट सकती हैं सूबे की सियासी बाजी

रायपुर। छत्तीसगढ़ में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाता की अपेक्षा अधिक है। यहां प्रति हजार पर 1003 महिला मतदाता हैं। इस बात की जानकारी मंगलवार को छत्तीसगढ़ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने प्रेस वार्ता के दौरान दी। कंगाले ने इस दौरान कई जानकारियां दी। जानकारी के मुताबिक वोटर आईडी को आधार से लिंक कराना जरूरी नहीं है। यह स्वैच्छिक है हालांकि वर्तमान में लगभग 90 फीसद वोटर आईडी आधार से लिंक हो चुके हैं।

बता दें कि छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या 3 करोड़ 3 लाख 80 हजार है। कुल मतदाताओं की संख्या एक करोड़ 96 लाख 40 हजार 430 है, जो कि आबादी का लगभग 64.65 फीसद है। इनमें पुरुष मतदाता की संख्या 98 लाख 6 हजार 906 है, जबकि महिला मतदाता 98 लाख 32 हजार 557 है। वहीं, थर्ड जेंडर 767 हैं। बात अगर रेशियो की करें तो छत्तीसगढ़ में पुरुषों से अधिक महिला मतदाता है। प्रति हजार पर 1003 महिला मतदाता हैं।

छत्तीसगढ़ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक प्रदेश में मतदान केंद्रों की संख्या 24 हजार 109 है। दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 1 लाख 47 हजार 364 है। स्पेशल समरी रिवीजन के प्रथम चरण के दौरान अंतिम प्रकाशन 5 जनवरी 2023 को हुआ थी। इसमें 18-19 साल के युवा मतदाताओं की संख्या 3 लाख 9 हजार 464 थी। शुरुआती प्रकाशन 2 जून 2023 को हुई थी। इसमें 18-19 साल के युवा मतदाताओं की संख्या कुल 4 लाख 25 हजार 600 हो गई थी। वरिष्ठ नागरिक मतदाता (80+) की संख्या 2 लाख 2 हजार 740 है। सेवा कार्मिकों की संख्या 19 हजार 854 है

एक से अधिक पहचान पत्र के अलावा मृत मतदाताओं के नाम पर वोटिंग को लेकर अलग प्रोटोकॉल रहेगा। ऐसे मतदाताओं की पहचान की जाएगी। साथ ही कुछ राजनीतिक दलों की ओर से आय व्यय की जानकारी ना देने वालों के मामले में केंद्रीय निर्वाचन आयोग को जानकारी दी जाती है। जानकारी के बाद आयोग कार्रवाई करता है। छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची के दूसरे ऑब्जर्वेशन का काम 2 अगस्त से शुरू हो चुका है। अधिक से अधिक लोगों को मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। लोगों से मतदान के लिए अपील की जा रही है। छत्तीसगढ़ में प्री अरूव मतदान केन्द्रों की संख्या 23907 है। इनमें नये मतदान केन्द्रों की संख्या 204 है। जबकि दो ऐसे मतदान केन्द्र हैं, जो कि खत्म हो चुके हैं। प्रदेश के 970 मतदान केन्द्रों के भवन परिवर्तन हुए हैं।

चुनाव के लिए कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की घोषणा, माकन बने छत्तीसगढ़ के चेयरमैन

रायपुर। कांग्रेस पूरी तरह से चुनावी मोड में है। इसी क्रम में कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के लिए स्क्रीनिंग कमेटी की घोषणा की है। जिन राज्यों चुनाव होने हैं वहां के लिए स्क्रीनिंग कमेटी का ऐलान किया गया है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता अजय माकन को छत्तीसगढ़ स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। वहीं डॉ. एल हनुमैंथया और नेटा डिसूजा को मेंबर बनाया गया है।

इसके साथ ही छत्तीसगढ़ से पीसीसी चीफ दीपक बैज, सीएम भूपेश बघेल, कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी और प्रदेश प्रभारी कुमारी सेलजा, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव और कांग्रेस के सचिवों को पदेन सदस्य बनाया गया है।

जिन-जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने होते हैं। वहां के लिए कांग्रेस एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाती है। ये कमेटी ही प्रत्याशियों के चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कौन उम्मीदवार होगा और कौन नहीं है, ये कमेटी ही निर्धारित करती है। इस कमेटी में हमेशा बाहर के ही नेताओं को प्राथमिकता दी जाती है ताकि पक्षपात और भाई भतीजावाद की बात न हो। कमेटी सभी विधानसभा क्षेत्रों से तीन-तीन नामों की लिस्ट, सर्वे सूची, जातीय समीकरण के आधार पर तैयार कर करके संगठन के केन्द्रीय चुनाव समिति को भेजती है। इसके बाद यहां से अंतिम सूची पर मुहर लगती है।

इसके पहले ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए थे

इसके पहले हाल ही में कांग्रेस आलाकमान ने पांचों राज्यों में ऑब्जर्वर नियुक्त किए थे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह और मीनाक्षी नटराजन को जिम्मेदारी दी गई है। विधानसभा चुनाव के लिए सीनियर ऑब्जर्वर प्रीतम सिंह को विधानसभा चुनाव के लिए बनाया गया है। मीनाक्षी नटराजन को ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है।

पदस्थापना में भ्रष्टचार, सरकार बताएं अधिकारियों को किन लोगों का संरक्षण था : नेता प्रतिपक्ष

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा है कि शिक्षा विभाग में पदस्थापनाओं को लेकर हुई कार्रवाई के बाद प्रदेश में कांग्रेस सरकार के राज का एक और नया प्रमाणित भ्रष्टाचार सामने आया है। अब तक इस मामले में दोषी पाए गए अधिकारियों पर हुई कार्रवाई को अपर्याप्त बताते हुए श्री चंदेल ने कहा कि यह पता लगाया जाए कि इन अधिकारियों को किन लोगों का संरक्षण था? क्या उन लोगों का पता लगाकर प्रदेश सरकार उन लोगों पर कार्रवाई करने का साहस दिखाएगी, जिनके संरक्षण में इस भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया।

चंदेल ने कहा कि पदस्थापना आदेश में संशोधन करने के इस बेहद गंभीर मामले के परिप्रेक्ष्य में अब तक हुई तमाम पदस्थापनाओं की पूरी जाँच कराई जाए और यह भी पता लगाया जाए कि इस पूरे भ्रष्टाचार में कितने रुपयों का लेन-देन हुआ है? प्रदेश सरकार इस मामले के सारे तथ्यों को सार्वजनिक करे। श्री चंदेल ने कहा कि यह बेहद गंभीर और प्रदेश के शर्मनाक विषय है कि शिक्षा विभाग की पदस्थापना में लेन-देन, कमीशन, करप्शन को लेकर करीब एक दर्जन से अधिकारियों के निलंबन की घोषणा की गई है।

उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई के बाद अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि भ्रष्टाचार का यह खेल पता नहीं, कितने सालों से चल रहा है? कौन-कौन इसमें शामिल हैं? भाजपा प्रदेश सरकार से मांग करती है कि जितने भी प्रकरण इस तरह के प्रकाश में आए हैं, जितनी भी पदस्थापनाएँ कांग्रेस शासनकाल के इन पौने पाँच सालों में हुई हैं, सबकी उच्चस्तरीय और निष्पक्ष जाँच कराई जाए। श्री चंदेल ने कहा कि जिन लोगों को भ्रष्टाचार के इस मामले में दोषी पाया जाए, उनके खिलाफ सख्त-से-सख्त कार्रवाई की जाए।

भाजपा का घोषणा पत्र अभियान शुरु

भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले गुरुवार को घोषणा पत्र समिति अभियान का शुभारंभ किया। इसके लिए चुनाव अभियान समिति ने सभी जिलों में सुझाव प्राप्त करने के लिए भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर से घोषणा पत्र सुझाव पेटियों का पार्टी कार्यकर्ताओं को वितरित किया। इसके अलावा चुनाव अभियान समिति ने व्हाट्सएप नंबर 9584656500 भी जारी किया है। इस अवसर पर ओम माथुर, नितिन नबीन, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व अध्यक्ष विक्रम उसेंडी ,घोषणा पत्र समिति के संयोजक विजय बघेल, गौरीशंकर अग्रवाल, रामविचार नेताम, नारायण चंदेल, बृजमोहन अग्रवाल, पुन्नू लाल मोहिले, पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल, राजेश मूणत, केदार कश्यप, विजय शर्मा, पूर्व मंत्री महेश गागड़ा उपस्थित थे।

संविदा कर्मचारी संघ के प्रतिनिधिमंडल ने सीएम को हड़ताल वापस लिए जाने की सूचना दी

■ संविदा कर्मचारियों के वेतन में 27 प्रतिशत वृद्धि किए जाने पर मुख्यमंत्री का जताया आभार

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल से यहां उनके निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री को प्रतिनिधिमंडल ने संविदा कर्मचारियों के वेतन में 27 प्रतिशत वृद्धि किए जाने के लिए आभार जताया और उन्हें विगत 3 जुलाई से जारी अनिश्चितकालीन हड़ताल को वापस लिए जाने की सूचना दी।

मुख्यमंत्री को प्रतिनिधिमण्डल ने बताया कि पहली बार संविदा कर्मचारियों के वेतन में 27 प्रतिशत वृद्धि की गयी है। इस फैसले का लाभ छत्तीसगढ़ के समस्त विभागों एवं योजना में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को मिलेगा। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लगातार कर्मचारियों के हित में अनेक फैसले लिए जा रहे हैं। जहां एक ओर केंद्र के समान डीए और गृहभाड़ा सहित कई घोषणाएं कर्मचारियों के हित में की गई, वहीं अनुपूरक बजट में सबसे अधिक 27 प्रतिशत वेतन वृद्धि का निर्णय संविदा कर्मचारियों के लिए लिया गया है। मुख्यमंत्री को प्रतिनिधिमंडल ने अपनी अन्य मांगों के विषय में ज्ञापन सौंपा।

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने संविदाकर्मियों को उनके ज्ञापन पर हरसंभव कार्यवाही किये जाने आश्वस्त किया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी संघ से प्रदेश अध्यक्ष श्री कौशलेश तिवारी सहित सर्वश्री हेमंत सिन्हा, अशोक कुर्रे, संजय सोनी, विजय यादव, श्रीकांत लास्कर, सुदर्शन मंडल, ताकेश्वर साहू, टीकमचंद कौशिक, गोपालगिरी गोस्वामी, सूरज सिंह ठाकुर, टेकलाल पाटले, परमेश्वर कौशिक, संजय तिवारी, अशोक सिन्हा सहित अनेक सदस्यगण उपस्थित रहे।

नोएडा में ईडी द्वारा लिखाई गई एफआईआर भाजपा के राज्य सरकार को बदनाम करने का षडयंत्र

■ कांग्रेस सरकार को बदनाम करने ईडी साजिश रच रही

रायपुर। पिछले लगभग एक साल से भाजपा द्वारा राज्य सरकार को बदनाम करने के उद्देश्य से इनकम टैक्स तथा ई.डी. का दुरुपयोग किया जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि ईडी अपने संवैधानिक दायरों से बाहर जाकर कार्यवाही कर रही है। ईडी की कार्यवाही करने के तरीके और कार्यप्रणाली बता रही है कि वह भाजपा के राजनैतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिये तथा कांग्रेस सरकार के खिलाफ झूठ फैलाने के उद्देश्य से कार्यवाहियां की जा रही अधिकार का। ईडी अपने अधिकारों से बाहर काल्पनिक और मनगढ़त आरोपों के आधार पर कार्यवाही कर रही है। ईडी की असंवैधानिक कार्यवाही अदालत में नहीं टिकने वाली उसका उद्देश्य 2023 के विधानसभा चुनाव में सरकार की छवि खराब करना है।

शुक्ला ने कहा कि ईडी द्वारा कथित शराब घोटाला 2100 करोड़ का बताया गया। चूंकि यह आरोप कल्पना पर आधारित एवं गवाहों को विभिन्न प्रकार से प्रताड़ित करके पूर्व से ही टाइप किये गये ब्यानों पर हस्ताक्षर कराने के षड्यंत्र पर आधारित था। इसलिये अभी तक 2100 करोड़ में से ई.डी. द्वारा किसी प्रकार की अवैध संपत्ति का पता नहीं लगाया जा सका है। कुछ व्यक्तियों की वैध स्त्रोतों से अर्जित संपत्ति, वह भी 200 करोड़ से कम है, को अटैच कर 2100 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाये जाने मात्र से ही ई.डी. एवं भाजपा का षड्यंत्र प्रमाणित हो जाता है। ई.डी. द्वारा काल्पनिक शराब घोटाले में सरकार को बदनाम करने के षड्यंत्र में पूरी तरह से विफल रहने के बाद अब भाजपा के इशारे पर नोएडा पुलिस में एक गैरकानूनी एफ.आई.आर. दर्ज की गयी है। देश के इतिहास का संभवतः यह पहला अनोखा प्रकरण होगा जिसमें ई.डी. अधिकारियों द्वारा किसी पुलिस थाने में एफ.आई.आर. दर्ज करायी होगी। कानूनी प्रावधान तो यह है कि ई.डी. की कार्यवाही स्वयं किसी अन्य एजेंसी द्वारा एफ.आई.आर लिखे जाने के बाद ही आरंभ हो सकती है। फिर छत्तीसगढ़ में उल्टी गंगा क्यों बहायी जा रही है?

उन्होंने कहा कि ई.डी. की संपूर्ण जांच में यह उल्लेख नहीं है कि होलोग्राम टेंडर में अपनायी गयी पूर्णतः पारदर्शी प्रणाली में क्या कमियां थी? ई.डी. अधिकारियों द्वारा न तो शासन के किसी अधिकारी से टेंडर प्रक्रिया की जानकारी ली और न ही टेंडर कमेटी के सदस्यों से किसी प्रकार की कोई जानकारी लेने का प्रयास था। यह

इसलिये नहीं किया गया क्योंकि ई.डी. को यह जानकारी थी कि यदि होलोग्राम आपूर्ति के टेंडर की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी प्राप्त की जाती तो यह स्पष्ट हो जाता कि होलोग्राम आपूर्ति के टेंडर में पूर्ण पारदर्शिता बरती गयी थी, जिससे ई.डी. की झूठी कहानी बनती ही नहीं। होलोग्राम क्रय समिति में आबकारी विभाग के अधिकारियों के अलावा एन.आई.टी. के दो प्रोफेसर एन.आई.सी. के प्रतिनिधि एवं वित्त विभाग के अधिकारी भी शामिल थे। होलोग्राम आपूर्ति की निविदा को विभिन्न चरणों में विस्तृत परीक्षणोंपरान्त ही अंतिम रूप दिया गया था।

शुक्ला ने कहा कि ई.डी. द्वारा विशेष न्यायालय रायपुर के समक्ष प्राप्त प्रकरण में यह बताया गया है कि राज्य में अप्रैल 2019 से नकली होलोग्राम की सप्लाई तथा बिना ड्यूटी पटाये शराब की बिक्री आरंभ हुई थी। ई.डी. को इतना बड़ा झूठ बोलते समय यह भी ध्यान नहीं आया कि कथित रूप से नकली होलोग्राम सप्लाई करने वाली नोयडा की कंपनी प्रिज्म होलोग्राफी एण्ड सिक्योरिटी फिल्म प्राइवेट लिमिटेड के मालिक विधु गुप्ता द्वारा राज्य में अक्टूबर 2019 के बाद होलोग्राम सप्लाई का कार्य आरंभ किया गया था। ई.डी. की फर्जी कहानी एवं अवैधानिक रूप से एफ.आई.आर. दर्ज करने की कार्यवाही में एक अन्य गंभीर त्रुटियां यह है कि विधु गुप्ता 80 करोड़ नकली होलोग्राम डिस्टलरों को सप्लाई कर रहा है। डिस्टलर उस नकली होलोग्राम को शराब की बोतलों में लगाकर उसका विक्रय कर रहे हैं। होलोग्राम प्रदायक एवं डिस्टलरी के मालिक इस कथित अवैधानिक कार्यवाही से सर्वाधिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं किंतु यह दोनों पक्ष गवाह हैं। होलोग्राम सप्लायर तथा डिस्टलरों की कोई अचल संपत्ति अटैच नहीं की जाती, उनके बैंक खाते सील नहीं किये जाते, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाता।

इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि भाजपा के उच्च स्तरीय राजनीतिक षड्यंत्र के अंतर्गत ही उन्हें यह आश्वासन दिया गया था कि वे ई.डी. की झूठी कहानी एवं पूर्व से तैयार किये गये ब्यानों पर हस्ताक्षर करें तो उन्हें प्रकरण में गवाह बना लिया जायेगा अन्यथा उन्हें झूठे प्रकरण में फंसा कर जेल भेज दिया जायेगा। यह बात इस तथ्य से भी प्रमाणित होती है कि शराब कारोबारियों के यहां फरवरी 2020 में आयकर विभाग द्वारा मारे गये छापों के बाद आयकर अधिकारी के समक्ष हुये शपथपूर्वक ब्यानों में डिस्टलरों एवं विधु गुप्ता ने राज्य में अवैध शराब के विक्रय से स्पष्ट इंकार किया था।

उन्होंने कहा कि भाजपा में जरा भी नैतिक साहस है तो कांग्रेस के आरोपों का बिंदुवार तथ्यात्मक खंडन करें अन्यथा राज्य की जनता से माफी मांगना चाहिये। राज्य की जनता उन्हें पहले ही ठुकराने का निर्णय ले चुकी थी किंतु ई.डी. के दुरुपयोग से भाजपा के षड्यंत्र से जनता पूरी तरह वाकिफ है जिससे आगामी विधानसभा चुनाव में राज्य से भाजपा का सफाया होना निश्चित है।

भाजपा ने लांच की चुनावी घोषणापत्र से जुड़ी सुझाव पेटी

90 विधानसभा क्षेत्रों में जाएगी पेटी; वॉट्सएप पर भी लोग बताएंगे सरकार से क्या चाहिए

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र सुझाव अभियान का गुरुवार को राजधानी के एकात्म परिसर स्थित भाजपा कार्यालय में समारोहपूर्वक शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर जन-जन से उनके सुझाव प्राप्त करने के लिए सुझाव पेटिका वितरित की गई। प्रदेशवासी सीधे अपने सुझाव घोषणा पत्र समिति तक पहुंचा सके इस हेतु व्हाट्सएप नंबर 9548656500 जारी किए गए व मेल आईडी cgbjpmankibaatw®wx@gmail.com भी जारी किया गया। भाजपा कार्यकर्ता सुझाव पेटिका के साथ प्रत्येक विधानसभा स्तर के गाँव-गाँव, घर-घर जाकर सभी सामाजिक धार्मिक व्यापारिक खेल संगठनों के साथ आम जनों से मिलकर सुझाव एकत्रित करेंगे। पार्टी के बस्तर से लेकर सरगुजा तक सभी 35 जिला संगठन इकाइयों के पदाधिकारियों को प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, सह प्रभारी नितिन नवीन, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लता उसेंडी, घोषणा पत्र समिति के संयोजक विजय बघेल, छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल व मंचस्थ नेताओं ने सुझाव पेटिकाएँ सौंपी। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश प्रभारी श्री माथुर ने कहा कि चुनाव घोषणा पत्र के लिए सीधी जन भागीदारी करके सरकार को जनभावनाओं को अनुरूप संचालित करना भारतीय जनता पार्टी

का अपना अभिनव राजनीतिक चिंतन है और भाजपा सन 2003 से इसी प्रकार अपने घोषणा पत्र की रचना करती आ रही है। श्री माथुर ने कहा कि घोषणा पत्र को जनभावनाओं के अनुरूप, छत्तीसगढ़वासियों के मन की बात के अनुरूप बनाने के लिए प्रदेश भाजपा की घोषणा पत्र समिति के मार्गदर्शन में सभी जिलों और विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ता जनता के बीच जाएंगे। भाजपा कार्यकर्ता समाज जीवन के हर वर्ग तक सुझाव संग्रह करने पहुँचें और समाज को यह संदेश दें संसाधन-सम्पन्न छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आपकी इच्छा और आपके मन की बात के अनुरूप काम करने वाली होगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ के दुःख-दर्द को, छत्तीसगढ़वासियों की तकलीफ को महसूस करते हुए हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटलजी ने छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया। एक माँ अपने बच्चे का जिस प्रकार पालन-पोषण करती है, उसी भाव से अनुप्राणित होकर भाजपा ने अपने 15 वर्षों के शासनकाल में छत्तीसगढ़ को सजाने-सँवारने का काम किया है। लेकिन पौने पाँच साल में कांग्रेस की प्रदेश सरकार ने छत्तीसगढ़ को बदहाल कर दिया। श्री साव ने प्रदेशवासियों से भी अपील की कि वे भाजपा के घोषणा पत्र की रचना में उत्साहपूर्वक भागीदार बनकर अपने बहुमूल्य सुझाव दें। प्रदेशवासियों के सुझाव के अनुरूप घोषणा पत्र की रचना करके भाजपा सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ को समृद्ध व खुशहाल प्रदेश बनाने के लिए योजनाएँ व कार्यक्रम तय किए जाएंगे। इससे पूर्व अपने भाषण में घोषणा पत्र समिति के संयोजक व सांसद विजय बघेल ने कहा कि आज का यह दिन आगामी चुनाव में इतिहास गढ़ने वाला सिद्ध होगा। भाजपा सबके साथ विकाम करके उनकी भावनाओं के अनुरूप घोषणा पत्र बनाएगी। सर्वप्रथम श्री विजय बघेल ने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया जगत से कांग्रेस शासनकाल में उनके साथ हुई प्रताड़ना का जिक्र कर अपने बहुमूल्य सुझाव देने की अपील की। किसानों के प्रति कांग्रेस के दुराग्रहपूर्ण रवैए की चर्चा करते हुए श्री विजय बघेल ने कहा कि किसान भुइयाँ का भगवान है और भाजपा इसे अपने अंतर्मन से स्वीकार करती है। किसानों के उत्थान के लिए भाजपा शुरू से ही काम करती आ रही है। भाजपा की सरकार ने शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण सहित धान खरीदी की मॉडल व्यवस्था लागू की, जिसका दुनिया में कोई सानी नहीं है। श्री बघेल ने कहा कि किसानों के नाम पर सियासी जुमलेबाजी करने वाली प्रदेश सरकार किसानों को जितना नहीं दे रही है, केंद्र की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार प्रदेश के किसानों उससे चार गुना ज्यादा दे रही है। समय इस पर चर्चा करके उसे किसानों तक पहुँचाने का है। भाजपा आगे भी किसानों के सुझावों के अनुरूप उनके सपने साकार करेगी। श्री बघेल ने कहा कि कांग्रेस के झूठ और वादाखिलाफी से प्रदेश का हर वर्ग त्रस्त है और अपने हक व इंसाफ के लिए उन्हें सड़क पर उतरना पड़ रहा है। श्री बघेल ने कांग्रेस शासनकाल में पत्रकारों की हुई प्रताड़ना का जिक्र कर उनसे भी अपने बहुमूल्य सुझाव देने की अपील की। छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री चंदेल ने कहा कि घोषणा पत्र राजनीतिक दल के संकल्पों का दस्तावेज होता है, राजनीतिक दल के दृष्टिकोण का दर्पण होता है। भाजपा के विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में जनता से प्राप्त सुझावों को समायोजित किया जाएगा और हमारी सरकार उन घोषणाओं पर काम करेगी। भाजपा की नवनियुक्त राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुश्री उसेंडी ने कहा कि छत्तीसगढ़वासियों के मन की बात को घोषणा पत्र में शामिल कर छत्तीसगढ़ को तेज गति से विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए भाजपा घोषणा पत्र तैयार करेगी और हमें प्रदेश की जनता अपना आशीर्वाद देगी। घोषणा पत्र सुझाव अभियान के शुभारंभ के अवसर पर प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी, प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल, विधायक व पूर्व मंत्री द्वय बृजमोहन अग्रवाल व पुन्नूलाल मोहिले, पूर्व मंत्रीगण महेश गागड़ा, प्रेमप्रकाश पांडेय, डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी व अमर अग्रवाल, पूर्व सांसद रामविचार नेताम, सहित बड़ी संख्या में पार्टी के प्रदेश व जिला पदाधिकारी, नेता व कार्यकर्ता उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन प्रदेश महामंत्री विजय शर्मा और आभार प्रदर्शन पूर्व सांसद श्री नेताम ने किया।

अहंकार के पथ पर चलकर क्रुर हो गई हैं कांग्रेस सरकार : कौशिक

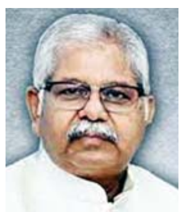

रायपुर। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धरमलाल कौशिक ने मानदेय में वृद्धि करने की मांग को लेकर जूनियर डॉक्टरों द्वारा किये जा रहे अनिश्चितकालीन हड़ताल का समर्थन करते हुए प्रदेश सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि जूनियर डॉक्टर की हड़ताल करना वाजिब है क्योंकि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने अपने किए वादों के अनुसार अभी तक उनकी मांगो को पुरा नहीं कर पाई है विभिन्न कर्मचारी संगठनों की हड़ताल में चले जाने से प्रदेश की जनता को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है किन्तु कांग्रेस सरकार इनके मांगो को पुरा करना छोड़ अपने सारे वादों से मुकर रही है और इन पर दमनकारी नीति चला रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार जिन घोषणा पत्र एवं झूठे वादों को लेकर सत्ता में आई थी आज उन्हीं बातों से मुकर चुकी है। कांग्रेस ने अपने जन घोषणापत्र में कहा था कि सभी अनियमित-संविदा कर्मचारी साथियों को कांग्रेस की सरकार बनने के 10 दिनों के भीतर सबका नियमितीकरण कर दिया जाएगा। लेकिन पौनें पांच साल गुजर जाने के बाद भी वादा पुरा नहीं कर पाई है और वादों को पुरा करने के बजाय अपनी मांगो को लेकर हड़ताल कर रहे संविदा कर्मचारियों एवं स्वास्थ्य कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त कर रही है। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि क्या कर्मचारी संगठनों को अपना हक मांगना गुनाह है? ये कांग्रेस को उनका वादा याद दिला रहे हैं, किंतु सरकार ने इन बेकसूर युवाओं को बर्बरतापूर्वक एस्मा जैसे नियम लगाकर उन पर तानाशाही करके उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर रही है। कांग्रेस की सरकार अहंकार के रास्ते पर चलकर क्रूर हो गयी है। झुठ की बुनियादी पर खड़ी कांग्रेस सरकार के कारण एक संविदा कर्मचारी हड़ताल करते वक्त शहिद हो गए यह कोई दुर्घटना नहीं बल्कि कांग्रेस सरकार की संविदार्मिकयों के विरूद्ध अमानवता, अंसवेदनशीलता और धोखाधड़ी के हाथों हुई एक हत्या है किंतु कांग्रेस के सरकार एवं उनके मुखिया भूपेश बघेल यह जान लें कि अब उनके झूठ का पर्दाफाश हो चुका है और अब प्रदेश के लाखों कर्मचारीगण और छत्तीसगढ़ के करोड़ो आमजन शहिद संविदाकर्मी का बलिदान व्यर्थ नहीं जाने देंगे और आगामी विधानसभा चुनाव में प्रदेश के संविदा कर्मचारी एवं प्रदेश कि जनता तैयार है इस सरकार को सत्ता से उखाड़ फेकने के लिए।

डॉ रमन सिंह अस्पताल में भर्ती, दिल्ली एम्स में भर्ती

रायपुर। पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह की तबीयत ठीक नहीं हैं। इलाज के सिलसिले में वो दिल्ली में हैं। गुरुवार को उन्हें एम्स में भर्ती किया गया। इसकी जानकारी खुद देते डॉ रमन ने ट्वीट किया उन्होंने जानकारी दी - पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में हूँ, आज रूटीन चेकअप के लिए,ड्ढद्बद्वह्य जाना हुआ जहाँ चिकित्सकों के परामर्श से एहतियात के तौर पर भर्ती हुआ हूँ। फ़िलहाल स्वास्थ्य ठीक है, मानसून के बीच आप सब भी बारिश में पूरी एहतियात बरतें और स्वस्थ रहें।

प्रदेश में बारिश का कहर, खतरे का अलर्ट

रायपुर। प्रदेश में इन दिनों लगातार बारिश हो रही है. भारी बारिश से प्रदेश के कई जिलों में नदी-नाले खतरे के निशान से ऊपर बह रहे हैं. ऐसे में भारी बारिश के कारण गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है. जिसके बाद जिले में 2 दिन का अवकाश घोषित कर दिया गया है.

जिले में पिछले 48 घण्टों से लगातार बारिश हो रही है. मौसम विज्ञान केंद्र ने भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया था. जिसके बाद जिला प्रशासन ने कई जगह जलभराव और बारिश को देखते हुए 4 और 5 अगस्त को अवकाश घोषित किया है. जारी आदेश के अनुसार, प्रमायरी क्लास से लेकर क्लास 12वीं तक के लिए छुट्टी का आदेश जारी किया है.

कलेक्टर प्रिंयका महोबिया द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि, जिले में अत्यधिक वर्षा जलभराव की स्थिति को देखते हुए और मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए अलर्ट के कारण विद्यार्थियों की सुरक्षा के कारण प्री प्राइमरी कक्षा से लेकर कक्षा बारहवीं तक संचालित सभी शासकीय, अशासकीय, अनुदान प्राप्त विद्यालयों को 4 एवं 5 अगस्त तक अवकाश घोषित किया गया है. वहीं स्थानीय पेंड्रारोड मौसम विज्ञान केंद्र से प्राप्त जानकारी के अनुसार 2 अगस्त से लेकर गुरुवार शाम 5ः30 बजे तक 156.8 मिलीमीटर रिकॉर्ड बारिश दर्ज की गई है. इसके साथ ही स्थानीय मौसम विभाग ने 5 तारीख तक येलो अलर्ट जारी किया है. जिले में कई जगह बारिश के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन होने की खबरें भी आ रही हैं. सुबह गौरेला अमरकंटक मार्ग में केंवची और कबीर के बीच में पहाड़ भसकने से यह मार्ग अवरुद्ध हो गया था, जिसे दोपहर बाद नेशनल हाइवे विभाग के द्वारा दुरुस्त कर यातायात के लिए खोला गया. अभी भी कई जगह पहाड़ी क्षेत्रों से पेड़ों के गिरने और भूस्खलन की खबरें आ रही हैं. इसके साथ ही पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बारिश के चलते कई नदी और नाले उफान पर हैं जिन का जलस्तर काफी बढ़ चुका है.बारिश के कारण जिले जान माल का भी नुकसान देखने को मिला है, दो मासूम बच्चों की मौत हुई है. पहली घटना में पेंड्रा के बाजार पारा में बाजार शेड का छज्जा गिरने से एक मासूम बच्चे की मौत हुई है, तो वहीं दूसरी घटना में पेंड्रा के ही नवागांव में एक मासूम बच्ची की दीवार गिरने से दबकर मौत हो गई है. जिसकी जांच पुलिस कर रही है. वहीं दूसरी तरफ मरवाही के 2 गांव में बिजली का तार टूट कर गिर जाने से करंट की चपेट में आने से 3 मवेशियों की मौत हुई है।

छत्तीसगढ़/राजधानी
प्रमुख समाचार

सुझाव पेटी जनता के सुझाव कम सवाल ज्यादा मिलेंगे: बैज

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी को घोषणा पत्र के बजाये प्रायश्चित पत्र बनाना चाहिये। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि 15 साल जनता को धोखा देने वाली भाजपा किस नैतिकता से घोषणा पत्र बनायेगी। भाजपा को इस बात का प्रायश्चित करना चाहिये जनता ने उन्हें तीन बार घोषणा पत्र बनाने का मौका दिया था उस घोषणा पत्र के वायदो को पूरा करने के लिये तीन बार सरकार चलाने का अवसर दिया था लेकिन भाजपा वायदा करके वो मुकर गयी। 2003 के घोषणा पत्र में वायदा किया था कि हर आदिवासी परिवार को गाय देने का, हर आदिवासी परिवार से एक को सरकारी नौकरी देने का, युवाओं को 500 रू. बरोजगारी भत्ता देने का, 2008 में वायदा किया किसानों को धान का 300 रू. बोनस देने का, 2013 में वायदा किया था धान की कीमत 2100 रू. देंगे और 300 रू. बोनस कुल 2400 रू. प्रति क्विंटल धान खरीदी करने का कोई भी वायदा पूरा नहीं किया। एक बार फिर से जनता को ठगने के लिये घोषणा पत्र बनाने जनता के बीच जाने की बात कर रहे है। अब जनता उनके घोषणा पत्र में क्यों भरोसा करेगी? हमने अपने घोषणा पत्र के वायदों को पूरा किया हमारे 36 में से 34 वायदें पूरा हुये। सरकार बनने के पहले घंटे से लेकर आज दिनांक तक मुख्यमंत्री अपने वायदा को पूरा कर रहे है। छत्तीसगढ़ में सरकार में रहते 15 साल वादाखिलाफी करने वाले भाजपाई किस नैतिकता से नये वादो की बात कर रहे है।

आवास मांग रहे हैं तो भाजपा के पेट में दर्द क्यों हो रहा है?: ठाकुर

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर 8 लाख से अधिक गरीबों को मकान देने की मांग कर रहे तो भाजपा के पेट मे दर्द क्यो हो रहा है? भाजपा के 9 सांसदों ने पीएम आवास के शेष हितग्राहियों को आवास दिलाने में रुचि क्यो नही दिखाई? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार में पौने 5 साल में ग्रामीण एवं शहरी मिलाकर 14 लाख 38 हजार 823 मकान स्वीकृत हुये जबकि रमन सरकार के दौरान पौने चार साल में ग्रामीण एवं शहरी मिलाकर मात्र 2 लाख 37 हजार मकान स्वीकृत हुआ था। प्रतिवर्ष के अनुसार देखा जाए तो भूपेश सरकार के पौने 5 साल में प्रति वर्ष 2 लाख 80 हजार मकान बने जबकि रमन सरकार के पौने चार साल में प्रति वर्ष मात्र 59 हजार मकान ही बने थे। भूपेश सरकार ने गरीबो के मकान बनाने अब ग्रामीण एवं शहरी मिलाकर 8489 करोड़ रुपया से अधिक की राशि जा रही कर चुके है। जबकि रमन सरकार के पौने चार साल में मात्र 272 करोड़ राज्यांश दिया गया था।प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा बताये जब प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत हुई तब भारत सरकार के सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 के अनुसार 1875585 ग्रामीण हितग्राही थे लेकिन उस दौरान रमन सरकार ने मात्र 2 लाख 18 हजार ग्रामीण मकान स्वीकृत क्यो किया? प्रदेश के 16 लाख 57 हजार 585 गरीबों को पीएम ग्रामीण आवास योजना से वंचित क्यो रखा? भूपेश सरकार में 1176146 ग्रामीण हितग्रहियों का आवास का सपना पूरा हुआ।

राज्यपाल ने अत्याधुनिक ब्लड सेंटर का शिलान्यास किया

रायपुर। राज्यपाल एवं छत्तीसगढ़ रेडक्रॉस के अध्यक्ष श्री विश्वभूषण हरिचंदन ने आज भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी छत्तीसगढ़ राज्य शाखा रायपुर द्वारा सिविल लाइन रायपुर में बनाए जा रहे अत्याधुनिक ब्लड सेंटर का शिलान्यास किया। इस ब्लड बैंक में अत्याधुनिक मशीन के माध्यम से जांच कर रक्त का संग्रहण किया जायेगा, ताकि जरूरत मंद मरीजों को सुरक्षित रक्त उपलब्ध कराया जा सके। इस अवसर पर राज्यपाल श्री हरिचंदन ने संक्षिप्त उद्बोधन में कहा कि मानव सेवा ही माधव सेवा है, इस उद्देश्य के साथ भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी द्वारा सतत् मानव सेवा का कार्य किया जा रहा है। इस अत्याधुनिक ब्लड सेंटर के निर्माण से आमजनता को बहुत लाभ होगा। उन्होंने निर्माणाधीन बल्ड सेंटर परिसर में वृक्षारोपण कर हरियाली का संदेश दिया है। इस अवसर छत्तीसगढ़ रेडक्रॉस सोसायटी के जनरल सेक्रेटरी श्री एम. के. राउत, चेयर मेन श्री अशोक अग्रवाल, सचिव डॉ. आर. पुरोहित, रेडक्रॉस के अन्य सदस्य तथा रक्तदाता उपस्थित थे।

भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हो रही है तो कांग्रेस क्यों परेशान है: गुप्ता

रायपुर। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता केदार गुप्ता ने कहा कि जब भ्रष्ट अधिकारियों व कुछ लोगों पर ईडी एवं आईटी के छापे की कार्यवाही हो रही तो कांग्रेस क्यों परेशान है। कांग्रेस का हाथ क्या भ्रष्टाचारियों के साथ है इस पर कांग्रेस को अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए। उन्होंने कहा कि शराब घोटाला, कोयला घोटाला और ऐसे दर्जनों घोटालों में कांग्रेस पूरी तरह डूबी हुई है। साक्ष्यों के साथ मामले अदालत में पेश किए जा रहे है। माननीय न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों को जेल भेज रही है संलिप्त अधिकारियों पर कार्रवाई हो रही है। यह दिन के उजाले की तरह साफ है। कांग्रेस का एक तबका भी इस तरह के घोटाले होने को स्वीकार कर रहा है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्री गुप्ता ने कहा कि जब अधिकारियों एवं व्यवसायियों के बीच बातचीत के ऑडियो एजेंसियों ने माननीय न्यायालय में पेश किए है। इसके अलावा हजारों दस्तावेजी सबूत ईडी और आईटी ने रायपुर दिल्ली और भोपाल में दर्ज मामलों में पेश किए हैं। इन दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों से यह दिन के उजाले की तरह साफ है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनने के बाद से किस तरह से सुनियोजित और संगठित लूट के लिए माफिया और सरकारी अधिकारियों के बीच गठजोड़ बन गया था। इस अपवित्र गठजोड़ के पीछे कांग्रेस सरकार के सर्व शक्तिमान चेहरों की संलिप्तता को लेकर भी दोनों एजेंसियों ने न्यायालय में अकाट्य सबूत पेश किए हैं। ईडी ने माननीय उच्चतम न्यायालय और रायपुर के विशेष न्यायालय में अलग-अलग हलफनामों में बार-बार इंगित किया है।

विकास कार्यों को तय समय पर पूर्ण कराएं : लखमा

रायपुर। उद्योग मंत्री श्री कवासी लखमा ने आज नारायणपुर कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में विभागीय कार्य एवं योजनाओं की समीक्षा बैठक लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि फ्लैगशिप योजनाओं सहित अन्य जनहित के निर्माण गतिविधियों को जनप्रतिनिधि तथा विभागीय अधिकारी आपसी समन्वय के साथ निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कराएं, ताकि स्थानीय स्तर पर ग्रामीणों को उसका लाभ मिल सके। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ एवं उपयोगी बनाने के लिए हमने रीपा प्रारंभ किया। इस महत्वपूर्ण योजना के क्रियान्वयन से युवा एवं महिलाओं को स्वरोजगार से बड़ी संख्या में जोड़ा जा सकेगा। मंत्री श्री लखमा ने स्कूल, आश्रम और आंगनबाड़ी भवन निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिये, ताकि इसका लाभ स्थानीय लोगों को मिल सके। समीक्षा बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं की गहन समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराएं, जिससे आम जनता को शुद्ध पेयजल मिल सके। उन्होंने मुख्यमंत्री की मंशानुरूप जिले में स्वामी आत्मानंद स्कूल, आश्रम छात्रावास, आंगनबाड़ी और स्कूल भवनों का सौंदर्यीकरण करने अधिकारियों को निर्देशित किया। बैठक में विभागीय अधिकारियों द्वारा मनरेगा योजना, गोबर क्रय निर्मित खाद की विक्रय, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वामी आत्मानंद स्कूल की प्रगति, सामुदायिक वन अधिकार पत्र और सड़क मार्ग निर्माण की प्रगति से प्रभारी मंत्री को अवगत कराया गया।

प्रधानमंत्री मुद्रा लोन मेला में हितग्राहियों ने लिया लाभ: अमर

■ कैट के प्रदेश कार्यालय में प्रधानमंत्री मुद्रा लोन मेला का आयोजन हुआ

रायपुर। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमर पारवानी, चेयरमेन मगेलाल मालू, अमर गिदवानी, प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र दोशी, कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम सिंहदेव, परमानन्द जैन, वाशु माखीजा, महामंत्री सुरिन्द्रर सिंह, कार्यकारी महामंत्री भरत जैन, एवं कोषाध्यक्ष अजय अग्रवाल ने बताया कि आज कैट के प्रदेश कार्यालय में शाम साढ़े तीन बजे से शाम 6 बजे तक प्रधानमंत्री मुद्रा लोन मेला का आयोजन किया गया। मुद्रा लोन मेले में व्यपारियों एवं हितग्राहियों को प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना का लाभ देने कैट के टेक्नीकल टीम के साथ ही विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंक भी शामिल हुए। मुद्रा लोन मेले में व्यापारियों को इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों के बारे में विस्तार से बताया गया.कैट के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री अमर पारवानी एवं प्रदेश अध्यक्ष श्री जितेन्द्र दोशी ने बताया कि आज कैट के प्रदेश कार्यालय में प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के अंतर्गत लोन मेले का आयोजन किया गया। जिसमें विभिन्न व्यापारिक संगठनो के प्रमुखों सहित व्यापारीगण शामिल हुए और इस योजना के बारे में हितग्राहियों ने विस्तार से जाना तथा लाभ उठाया । इस योजना के तहत 50 हजार से 10 लाख तक लोन, बिना गारंटी (पात्रता अनुरूप), आकर्षक ब्याज दर एवं अन्य लोन सम्बन्धी समस्याओं का समाधान किया जाना इत्यादि शामिल हैं। लोन मेले में राष्ट्रीयकृत बैंकों में बैंक ऑफ बडौदा, यूनियन बैंक, इण्डियन ओवरसीज बैंक आईडीबीआई बैंक, आरबीएल बैंक ने अपने स्टॉल लगाये तथा लगभग 100 लाभार्थी पहुंचे। कई हितग्राहियों के लोन तत्काल स्वीकृत हुए।

श्री पारवानी एवं श्री दोशी ने आगे बताया कि प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना से पूरे प्रदेश के व्यापारियों को इसका लाभ मिल सके इसके लिए कैट द्वारा टेक्नीकल टीम बनाया गया है।

त्योहारों के सहारे महिला वोटरों को साधेगी भाजपा महिलाओं संग मनाएंगे सावन उत्सव, रक्षाबंधन

रायपुर। अगले विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए भाजपा ने त्योहारों के सहारे महिला मतदाताओं तक पहुंचने का निर्णय लिया है। प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा 31 अगस्त तक सावन उत्सव और रक्षाबंधन का उत्सव महिलाओं के साथ मनाएंगी। इसके लिए पार्टी कई खास कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है।

भाजपा का मानना है कि विधानसभा की चुनाव में बंपर जीत यानि मिशन 2023 के लिए महिलाओं के बीच गहरी पैठ सबसे अधिक जरूरी है। मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत ने बताया कि केंद्र सरकार की 15 बड़ी योजनाओं को लेकर महिलाओं के बीच मोर्चा लगातार पहुंच रहा है। इनमें बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, अभियान से लेकर महिला शक्ति केंद्र योजना, सक्षम योजना, स्वावलंबन योजनाओं से महिलाओं को जोड़ा जा रहा है।महिला मोर्चा ने राज्य स्तर पर शराबबंदी को लेकर आंदोलन करने के बाद अब जिलों में आंदोलन करने का निर्णय लिया है। अगस्त में कई आंदोलन होंगे। इसके बाद सितंबर में महिलाओं से संपर्क साधने के लिए संपर्क अभियान चलाया जाएगा।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.